चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

12 अगस्त–18 अगस्त 2013

आज़ादी की दूसरी लड़ाई

अन्ना हज़ारे

जिस आज़ादी का जश्न हम स्वतंत्रता दिवस के दिन मना रहे हैं, वह बस शब्दों तक सीमित होकर रह गई है. उसके मायने कहीं खो गए हैं. अगर हम इसकी वज़ह तलाशें, तो राजनीतिक दल ही इसके लिए सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं. राजनीतिक दलों ने संविधान का माख़ौल उड़ाते हुए अपने हिसाब से संविधान की व्याख्याओं को स्थापित किया और जनतंत्र के बजाय पार्टीतंत्र को तरज़ीह दी. आज हम स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि पार्टीतंत्र की गिरफ़्त में हैं. इस दौर से बाहर निकलकर ही स्वतंत्रता की वास्तविकता का अनुभव किया जा सकता है. इसीलिए अब दूसरी आज़ादी का संघर्ष जरूरी हो गया है.

अन्ना हज़ारे

आज़ादी की लड़ाई 1857 में ही शुरू हो गई थी. 1857 से लेकर 1947 तक लाखों लोगों ने अपनी जान की क़ुर्बानी दी. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे कई देशभक्त हंसते-हंसते देश के लिए क़ुर्बान हो गए. देशवासियों ने एक लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों पर विजय पाई और अंग्रेज इस देश से चले गए. एक लंबे अर्से के बाद देश 15 अगस्त, 1947 को ग़ुलामी की बेड़ियों से निकला और स्वतंत्रता के जश्न में डूब गया. कितना उत्साह था लोगों में. सबके चेहरों पर ख़ुशी की चमक थी. हर घर में रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया, वह रोशनी फीकी पड़ती गई और उस रोशनी के साथ-साथ स्वतंत्रता का उत्साह भी आज लोगों के चेहरे से ग़ायब-सा हो गया है. आज हम स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के मायने ख़त्म हो गए हैं. सही मायनों में हम आज़ादी अभी तक केवल इस बात की मना रहे हैं कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए. वास्तविक स्वतंत्रता अभी भी हमसे दूर है, इसीलिए देशवासी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन अनमने ढंग से.

ऐसा क्यों हुआ, हमें पहले यह समझने की ज़रूरत है. अंग्रेजों से मुक्ति के बाद देश का संविधान बना, लेकिन मुश्किल तब शुरू हुई, जब राजनीतिक दलों ने संविधान की खिल्ली उड़ाते हुए अपने हिसाब से संविधान की सभी व्याख्याओं को स्थापित कर लिया. संविधान में कहा गया है कि लोकतांत्रिक गणराज्य में जनता जिसे योग्य समझे, उसे अपना उम्मीदवार चुनकर संसद में भेजे, लेकिन जब 1952 में देश का पहला चुनाव हुआ, तो पार्टी के आधार पर चुनाव हुआ, जबकि संविधान में राजनीतिक दलों का कहीं उल्लेख ही नहीं है. तभी संविधान की व्याख्या के अनुसार, न चलने पर देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को बर्ख़ास्त होना चाहिए था, क्योंकि जब लोकतंत्र आ गया, तो पक्ष और पार्टी की भूमिका का क्या मतलब? महात्मा गांधी जी ने भी कांग्रेस पार्टी से कहा था कि अब लोकतंत्र आ गया है, इसलिए पक्ष और पार्टियों को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हुआ इसके उल्टा और 1952 का चुनाव तो पार्टियों के तहत ही लड़ा गया और चुनाव लड़कर पक्ष और पार्टियों ने अपने लोग संसद में भेजे, जनता के लोग नहीं गए.

हम कहते हैं लोकसभा. लोकसभा का मतलब है लोगों के भेजे हुए प्रतिनिधियों की सभा, लेकिन कहां है लोकसभा? वह तो मात्र पार्टियों की सभा बनकर रह गई है. गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई. जनतंत्र पर इन पार्टियों ने अतिक्रमण किया और लोकतंत्र के अर्थ को ही ख़त्म कर दिया.

महात्मा गांधी कहते थे कि देश को बदलना है, तो पहले गांवों को बदलना होगा, लेकिन इन पार्टियों ने गांवों में विकास को दरकिनार कर अपने हितों को स्थापित किया. लोग संगठित होकर इन पार्टियों के ख़िलाफ़ न खड़े हो जाएं, इसलिए उन्होंने ग्रामीण जनता को जात-पात के नाम पर भ्रमित कर सिस्टम से बाहर बनाए रखा.

महात्मा गांधी कहते थे कि देश को बदलना है, तो पहले गांवों को बदलना होगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने गांवों में विकास को दरकिनार कर अपने हितों को स्थापित किया. संगठित होकर लोग इन पार्टियों के ख़िलाफ़ न खड़े हो जाएं, इसलिए उन्होंने ग्रामीण जनता को जात-पात के नाम पर भ्रमित कर सिस्टम से बाहर बनाए रखा.

लोकतंत्र का अर्थ है वह तंत्र, जो लोगों द्वारा बुना गया हो. अब चूंकि इसमें जनता की भूमिका ही नहीं है, इसलिए यह लोकतंत्र नहीं है, पार्टी तंत्र है. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, पार्टी तंत्र की गिरफ्त में हैं.

जनतंत्र का वास्तविक मतलब है जन-सहभागिता से चलाया जा रहा तंत्र. असली मालिक तो जनता है. जिन्हें चुनकर भेजा गया है, वे तो जनता के सेवक हैं. जो अधिकारी चुने जाते हैं, वे भी लोकसेवा के लिए चुने जाते हैं. इसलिए वे भी लोकसेवक हैं, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है. मालिक सेवक बन गया है और सेवक मालिक. अगर व्यवस्था विपरीत चल रही है, फिर स्वतंत्रता कैसी? स्वतंत्रता के नाम पर क्या बस यही समझा जाए कि अंग्रेज चले गए? स्थितियां तो जस की तस बनी हुई हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि लाखों लोगों की क़ुर्बानी और आज़ादी की राह में वर्षों का संघर्ष क्यों व्यर्थ हो गया? आइए, शपथ लें कि अपने शहीदों का बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे.

अगर प्रजातंत्र लाना है, तो जनता को अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी. हर एक मतदाता को जागरूक होकर यह तय करना होगा कि वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देने की प्रतिज्ञा लें. जनता अपना उम्मीदवार खुद खड़ा करेगी, उसमें पार्टी की कोई भूमिका नहीं होगी. जनता चरित्रवान लोगों का चुनाव करेगी और उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाएगी. ऐसे में पार्टी तंत्र, जो कि दरअसल भ्रष्ट-तंत्र है, अपने आप नेस्तनाबूत हो जाएगा.

इन सबके बीच यह सवाल खड़ा होना लाज़िमी है कि क्या राजनीतिक दल, जनता में यह विश्वास पैदा होने देंगे कि वे अपना उम्मीदवार खड़ा करें और क्या देश की जनता में इतना भरोसा आ गया है कि वह अपना उम्मीदवार ख़ुद खड़ा कर सके. इस सवाल की सबसे बड़ी वज़ह है धनबल और बाहुबल का राजनीति पर हावी होना. इन धन पशुओं के सामने जनता का उम्मीदवार कैसे टिक पाएगा. यह चिंता जायज़ है, लेकिन देश का इतिहास गवाह है कि इसी जनता ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है और एक बार फिर जनता इसे आज़ादी की दूसरी लड़ाई समझकर यह तय कर ले कि हम रिश्वत लेकर वोट नहीं देंगे.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

लोकतंत्र का अर्थ है वह तंत्र, जो लोगों द्वारा बुना गया हो. अब चूंकि इसमें जनता की भूमिका ही नहीं है, इसलिए यह लोकतंत्र नहीं है, पार्टीतंत्र है. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, पार्टीतंत्र की गिरफ्त में हैं.

जल्द हो सकता है लोकसभा चुनाव 02

साइबर खिड़की के पीछे खड़ा मतदाता 04

हिंदुओं और बौद्धों में टकराव 05

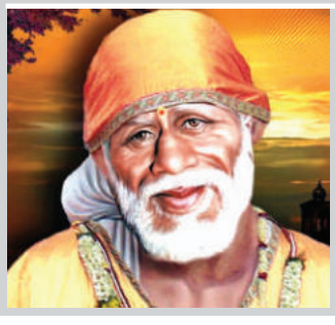

साई की महिमा 12

आज़ादी की दूसरी लड़ाई : अन्ना हज़ारे

हमें यह भी समझना होगा कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है. हालांकि राजनीतिक पार्टियां, युवाओं को भी अपने पक्ष में लाने के लिए इनके बीच दलगत राजनीति का बीज बो रही हैं, लेकिन आपने देखा कि देश का युवा अब भ्रष्टाचार के ख़िलाफ जाग गया है. समूचे देश को इसी तरह जागना होगा.

पृष्ठ एक का शेष

दाग़ियों को वोट नहीं देंगे. अपने खड़े किए हुए उम्मीदवारों को चुनेंगे. जनता की प्रतिबद्धता के सामने बड़ी-बड़ी मुश्किलें हल हुई हैं, यह भी हल होगी.

हमें यह भी समझना होगा कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है. हालांकि राजनीतिक पार्टियां, युवाओं को भी अपने पक्ष में लाने के लिए इनके बीच दलगत राजनीति का बीज बो रही हैं, लेकिन आपने देखा कि देश का युवा अब भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जाग गया है. समूचे देश को इसी तरह जागना होगा. इस मानसिक परिवर्तन में समय लगेगा, लेकिन जितनी जल्दी लोग इस अवस्था से बाहर निकल कर, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बाहर आएंगे, उतना ही जल्दी देश सही मायनों में स्वतंत्र होगा.

आज़ादी की दूसरी लड़ाई को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि जनता पहले राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार का ख़ात्मा करे. इसके लिए जनता अपने बीच से निष्ठावान, चरित्रवान व सच्चे उम्मीदवार का चयन करे. ऐसे जनता उम्मीदवारों के साथ मेरा समर्थन रहेगा. उनके लिए मैं देश भर में भ्रमण करूंगा. मैं ऐसे लोगों के पक्ष में रहूंगा और जनता के सहयोग से जब ऐसे लोग जीत कर आएंगे, तभी सही मायने में लोकतंत्र की अवधारणा को अर्थ मिलेगा.

जनता इन सभी परिस्थितियों को समझती है. मैं मानता हूं कि देश में संवेदनशील लोगों की कमी नहीं है, लेकिन इस संवेदनशील जनता को राजनेताओं ने हमेशा धोखा दिया है. देश के प्रधानमंत्री बार-बार कहते हैं कि हम जनलोकपाल लाएंगे, लेकिन यह अभी तक हक़ीक़त में तब्दील नहीं हो पाया है. सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है और मैं इसी धोखे को इस संवदेनशील जनता के सामने लाना चाहता हूं और इसका माध्यम मैं आत्मक्लेश समझता हूं. गांधी जी ने अहिंसा और आत्मक्लेश के मार्ग की बात की थी. इस लिए भी और देश की दूसरी आज़ादी की आवाज़ को बल देने के लिए मैं संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के पहले दिन से आत्मक्लेश-आत्मशुद्धि के लिए उपवास करने जा रहा हूं. मुझे यक़ीन है कि इसकी संवेदना जनता तक पहुंचेगी. मुझे यह भी विश्वास है कि 16 अगस्त, 2011 के दौर में जिस तरह जनता जन लोकपाल के समर्थन में सड़कों पर उतर आई थी, उससे कहीं बड़ी संख्या में इस बार लोग भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हाथ से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि उन्हें न केवल छला गया है, बल्कि स्थितियों को और भी बदतर बना दिया गया है.

इन्हीं बदतर स्थितियों ने देश की जनता के बीच से कई हाथों में बंदूकें थमा दी हैं. यह देश तो गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाला देश था, लेकिन यह सरकार की नाक़ामी है कि जो हाथ साकार के लिए उठते थे, वह प्रतिकार के लिए उठ रहे हैं. और सरकार का यह तानाशाही रवैया तो देखिए, वह उन हाथों में विकास की डोर देने के बजाए उनका दमन कर रही है. सरकार ग़लतफ़हमी में है कि वह मालिक है. इस देश में प्रजा सत्ता है और जिस दिन सत्ता में बैठे लोगों की समझ में यह बात आ जाएगी, उसी दिन समाज में व्याप्त सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी.

राजनीतिक दल जनता में भरोसा नहीं करते. वे जनता को केवल वोट बैंक में बदलने के लिए धर्म-जाति व अन्य आधारों पर बांट रहे हैं. मेरा संघर्ष यह है कि राजनीतिक पार्टियां जनता का इस्तेमाल अपने छुद्र स्वार्थों के लिए न करें. इसीलिए मैं बार-बार जनता की सहभागिता की बात कर रहा हूं. जनता के दिल में जाति-पंथ जैसा कोई विभेद नहीं है. नेता के दिमाग़ में लोकसेवा के बजाए वोट बैठ गया है. देश की जनता इन विचारों से ऊपर है, बस उनमें समन्वय बनाए रखना होगा. मेरी कोशिश भी इसी समन्वय को बनाए रखने की है. हो सकता है कि इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मैं इसे जनता के साथ चलकर हर क़दम मंज़िल को हासिल करने के लिए बढ़ाऊंगा.

मेरी दूसरी आज़ादी की लड़ाई को लेकर एक सवाल यह खड़ा हो सकता है कि जब पहली आज़ादी की लड़ाई के बाद देश के कर्णधार ग़लत रास्तों पर चलने लगें, तो अब जनता जिन लोगों को चुनकर भेजेगी, क्या वे निष्ठावान बने रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी है. मेरा जवाब है कि जनता के जो उम्मीदवार चुन के जाएंगे, वह राइट टु रीकॉल की सीमा में बंधे रहेंगे. अगर वो जनता के हित में नहीं रहेंगे, तो जनता उन्हें वापस बुलाकर सबक सिखाएगी. जनता के हाथ और उसकी सोच दोनों मज़बूत हैं. इसलिए जब वह अपने ही भीतर से, अपने पैमानों के आधार पर लोगों को चुनेगी, तो निश्चित रूप से चुने गए वे लोग, देश और समाज के बारे में सोचने वाले लोग होंगे.

जनता को पता है कि आज़ादी की लड़ाई की क्या क़ीमत चुकाई गई थी और जनता उस क़ुर्बानी को न भूले और जिस आज़ाद और आदर्श भारत की कल्पना उन शहीदों ने की थी, उसे क़ायम रखने के लिए क़दम आगे बढ़ाए. यही उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही सोच असली स्वतंत्रता को साकार रूप दे पाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 23
दिल्ली, 12 अगस्त–18 अगस्त 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय	0120–6451999
	6450888
	6452888
	011–23418962
विज्ञापन व प्रसार	+91–9266627379
फैक्स न.	0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

जल्द हो सकते हैं लोकसभा चुनाव

कांग्रेस पार्टी अब यह मानकर चल रही है कि लोकसभा 2014 के चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है. पार्टी इस दिशा में जिस तरह से तेजी से तैयारियां कर रही है, उसको देखकर इस आशंका को और बल मिल रहा है. हाल ही में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रबंधकों ने मध्य दिल्ली में छह बड़े बंगलों को किराये पर लिया. पार्टी के एक महासचिव ने इन बंग्लों का निरीक्षण किया. पार्टी इन बंगलों का इस्तेमाल प्रत्याशियों के चयन और चुनाव प्रचार सामग्री के भंडारण के तौर पर करेगी. ऊपरी तौर देखें, तो एक बारगी यह लगेगा कि यह सब कुछ जल्दी में किया जा रहा है, लेकिन इससे साफ़ मतलब निकाला जा सकता है कि चुनाव तय समय से पहले ही हो सकते हैं.

हालांकि पार्टी प्रवक्ताओं के जो आधिकारिक बयान आ रहे हैं, उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव तयशुदा समय पर ही होंगे, लेकिन जिस तरह से हाल ही में विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किए गए चुनावी सर्वेक्षणों के परिणाम आए और उनमें यूपीए सरकार की सीटें घट रही हैं, उससे सरकार की चिंता ज़रूर बढ़ी है. साथ ही पार्टी ने एक आंतरिक सर्वे भी कराया है. वह सर्वे भी पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है.

इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस का एक धड़ा यह सलाह दे रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ ही कराया जाए, क्योंकि आनेवाले समय में पार्टी की छवि में कोई बड़ा सकारात्मक इजाफा हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है. भ्रष्टाचार के आरोप, महंगाई, रुपये के मूल्य में गिरावट आगामी चुनावों में पार्टी के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर सकती है. इससे पहले कि हालात और ख़राब हों, पार्टी के अंदर ऐसे नेताओं की जमात बढ़ रही है, जो दिसंबर तक ही चुनाव कराना चाहते हैं.

हालांकि पार्टी के भीतर एक पक्ष ऐसा भी है, जो चाहता है कि चुनाव तयशुदा समय पर ही हो. उनका मानना है कि यूपीए को अब अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे फूड सिक्योरिटी बिल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करना चाहिए, जिससे लोगों में पार्टी की छवि सुधरेगी. साथ ही अच्छे मॉनसून के चलते खरीफ की पैदावार अच्छी होने की संभावना है और रबी की फसल के बेहतर होने का भी अनुमान है. इस धड़े का मानना है कि यह पूरा पैकेज मिलकर पार्टी के पक्ष में ही जाएगा.

इससे एकदम अलग एक यह विचार भी सामने आ रहा है कि अगर अभी तयशुदा समय से पहले चुनाव की घोषणा कर दी जाती है, तो प्रमुख विपक्षी दल के लिए यह चौंकाने वाला फ़ैसला होगा. साथ ही उन्हें चुनाव के लिए तैयारी का मौक़ा भी कम ही मिल पाएगा.

इन सब कयासों के बावजूद, अभी भी इस मुद्दे पर किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता. सरकार और पार्टियां उन सभी कमियों को दूर करने में लगी हैं, जो उन्हें नुक़सान पहुंचा सकती हैं और उन मुद्दों को तलाशने में लगी हैं, जो उनकी छवि को और मजबूत करे. यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी फूड सिक्योरिटी बिल के माध्यम से इस रास्ते पर बढ़ रही है और इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश में है.

इसी दौर में पार्टी लंबे समय से तेलंगाना को अलग राज्य के लिए उठ रही मांग को अंतिम रूप देने की कोशिश में लगी है. हालांकि अभी भी इसका काफ़ी विरोध हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने यह फ़ैसला चुनावों के मद्देनज़र राजनीतिक लाभ के लिए ही किया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

साउथ ब्लॉक

आभा शुक्ला सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त

1993 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईएएस आभा शुक्ला को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. फिलहाल वह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं.

पुष्पा सुब्रमण्यम एमएसएमई में संयुक्त सचिव बनीं

1985 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की आईएएस पुष्पा सुब्रमण्यम की सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति की संभावना है. वह 1983 बैच के बिहार कैडर के आईएएस सी के मिश्रा का स्थान ले सकती हैं.

जेम्स कुरियन कैबिनेट सचिवालय में सयुक्त सचिव होंगे

1987 बैच के यूटी कैडर के आईएफएस जेम्स कुरियन राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार कन्वेंशन मंत्रालय में सयुक्त सचिव का पद संभाल सकते हैं. वह यूटी कैडर के 1989 बैच के आईएएस जी नरेंद्र कुमार का स्थान लेंगे.

नॉयल थामस प्रवासी भारतीय मामलों के निदेशक होंगे

1991 बैच के केरल कैडर के आईएफएस नॉयल थामस को जल्द ही प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय में निदेशक बनाया जा सकता है. वह 1999 बैच के हरियाणा कैडर के आईएफएस अनंत प्रकाश का स्थान लेंगे.

युवा मामलों के मंत्रालय में जाएंगे ललित

1987 बैच के आईएएस अधिकारी ललित कुमार गुप्ता को युवा मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में ज़िम्मेदारी दी जा सकती है. वह 1987 बैच के आईए एंड एस अधिकारी राकेश मोहन का स्थान लेंगे. राकेश अल्पसंख्यक विभाग में संयुक्त सचिव का पद संभाल सकते हैं. ■

दिल्ली भारत की राजधानी है. यहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं. हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालयों के लिए कायदे–कानून बनाने वाला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी यहीं पर स्थित है. एचआरडी मिनिस्ट्री का दफ्तर भी यहीं पर है. दिल्ली स्थित जामिया हमदर्द में चल रही धांधलियों की खबर इन लोगों तक भी ज़रूर पहुंची होगी, पर हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी जीएन क़ाज़ी को रोकने की कोशिश तक नहीं की.

जामिया हमदर्द में घोर अनियमितताएं

कुलपति को रोकने वाला कोई नहीं

क्या प्रवेश परीक्षा दिए बगैर किसी का मेडिकल कोर्स में एडमिशन हो सकता है? बगैर इंटरव्यू दिए हुए कोई प्रोफेसर बन सकता है? क्या कोई किसी विश्वविद्यालय के ऐसे पद पर नियुक्त हो सकता है, जिसके लिए उसने कभी न तो अप्लाई किया हो और न ही इंटरव्यू दिया हो? क्या किसी यूनिवर्सिटी का कुलपति रिटायर होने के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है? अगर आपका जवाब ना है, तो शायद आपको मालूम नहीं कि दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित जामिया हमदर्द में ये सब कुछ खुद वहां के कुलपति डॉ जीएन क़ाज़ी की मर्ज़ी से हो रहा है. कैसे? आइये पढ़ते हैं इस रिपोर्ट में.

डॉ. क़मर तबरेज़

सर सैयद अहमद खान के बाद भारतीय मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी ने आगे बढ़ाने का सबसे अधिक प्रयास किया, तो वह हकीम अब्दुल हमीद थे. हमदर्द दवाखाना और पूरी दुनिया में यूनानी इलाज के तरीके को दोबारा जिंदा करने की वजह से उन्हें देश–दुनिया में ख्याति मिली. वह चाहते थे कि भारत में हर धर्म और जाति के बच्चों की उच्च स्तरीय शिक्षा का भी बेहतर प्रबंध हो, इसीलिए उन्होंने 1948 से ही इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया था. हमदर्द दवाखाना से उन्होंने जो पैसे कमाए, उससे उन्होंने दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बंजर पड़ी ज़मीनों को खरीदना शुरू किया और फिर उस ज़मीन पर 1962 से लेकर 1972 तक यूनानी पर आधारित बहुत सी शैक्षणिक संस्थाएं बनाईं. बाद में हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी के तहत इन सभी संस्थानों को मिलाकर उसे जामिया हमदर्द का नाम दिया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1 अगस्त, 1989 को विश्वविद्यालय के तौर पर इसका उद्घाटन किया. अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हकीम अब्दुल हमीद ने पूर्व आईएएस ऑफिसर और 1980 से 1985 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके सैयद हामिद को हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी का सेक्रेटरी बनाया. बाद में सैयद हामिद की कोशिशों से ही जामिया हमदर्द को 2004 में माइनॉरिटी कैरेक्टर और फिर 2009 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला. और अब, जबकि जामिया हमदर्द के केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने की आशाएं काफी हद तक बढ़ चुकी हैं, खुद यहां के कुलपति डॉ जी एन क़ाज़ी असंवैधानिक तरीके से अपने पद पर बने हुए हैं, मनमाने ढंग से फैकल्टी को नियुक्त कर रहे हैं और इसे बर्बाद करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ रहे हैं. वह इसे एक निजी संस्था बना देना चाहते हैं, ताकि ज़िंदगी भर खुद भी इसे लूटें और बाद में अपने सगे–संबंधियों को लूटने का बंदोबस्त करके जाएं. केंद्र की यूपीए सरकार, एचआरडी मिनिस्ट्री, दिल्ली हाईकोर्ट के जजों और अपने इलाके की पुलिस तक से उनकी इतनी ज़बरदस्त सेटिंग है कि किसी में उनके खिलाफ बोलने तक की हिम्मत नहीं है. चौथी दुनिया के पास इसके सारे सुबूत मौजूद हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम सबके सामने इसे पेश भी कर सकते हैं.

एमबीबीएस के एडमिशन में धांधली

हमदर्द मेडिकल कॉलेज ने वर्ष 2012 में मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया की अनुमति से अपने यहां पहली बार प्राइवेट तरीके से एमबीबीएस का कोर्स शुरू किया. इसके लिए उसे 100 छात्रों का प्रवेश लेने की अनुमति मिली, 85 जनरल केटेगरी के और 15 मैनेजमेंट केटेगरी के. जनरल केटेगरी के छात्रों की फीस रखी गई 6 लाख रुपये वार्षिक, जबकि मैनेजमेंट कैटेगरी के लिए 15 लाख वार्षिक. मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (एमसीआई) के नियमों के मुताबिक, फॉर्म भरने वाले सभी उम्मीदवारों का (जिनमें एनआरआई और विदेशी छात्र भी शामिल हैं) का प्रवेश परीक्षा में बैठना और फिर उसमें 50 प्रतिशत नंबर लाना आवश्यक है, लेकिन जब रिजल्ट आया, तो पता चला कि मोहम्मद आमिर और उमर अली नाम के दो एनआरआई स्टूडेंट ने न तो इसके लिए फॉर्म भरे थे और न ही वह प्रवेश परीक्षा में बैठे, फिर भी उनका एमबीबीएस कोर्स में चयन हो गया. यही नहीं, ज़ारा खान और समां रिज़वी नाम की दो छात्राओं ने प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक हासिल नहीं किए, फिर भी उनका चयन हो गया. बाद में जब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा, तो डब्ल्यू पी(सी) 5986/2012 और 740/2013 की सुनवाई के दौरान 8 फ़रवरी, 2013 को कोर्ट ने इन चारों उम्मीदवारों के एडमिशन को गैरकानूनी और एमसीआई के रूल्स का उल्लंघन बताया.

फैकल्टी की नियुक्ति में धांधली

डॉक्टर अली अहमद फिरदौसी ने 18 मई, 2010 को अंग्रेज़ी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस में हमदर्द के विज्ञापन नंबर 4/2010 को देखकर डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेट ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (डीओडीएल) के पद के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति जीएन क़ाज़ी को अपना बायोडाटा भेजा. हालांकि फिरदौसी के पास डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित न तो कोई डिग्री थी और न ही कोई पूर्व अनुभव. उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में एमए, पीएचडी की है और जिस समय उन्होंने अपना बायोडाटा हमदर्द विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजा था, उस समय वह हैदराबाद में स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया के सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ में बतौर प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे थे.

बहरहाल, डायरेक्टर के इस इकलौते पद के लिए 16 अगस्त, 2010 को सेलेक्शन कमेटी बैठी, जिसके सामने इंटरव्यू के फॉर्म भरने वाले कुल 11 उम्मीदवारों में से 6 उपस्थित हुए. सेलेक्शन कमेटी ने डीओडीएल के डायरेक्टर के पद पर डॉक्टर संजय मिश्रा को नियुक्त किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर ए. ए. फिरदौसी, जो न तो इंटरव्यू देने के लिए सेलेक्शन कमेटी के सामने उपस्थित हुए और न ही सेलेक्शन कमेटी हमदर्द कोचिंग एकेडमी के प्रोफेसर का चयन करने के लिए बैठी थी. इसके बावजूद कुलपति जीएन क़ाज़ी और चयन समीति के सदस्य प्रोफेसर एसएए ज़ैदी, प्रोफेसर सिद्दीक़ी वाहिद, प्रोफेसर मोहम्मद मियां और डॉक्टर लता पिल्लई ने अपने हस्ताक्षर से उन्हें सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कराने वाली इस कोचिंग एकेडमी में प्रोफेसर नियुक्त कर दिया.

इसी प्रकार की अन्य नियुक्तियां भी कुलपति जीएन क़ाज़ी ने सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए की और हमदर्द विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा व प्रतिष्ठा को प्रदूषित किया. उदाहरणस्वरूप हेल्थ मैनेजमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से डॉक्टर एन रविचन्द्रन की नियुक्ति की गई (जबकि विज्ञापन प्रोफेसर के पद के लिए दिया गया था), जिनके पास हेल्थ मैनेजमेंट या स्वयं मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी डिग्री नहीं है, बल्कि उन्होंने गणित और पॉपुलेशन साइंस में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है और एम. फिल और पीएचडी सोशल साइंस में की है. इनके पास प्रोफेसरशिप के लिए जरूरी न तो 10 साल पढ़ाने का अनुभव है और न ही वह पांच साल तक रीडर या इसके समकक्ष पदों पर कभी नियुक्त रहे हैं. फिर भी कुलपति डॉक्टर जीएन क़ाज़ी, चांसलर सैयद हामिद के द्वारा नामज़द सदस्य जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब्दुल नाफे और एक्सपर्ट मेंबर प्रोफेसर मिर्ज़ा सैयदेन, प्रोफेसर फुरक़ान क़मर (योजना आयोग, भारत सरकार) और डॉक्टर तलब हलीम (सीईओ, मैक्स हेल्थ सेंटर) पर आधारित सेलेक्शन कमेटी ने उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफ़ॉरमेशन टेक्नोलॉजी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया. जमिया हमदर्द के कुलपति जीएन क़ाज़ी ने डॉक्टर एस रईसुद्दीन, डॉक्टर रेशमा नसरीन और वसुंधरा शर्मा की नियुक्तियों के दौरान भी इसी प्रकार की धांधलियां कीं और नियमों की धज्जियां उड़ाईं.

कुलपति के पद पर अवैध क़ब्ज़ा

डॉक्टर जीएन क़ाज़ी जामिया हमदर्द के कुलपति के पद से 14 अगस्त, 2011 को रिटायर हो गए, लेकिन अवैध रूप से इस पद पर अब भी क़ब्ज़ा जमाए बैठे हैं और जामिया हमदर्द कार्यकारिणी परिषद से अपनी सेवा अवधि बढ़वाने के लिए ख़ुद ही नोटिफिकेशन जारी करवा देते हैं. किसी के अन्दर उनके ख़िलाफ़ बोलने का साहस नहीं है. आइए, सबसे पहले यह देखते हैं कि इस सिलसिले में क़ानून क्या कहता है.

जामिया हमदर्द को डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी (यानी, जिसको कभी भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा सकता है) का दर्जा प्राप्त है, जो सैयद हामिद के अथक प्रयासों का परिणाम है. यूजीसी ने 2008 में ऐसे विश्वविद्यालयों को इस बात की अनुमति दी कि वहां के कुलपति या डायरेक्टर्स की रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 साल कर दी जाए, लेकिन इसके लिए यूजीसी ने शर्त यह रखी कि रिटायरमेंट से संबंधित इस निर्णय को लागू करने से पहले इस यूनिवर्सिटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) या नियमों में संशोधन होना चाहिए. जीएन क़ाज़ी अगस्त 2014 में जिस समय सेवानिवृत्त हो रहे थे, उस समय तक हमदर्द के एमओए या नियमों में कुलपति की रिटायरमेंट की आयु को लेकर संशोधन नहीं हुआ था और अब, यानी अगस्त 2013 तक यह काम पूरा नहीं हो सका है, बल्कि संशोधन का यह सिलसिला अब भी जारी है. ऐसे में जामिया हमदर्द के कुलपति के पद पर जीएन क़ाज़ी का बने रहना अवैध नहीं, तो भला और क्या है? रिटायरमेंट की आयु से संबंधित विवाद पर ही राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर हमीदुल्ला भट्ट को उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अपना पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन जीएन क़ाज़ी की सेटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि उनको हटाने में अब न्यायालय भी असमर्थ है.

जामिया हमदर्द को डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी (यानी, जिसको कभी भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा सकता है) का दर्जा प्राप्त है, जो सैयद हामिद के अथक प्रयासों का परिणाम है. यूजीसी ने 2008 में ऐसे विश्वविद्यालयों को इस बात की अनुमति दी कि वहां के कुलपति या डायरेक्टर्स की रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 साल कर दी जाए, लेकिन इसके लिए यूजीसी ने शर्त यह रखी कि रिटायरमेंट से संबंधित इस निर्णय को लागू करने से पहले इस यूनिवर्सिटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) या नियमों में संशोधन होना चाहिए.

दिल्ली भारत की राजधानी है, जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं. हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालयों के लिए कायदे–कानून बनाने वाला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी यहीं पर स्थित है. एचआरडी मिनिस्ट्री का दफ्तर भी यहीं पर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जामिया हमदर्द में चल रही इन धांधलियों की खबर उन तक भी ज़रूर पहुंची होगी, पर किसी ने भी जीएन क़ाज़ी को रोकने की कोशिश तक नहीं की. क्या सरकार ऐसे ही मूकदर्शक बनी रहेगी या अपनी नाक के नीचे हो रही इन गैरकानूनी कार्यों को रोकने का कष्ट करेगी? अल्पसंख्यकों के कल्याण की बातें तो खूब की जाती हैं, लेकिन क्या जामिया हमदर्द जैसी प्रतिष्ठित अल्पसंख्यक संस्था को बचाने की भी कोई कोशिश सरकार की तरफ से होगी? ■

feedback@chauthiduniya.com

देश की सीमाओं से बाहर निकलकर सोशल मीडिया की ताकत तलाशें, तो ओबामा के राष्ट्रपति बनने में सोशल मीडिया पर चलाए गए उनके चुनावी अभियान को बड़ा क्रेडिट दिया गया. पहली बार कोई चुनावी अभियान पूरी तरह सोशल मीडिया से संचालित हुआ था. इसी तरह इजिप्ट आंदोलन को सोशल मीडिया से पैदा हुए उन्माद का परिणाम माना जाता है.

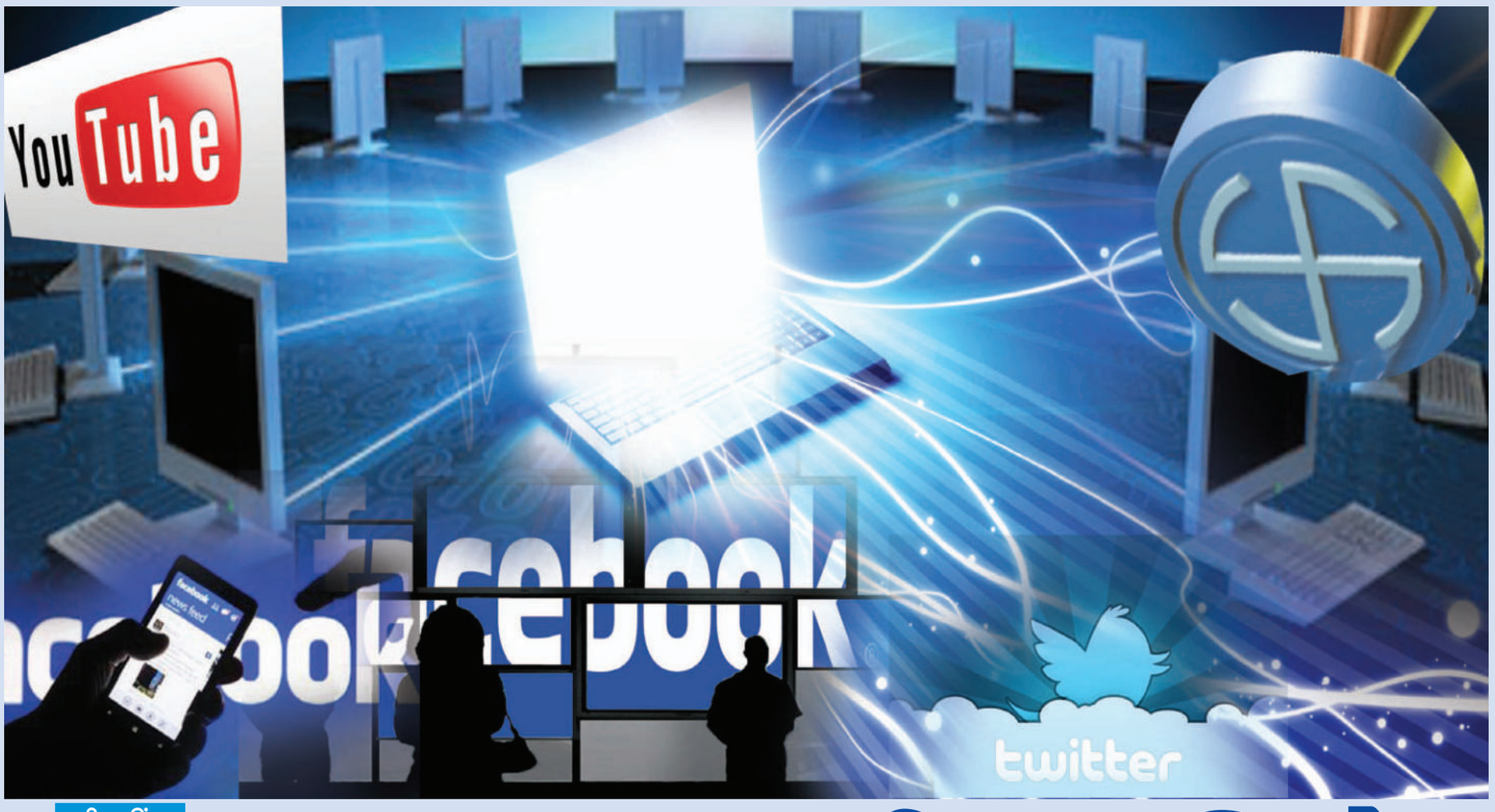

साइबर खिड़की के पीछे खड़ा मतदाता

इस बात की चर्चा गर्म है कि 2014 का लोकसभा चुनाव सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ा जाएगा. एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच सोशल मीडिया और उस पर सक्रिय वर्चुअल मिडिल क्लास भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा? यह तभी संभव है, जब हर एक फ्रेंड की तरह हर एक वोट का भी महत्व समझा जाए, अन्यथा साइबर खिड़की के पीछे का मतदाता खड़ा ही रह जाएगा और सोशल मीडिया एक प्रोपगंडा बन कर रह जाएगा...

नीरज सिंह

भारतीय राजनीति के कुछ पहलुओं पर गौर करने पर साफ़ पता चलता है कि देश की राजनीति अचानक कुछ बदलावों के साथ नये रूप में सामने आ रही है. उसके इस नयेपन पर सर्वाधिक प्रभाव सोशल मीडिया का है. राजनीतिक हलकों में यह जुमला पिछले लंबे समय से हवा में है कि 2014 का लोकसभा चुनाव सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ा जाएगा, लेकिन इस सोच को लेकर जिस तरह से पार्टियां गंभीर होती दिख रही हैं, तब इस बात को समझना मौजूं हो जाता है कि क्या सोशल मीडिया हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, के दायरे से निकलकर देश की राजनीतिक इबारत लिखने का दमखम रखता है.

हाल ही में कांग्रेस ने पार्टी विचारधारा में दिलचस्पी रखने वाले आम लोगों से सोशल नेटवर्क के ज़रिये जुड़ने के लिए एक नये प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है. पार्टी ने इसे नाम दिया गया है–खिड़की. यूपीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सरकार देश भर में डिजिटल वॉलेंटियर बनाने की शुरुआत पहले ही कर चुकी है. भारतीय जनता पार्टी तो इस दिशा में बेहद सक्रिय है. ऐसी ही कोशिशें तक़रीबन सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस सोच के साथ जारी है कि आने वाला समाज डिजिटल होगा और ऐसे समाज पर पैठ बनाने के लिए अभी से कोशिश ज़रूरी है.

हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम्स में स्तंभकार थॉमस फ्रेडमैन ने लिखा है कि उन्होंने भारत के अपने ताजा दौरे पर जो देखा, वह उनके लिए एक अनोखा अनुभव था–एक बिल्कुल नई राजनीतिक बिरादरी, भारत का वर्चुअल मिडिल क्लास. लेकिन सवाल यह है कि क्या विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र या उससे पहले ही वजूद में आ चुके राजनीतिक दांव–पेंच और उनकी उलझनें इतनी सुलझ गई हैं कि पिछले 10 साल से अस्तित्व में आया सोशल मीडिया और उस पर सक्रिय वर्चुअल मिडिल क्लास भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा?

कुछ दिनों पहले आईआरआईएस नॉलेज फाउंडेशन, इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन में कहा गया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 543 लोकसभा सीटों में से 160 सीटों के नतीजों को सोशल मीडिया प्रभावित कर सकता है. सोशल मीडिया के प्रभाव में आने वाले ये ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां कुल मतदाताओं की संख्या के दस फ़ीसदी फेसबुक यूजर्स हैं, साथ ही जहां फेसबुक यूजर्स की संख्या पिछले लोकसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवारों की जीत के अंतर से अधिक हैं. इस अनुमान के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक 21, गुजरात में 17, उत्तर प्रदेश की 14, कर्नाटक की 12, मध्यप्रदेश में 9 और दिल्ली की सभी 7 सीटें सोशल मीडिया के उच्च प्रभाव में हैं. हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की पांच–पांच सीटें, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू–कश्मीर, झारखंड और पश्चिम बंगाल की चार सीटों के नतीजे सोशल मीडिया द्वारा प्रभावित हो सकते हैं. अध्ययन में 67 निर्वाचन क्षेत्रों को मध्यम प्रभाव, 60 निर्वाचन क्षेत्रों को कम प्रभाव और 256 निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावहीन घोषित किया गया है. जिस आधार पर यह आंकड़े तय किए गए हैं, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, इसके लिए राजनीति और सोशल मीडिया के समाजशास्त्र को समझना होगा.

डिजिटल दुनिया का बड़ा हिस्सा एक आभासी समाज है. सोशल मीडिया भी उसी आभासी समाज का एक बड़ा हिस्सा है. अगर ठीक से इसका साथ मिला, तो कोई कुछ भी बन सकता है. फेसबुक पर राहुल गांधी के कई प्रोफाइल और पेज हैं. कई प्रोफाइल तो ऐसे हैं, जिन्हें पढ़कर लगेगा कि राहुल गांधी अभी भी बचपन में जी रहे हैं. ऐसे में जो लोग इन प्रोफाइल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके बारे में क्या माना जाए कि वो राहुल गांधी के समर्थक हैं. इसका जवाब होगा, नहीं, क्योंकि जैसे फेक प्रोफाइल, वैसे फेक समर्थक. हाल ही में एक उदाहरण सामने आया. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फेसबुक पेज पर अचानक लाइक करने वालों की संख्या बढ़ गई और पता चला कि उनके एक लाख से अधिक समर्थक तुर्की से हैं, जिन्हें ख़रीदा गया है. इंटरनेट पर ऐसी कई एजेंसियां सक्रिय हैं, जो पैसे लेकर लाइक्स बेच रही हैं. ऐसे ख़रीदे हुए लाइक को वो भी, जो तुर्की या दूसरे देशों से मिल रहे हैं. ऐसे में उन्हें वोटर या समर्थक समझना बेमानी होगा.

तो क्या साइबर संसार और ख़ास कर सोशल मीडिया की वास्तविकता को एकदम से नकार दिया जाए. बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए न केवल एक विकल्प है, बल्कि एक कारगर हथियार बनकर उभरा है. मसलन, अकबरुद्दीन ओवैसी के नफरत फैलाने वाले भाषण के यू–ट्यूब पर तेजी से फैलने के बाद 8 जनवरी को ओवैसी की गिरफ्तारी, अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, जो 2011 में कई दिनों तक दुनिया में सबसे ऊपर रहने वाला ट्विटर ट्रेंड था. दिसंबर 2012 में दिल्ली गैंगरेप के ख़िलाफ़ आंदोलन, जिसने सोशल मीडिया के मंचों पर लोगों की टिप्पणियों से हवा मिलने के कारण व्यापक रूप ले लिया था. दिल्ली गैंगरेप के बाद सोशल मीडिया पर अवाम का गुस्सा जिस तरह से देखने को मिली, उसने सरकार की भी चूलें हिला कर रख दी थीं.

देश की सीमाओं से बाहर निकलकर सोशल मीडिया की ताक़त तलाशें, तो ओबामा के राष्ट्रपति बनने में सोशल मीडिया पर चलाए गए उनके चुनावी अभियान को बड़ा क्रेडिट दिया गया. पहली बार कोई चुनावी अभियान पूरी तरह सोशल मीडिया से संचालित हुआ था. इसी तरह इजिप्ट आंदोलन को सोशल मीडिया से पैदा हुए उन्माद का परिणाम माना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बदलाव के इन सभी उदाहरणों में केवल ओबामा के चुनाव को छोड़कर गौर करिए, तो उनमें उन्माद अधिक और संगठनात्मक भूमिका कम दिखेगी. यह वह भीड़ है, जिसके लिए बदलाव की मांग फैशन है. यह भीड़ अपने साथियों के साथ निकल पड़ती है, यह युवा मानसिकता का उन्माद है, जिनमें से ज़्यादातर लोग राजनीति को सारी मुश्किलों की जड़ मानते हैं, लेकिन उससे निपटा कैसे जाए, इसका एक ही जवाब है क्रांति. एक विश्लेषक के नज़रिये से देखिए, तो देश की राजनीतिक दशा को बदलने के लिए क्रांति की नहीं, सही चुनाव करने की ज़रूरत है, जिसे केवल फेसबुक के माध्यम से नहीं समझा जा सकता. अगर समझा जा सकता था, तो सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय नरेंद्र मोदी गुजरात में इस माध्यम का बेहतर प्रयोग कर और चुनाव जीत कर जब कर्नाटक प्रचार करने जाते हैं, तो असफल रहते हैं, जबकि कर्नाटक में इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की संख्या गुजरात से ज़्यादा है.

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ इस दंभ के साथ पाकिस्तान लौटे थे कि पाकिस्तान में उनके 2 लाख से अधिक फॉलोअर ट्विटर पर मौजूद हैं. उन्हें भरोसा था कि यह समर्थक उनके लिए क्रांति करेंगे, लेकिन उनके वतन पहुंचने पर यह सारा समर्थन बस आभासी ही रह गया. कांग्रेसी नेता शशि थरुर ख़ुद यह बात मानते हैं कि ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स में ऐसे युवाओं की संख्या ज़्यादा है, जिनकी उम्र अभी वोट देने की नहीं है. दरअसल, हमें यह बात स्वीकारनी होगी कि भारतीय मतदाता धर्म–जाति, पैसा–पावर, क्षेत्र जैसे मुद्दों पर केंद्रित राजनीति से अभी उतना ऊपर नहीं उठ पाया है कि उसकी सोच का किसी आभासी कैंपेन के माध्यम से परिवर्तन किया जा सके. जिस शहरी और युवा मतदाता के भरोसे हम सोशल मीडिया को राजनीतिक हथियार मान रहे हैं, उसे इस उदाहरण से समझिए.

गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार के विकास के दावों का माखौल उड़ाती एक मॉडल की तस्वीर आपको याद होगी. मॉडल तूलिका पटेल को कांग्रेस सरकार ने गुजरात में मोदी के ख़िलाफ़ अपना ब्रांड अंबेसडर बनाया था. इस सोच के साथ कि तूलिका राज्य के युवा मतदाताओं को प्रभावित करेंगी, लेकिन तूलिका व्यक्तिगत रूप से किसके समर्थन में है. चित्रलेखा मैगजीन द्वारा पूछे गए इस सवाल के जवाब में तूलिका ने कहा था कि मुझे कांग्रेस पार्टी से पैसे मिल रहे हैं, इसलिए मैं उनके पक्ष में प्रचार कर रही हूं, लेकिन मेरा पूरा परिवार बीजेपी के समर्थन में है. दूसरे, सोशल मीडिया पर जो ओपिनियन मेकिंग हो रही है, वह ब्लाइंड फॉलोइंग के आधार पर ज़्यादा है. पिछले वर्ष जब आस्ट्रेलिया रेडियो स्टेशन 2डे से की गई प्रैंक कॉल के चलते ब्रिटेन के एक अस्पताल में भारतीय मूल की नर्स जेसंथा सलदान्हा ने आत्महत्या कर ली थी, तब भारतीय मीडिया ने फेसबुक से उसका नाम सर्च किया और जो तस्वीर हासिल हुई, वह बेंगलुरु की एक घरेलू महिला जेसंथा सलदान्हा की मिली. तीन दिन तक समूचा भारतीय मीडिया बेंगलुरु की महिला को ब्रिटेन की मृतक आर जे मानता रहा. ऐसी ब्लाइंड फॉलोइंग्स के आधार पर क्या राजनीतिक पेचीदगियों को समझा जा सकता है.

हालांकि जिस आधार पर राजनीतिक दल सोशल मीडिया की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं, उन्हें एकदम से नाकारा भी नहीं जा सकता. आकंडों पर गौर करें, तो पिछले 10 वर्षों में शहरी आबादी कुल आबादी का लगभग 32 फीसद है. इनमें 52 फीसद मिडिल क्लास है और पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली मिडिल क्लास की आबादी चीन के बाद भारत में ही है. युवा आबादी सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय है और देश में 35 फीसद आबादी 25 साल से कम उम्र के युवाओं की है. जनगणना 2011 से मिले आंकड़ों पर गौर करें, तो 2001 से 2011 के बीच देश में 2875 नये शहर बने. शहरी आबादी बढ़ी. आधुनिक टेक्नोलॉजी और संचार की सुविधाएं बढ़ीं. गांवों की सीटें शहरी सीटों में तब्दील हो गईं. आज देश में लगभग 25 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं. किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह आंकड़े बेहद उत्साहित करने वाले हैं, लेकिन अपने देश में पॉलिटिकल ओपिनियन मेकिंग में राजनेताओं की हिस्सेदारी कितनी है, यह इन आंकड़ों से साफ हो जाता है. आंकड़ों के मुताबिक संसद से सबसे ज़्यादा गैरहाजिर रहने वाले सांसद वे हैं, जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है.

साथ ही राजनीतिक दलों को यह भी समझना होगा कि साइबर मीडिया पर सक्रिय युवा आबादी उनकी लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सभी डिजिटल सैनिक भर नहीं हैं. उसमें एक बड़ा तबका वह भी शामिल है, जिसे सोशल मीडिया पर उभार ले रही राजनीतिक बहसों से कोई मतलब नहीं है.

अभी यह समझना बाक़ी है कि सोशल मीडिया के मंचों पर जन्म ले रहा वर्चुअल मीडिल क्लास, क्या केवल अपने अधिकारों की लड़ाई को लेकर ही आवाज़ उठाने में विश्वास रखता है या उसकी राजनीतिक चेतना भी उतनी ही विकसित है. हां, यह तस्वीर सुखद ज़रूर होगी, यदि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, को महत्व देने वाला युवा इस बात को भी उतना ही महत्व दे कि हर एक वोट भी ज़रूरी होता है. ■

डिजिटल दुनिया का बड़ा हिस्सा एक आभासी समाज है. सोशल मीडिया भी उसी आभासी समाज का एक बड़ा हिस्सा है. अगर ठीक से इसका साथ मिला, तो कोई कुछ भी बन सकता है. फेसबुक पर राहुल गांधी के कई प्रोफाइल और पेज हैं. कई प्रोफाइल तो ऐसे हैं, जिन्हें पढ़कर लगेगा कि राहुल गांधी अभी भी बचपन में जी रहे हैं. ऐसे में जो लोग इन प्रोफाइल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके बारे में क्या माना जाए कि वो राहुल गांधी के समर्थक हैं.

हाल ही में कांग्रेस ने पार्टी विचारधारा में दिलचस्पी रखने वाले आम लोगों से सोशल नेटवर्क के ज़रिये जुड़ने के लिए एक नये प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है. पार्टी ने इसे नाम दिया गया है- खिड़की. यूपीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सरकार देश भर में डिजिटल वॉलेंटियर बनाने की शुरुआत पहले ही कर चुकी है. भारतीय जनता पार्टी तो इस दिशा में बेहद सक्रिय है. ऐसी ही कोशिशें तक़रीबन सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस सोच के साथ जारी है कि आने वाला समाज डिजिटल होगा और ऐसे समाज पर पैठ बनाने के लिए अभी से कोशिश ज़रूरी है.

feedback@chauthiduniya.com

महाबोधि मंदिर प्रबंधन मामले के विवाद की सही जानकारी के लिए इतिहास में जाना होगा. कहा जाता है कि चौदहवीं शताब्दी के पुर्वार्द्ध तक बोधगया बौद्धों का एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन समय के साथ–साथ बिहार में बौद्ध धर्म का प्रचार–प्रसार कम होने लगा और सनातन धर्म का बोल–बाला बढ़ने लगा. इसके परिणामस्वरूप चौदहवीं शताब्दी के अंत तक बौद्धों का यह केंद्र समाप्त हो गया.

महाबोधि मंदिर प्रबंधन में बदलाव के प्रस्ताव पर

हिंदुओं और बौद्धों में टकराव

महाबोधि मंदिर में सीरियल बम ब्लास्ट की घटना के बाद बिहार सरकार ने बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमिटि एक्ट–1949 में संशोधन करने का निर्णय लिया है. सरकार के इस निर्णय से एक नया विवाद शुरू हो गया है. हिंदुवादी संगठन, बीटीएमसी के सदस्य सरकार के इस निर्णय का विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बौद्ध तथा बौद्ध संगठन भी महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूर्णत: बौद्धों के हाथों सौंपने की मांग कर रहे हैं.

सुनील सौरभ

वर्ल्ड हेरिटेज महाबोधि मंदिर बोधगया में सीरियल बम ब्लास्ट की घटना के बाद जागी बिहार सरकार ने अब बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमिटि एक्ट–1949 में संशोधन करने का निर्णय लिया है. 64 वर्ष पुराने इस एक्ट में संशोधन के सरकार के निर्णय से पुन: एक नया विवाद शुरू हो गया है. बी.टी.एम.सी. एक्ट–1949 में बिहार सरकार के संशोधन का विरोध हिंदुवादी संगठनों के साथ–साथ बी.टी.एम.सी. के सदस्य तथा सचिव रह चुके लोग भी करने लगे हैं. वहीं दूसरी ओर बौद्ध तथा बौद्ध संगठन भी बिहार सरकार के इस निर्णय को अपर्याप्त बताते हुए महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूर्णत: बौद्धों के हाथों सौंपने की मांग कर रहे हैं. बोधगया टेंपल मैनेजमेंट एक्ट–1949 के अनुसार, कमिटि में चार बौद्ध और चार हिंदू सदस्य होते हैं. उन्हीं में से किसी एक को सदस्य सचिव बनाया जाता है. इस एक्ट की धारा–3 (उपधारा–3) के अनुसार, गया के ज़िला पदाधिकारी इस कमिटि के पदेन अध्यक्ष होते हैं. हिंदू ज़िला पदाधिकारी नहीं होने की स्थिति में किसी दूसरे हिंदू पदाधिकारी को इसका पदेन अध्यक्ष बनाने का प्रावधान है. सरकार इसी प्रावधान को हटाने के लिए 1949 के इस एक्ट में संशोधन कर रही है. संशोधन के बाद गैर हिंदू भी बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमिटि के अध्यक्ष हो सकेंगे. सरकार के इसी संशोधन के निर्णय से विवाद शुरू हो गया है. लोगों ने सरकार के इस निर्णय को हिंदू तथा बौद्धों के बीच नफ़रत पैदा करने की कोशिश बताया है. वहीं बौद्धों तथा बौद्ध संगठनों ने सरकार के इस संशोधन को अपर्याप्त बताते हुए महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह बौद्धों को सौंपने की मांग कर रहे हैं.

क़रीब सौ साल पुराने इस विवाद को आज़ादी के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद तथा प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के प्रयास से सुलझाया गया था. बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्री कृष्ण सिंह ने बिहार विधानसभा से पारित कराकर इस एक्ट को अमलीजामा पहनाया था, तब से महाबोधि मंदिर का प्रबंधन इसी एक्ट के तहत हो रहा है. सच तो यह है कि इस मंदिर के मामले को लेकर बोधगया के शंकराचार्य मठ के तत्कालीन महंथ को आज़ादी के पूर्व प्रीवि काउंसिल, लंदन तक जाना पड़ा था और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी. महाबोधि मंदिर के प्रबंधन का विवाद सबसे पहले धर्मपाल ने उठाया था. महाबोधि मंदिर को लेकर हिंदुओं और बौद्धों में कभी विवाद नहीं हुआ. हालांकि कुछ मतभेद ज़रूर रहा. इस मतभेद का कारण महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित छह मूर्त्तियां हैं, जिसे हिंदू पंच पांडव के रूप में पूजते हैं. एक मूर्त्ति को द्रौपदी के रूप में पूजा जाता है, जबकि बौद्धों का नहीं, बल्कि नव बौद्धों का कहना है कि ये मूर्त्तियां भगवान बुद्ध की अलग–अलग मुद्राओं में हैं तथा महिला की मूर्त्ति तारा की है. हिंदुओं का यह भी कहना है कि भगवान बुद्ध विष्णु के नौवें अवतार हैं, इसलिए बौद्ध धर्म की दीक्षा के समय भी विष्णु के नाम का उच्चारण किया जाता है, लेकिन बौद्धों को इस पर भी आपत्ति है. महाबोधि मंदिर को लेकर अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पाया है कि हिंदुओं और बौद्धों के बीच टकराव हुआ हो. महाराष्ट्र के अंबेडकरवादी, जिसे नवबौद्ध भी कहा जाता है, का एक जत्था जापानी मूल के भारतीय नागरिक भदंत सुरई ससई के नेतृत्व में 1992 में बोधगया आया था और महाबोधि मंदिर को पूर्णत: बौद्धों के हाथों सौंपने के लिए उग्र आंदोलन के क्रम में पंच पांडव मंदिर में तोड़–फोड़ कर पुजारी की पिटाई भी की थी, तब हिंदूवादी संगठन भी आक्रोशित हो गए और नव बौद्धों की मांगों का विरोध करने लगे. इस समय बोधगया के पर्यटन व्यवसाय पर जबरदस्त असर पड़ा था, जिससे स्थानीय व्यवसायी तथा नागरिक भी नवबौद्धों के ख़िलाफ़ हो गए थे, लेकिन बाद में राजद की सरकार ने महाबोधि मंदिर मुक्ति आंदोलन से जुड़े भदंत सुरई ससई, भंते आनंद और भंते प्रज्ञाशील को बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमिटि का बौद्ध सदस्य मनोनित कर दिया और भंते प्रज्ञाशील को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया. इसके बाद यह विवाद थम गया. महाबोधि मंदिर के प्रबंधन के मामले के इस विवाद की सही जानकारी के लिए इतिहास में जाना होगा. कहा जाता है कि चौदहवीं शताब्दी के पुर्वार्द्ध तक बोधगया बौद्धों का एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन समय के साथ–साथ बिहार में बौद्ध धर्म का प्रचार–प्रसार कम होने लगा और सनातन धर्म का बोल–बाला बढ़ने लगा. इसके परिणामस्वरूप चौदहवी शताब्दी के अंत तक बौद्धों का यह केंद्र समाप्त हो गया. पूरे बोधगया में घास–फूस और जंगल उग गया.

1690 के आस–पास तत्कालीन बंगाल सरकार ने संपूर्ण बोधगया की सफाई करवाई. इसी क्रम में मिट्टी के नीचे दबे महाबोधि मंदिर की पहचान हुई. बाद के वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने इस मंदिर को बोधगया के महंथ के हाथों सौंप दिया. कहा जाता है कि 1890 में भारत के बौद्ध तीर्थ स्थलों की दुर्दशा पर अंग्रेज लेखक सर ऐडविन अर्नोल्ड का एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें बोधगया के महाबोधि मंदिर का जिक्र था. इसी लेख ने देश विदेश के बौद्धों का ध्यान बोधगया विशेष कर महाबोधि मंदिर की ओर खींचा. तत्पश्चात 31 अक्टूबर, 1891 को श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अनागरिक धर्मपाल की अध्यक्षता में बोधगया में बौद्धों का एक विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें बंगाल के तत्कालीन लेफ्टीनेंट गवर्नर सहित अनेक देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया. हिंदुओं के क़ब्ज़े से महाबोधि मंदिर को मुक्त कराने के संकल्प के साथ यह सम्मेलन समाप्त हुआ था, लेकिन बौद्धों के इस अनुरोध को तत्कालीन सरकार ने ठुकरा दिया था. इसके बाद उग्र बौद्धों ने महाबोधि परिसर में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा को जबरन उठाकर एक पुराने बौद्ध मंदिर में ले जाने की कोशिश की, जिसका महंथ के लठैतों ने विरोध किया. इस मुद्दे को लेकर बोधगया के महंथ और बौद्धों के बीच कई वर्षों तक फौजदारी मुक़दमा चला. अंतत: कलकत्ता हाईकोर्ट से महंथ की जीत हुई. कालांतर में बौद्धों द्वारा इस मामले को लंदन के प्रीवि काउंसिल में भी ले जाया गया, लेकिन वहां भी इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा. लोगों का कहना है कि 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में भी महाबोधि मंदिर के इस विवाद का जिक्र जोर–शोर से उठा था. बैठक में सर्वसम्मति से इस मामले के निपटारे की ज़िम्मेवार डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई थी. तब डॉ राजेंद्र प्रसाद ने हिंदुओं और बौद्धों की एक कार्य समिति बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में महाबोधि मंदिर के प्रबंधन में हिंदुओं और बौद्धों की संयुक्त भागीदारी पर ज़ोर दिया था. समिति की अनुशंसा के आलोक में 1935 में केंद्रीय सरकार के पास यह मामला गया, लेकिन पास नहीं हो सका. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्रीलंका, बर्मा, जापान आदि देशों के बौद्ध संगठनों ने इस मामले को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा.

पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने इस मामले में व्यक्तिगत रुचि दिखाई और उनकी पहल पर 21 जुलाई, 1949 को मंदिर में बौद्धों की भागीदारी से संबंधित बोधगया मंदिर एक्ट पास हुआ. इस ऐक्ट में मंदिर के प्रबंधन के लिए एक आठ सदस्यीय समिति का प्रवधान रखा गया, जिसमें बोधगया के महंथ के साथ–साथ हिंदु और बौद्धों के बराबर की भागीदारी रखी गई. वर्तमान में इसी ऐक्ट के तहत महाबोधि मंदिर का प्रबंधन चल रहा है, लेकिन अब बिहार सरकार ने इस एक्ट में बदलाव कर गैर हिंदू जिला पदाधिकारी को भी बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमिटि का पदेन अध्यक्ष बनाए जाने का निर्णय लिया है. इसी बदलाव के विरोध में भाजपा समेत अनेक हिंदूवादी संगठनों ने संघर्ष करने का ऐलान किया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

ऐक्ट में संशोधन आख़िर क्यों

बिहार सरकार द्वारा बोधगया मंदिर (संशोधन) बिल 2013 विधानसभा में पारित कराने पर बवाल शुरू हो गया है. बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति का अध्यक्ष गैर हिंदू ज़िला पदाधिकारी को भी बनाने के पारित प्रस्ताव से हिंदुओं तथा बौद्धों के बीच विवाद पैदा हो सकता है. विपक्षी दलों समेत अनेक संगठनों तथा महत्वपूर्ण लोगों ने सरकार के इस निर्णय पर उपर्युक्त बातें कहते हुए आपत्ति जताई है. बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता नंदकिशोर यादव ने इस विधेयक पर कहा है कि इसमें संशोधन से पहले बौद्ध धर्म की अनुयायियों की भावना का ख्याल रखा जाये. उन्होंने जानना चाहा कि आख़िर संशोधन विधेयक की ज़रूरत क्या है? क्या पहले का विधेयक ग़लत है? गैर हिंदू और गैर बौद्ध महाबोधी मंदिर प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कैसे बन सकता है? इस नए विधेयक से मंदिर को लेकर तनाव पैदा होगा. सरकार को इस विधेयक को वापस लेना चाहिए. पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बोधगया मंदिर प्रबंधन कमिटि में हिंदू या बौद्ध धर्म को मानने वाला ही चेयरमैन हो. उन्होंने कहा है कि बोधगया मंदिर कमिटि एक्ट 1949 में बना था, इसके लए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. श्री कृष्ण सिंह ने प्रस्ताव पेश किया था. अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि इस ऐक्ट को महात्मा गांधी का भी आशीर्वाद प्राप्त है. सरकार का संशोधन का निर्णय पूरी तरह ग़ैरवाजिब है और पूरे देश में नये विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम सभी हर स्तर पर विरोध करते हैं. राजद विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने संशोधन विधेयक को सरकार द्वारा हड़बड़ी में उठाया गया क़दम बताया. उनके मुताबिक, महाबोधि मंदिर में विस्फोट के बाद सरकार की नींद खुली है. उन्होंने कहा है कि डीएम को हटाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त बौद्ध धर्मावलंबी को वहां का अध्यक्ष होना चाहिए. पूर्व मंत्री और विधायक डॉ. प्रेम कुमार ने कहा है कि गया के गैर हिंदू ज़िला पदाधिकारी को बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति का अध्यक्ष मनोनीत किए जाने से हिंदुओं तथा बौद्धों के बीच टकराव पैदा होगा. सरकार का यह संशोधन पूरी तरह ग़लत है. इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा. बी.टी.एम.सी. के सदस्य और भाजपा नेता डॉ. राधाकृष्ण मिश्र ने कहा है कि मंदिर प्रबंधन के ऐक्ट में बदलाव कर सरकार पूरे ऐक्ट के औचित्य पर ही सवाल खड़ा कर रही है. इसका हर हाल में विरोध किया जाएगा. शंकराचार्य मठ बोधगया के महंथ सुदर्शनगिरि ने कहा है कि महाबोधि मंदिर के प्रबंधन ऐक्ट में संशोधन की ज़रूरत सरकार को क्यों पड़ी, यह समझ में नहीं आता. इस संशोधन से किसी को फ़ायदा नहीं होगा, पर विवाद ज़रूर बढ़ेगा. इसके ख़िलाफ़ हम लोग अदालत भी जाएंगे. जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध समाजसेवी और बी.टी.एम.सी. के पूर्व सचिव द्वारिको सुंदरानी ने कहा है कि वर्तमान प्रबंधन ऐक्ट में क्या कमी है. प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु, प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद तथा प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्री कृष्ण सिंह ने काफ़ी सोच–समझ कर उसे बनाया था. बदलाव करने से सिर्फ़ विवाद होगा. ऑल इंडिया भिक्खु संघ के कोषाध्यक्ष प्रज्ञादीप ने कहा है कि मंदिर के प्रबंधन ऐक्ट में बदलाव करने के पीछे सरकार की मंशा बौद्ध सदस्यों की संख्या बढ़ानी थी. अध्यक्ष के लिए हिंदू या गैर हिंदू कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सरकार के ऐसे प्रयास से सिर्फ आपसी तनाव बढ़ेगा और सौहार्द का माहौल भी बिगड़ेगा. चकमा बौद्ध मोनिस्ट्री के प्रभारी भिक्खु प्रियपाल ने कहा है कि महाबोधि मंदिर का पूरा प्रबंधन बौद्धों के हाथ में सौंपने की मांग हैं. सिर्फ अध्यक्ष पद को गैर हिंदू कर देने से नुक़सान ज़्यादा होगा. नये विवाद को पैदा करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है. वैसे भी ऐक्ट में संशोधन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. युवा जनआंदोलन मोर्चा के प्रदेश संयोजक आर.एस. नागमणी ने कहा है कि महाबोधि मंदिर प्रबंधन ऐक्ट में सरकार हिंदुओं और बौद्धों की भावना को भड़काना चाह रही है. इस संशोधन से देश–दुनिया में बिहार की छवि और ख़राब होगी. ■

अपनी यात्रा के दौरान अन्ना जन लोकपाल के मसले पर जनता को सचेत करते रहे. पश्चिम से लेकर पूर्व तक क़रीब डेढ़ दर्जन जिलों (मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, फर्रूखाबाद, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, फ़ैज़ाबाद, सुल्तानपुर, बदलापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर) में जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने अलख जगाया. वह जिधर से भी गुजर रहे थे, जनता मतवालों की तरह उनके आगे–पीछे भाग रही थी.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

जनतंत्र यात्रा

अन्ना को जबरदस्त समर्थन

अपनी जनतंत्र यात्रा के पांचवे चरण में अन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार जन लोकपाल बिल के नाम पर धोख़ा कर रही है. आज तक जन लोकपाल जनता को नहीं मिल पाया है. अन्ना ने सरकार की वायदाख़िलाफ़ी से क्षुब्ध होकर दिसंबर–जनवरी में फिर से दिल्ली में आंदोलन की राह पकड़ने का ऐलान करके केंद्र सरकार को सावधान कर दिया है...

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की जनता राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार, घोटालों, आतंकवाद, बेरोजगारी, लालफीताशाही, राज्य और केंद्र सरकारों की जनविरोधी नीतियों सहित तमाम मुद्दों को लेकर त्राहिमाम कर रही है. नेताओं पर से यहां की जनता का विश्वास उठ गया है. वह राजनीति से हटकर अपने लिए नई उम्मीदें तलाश रही है. जनता को यह उम्मीदें कभी बाबा रामदेव में दिखाई देती है, तो कभी समाजसेवी अन्ना हजारे उसे लुभाने लगते हैं. अन्ना हजारे की सादगी और बेबाकी की तो पूरी दुनिया कायल हो गई है. उनके भीतर कोई महात्मा गांधी का अक्श देखता है, तो किसी को उनमें डॉ. राम मनोहर लोहिया और जय प्रकाश नारायण नज़र आते हैं. यही वजह थी कि अन्ना हजारे रिमझिम बारिश में 11 दिनों की जनतंत्र यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचे, तो जनता ने अन्ना का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. जनता ने अन्ना को आश्वस्त किया कि अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. यात्रा के पांचवे चरण में यूपी पधारे अन्ना इस बात से आहत दिखे कि सांसदों ने सेंस ऑफ हाउस के प्रस्ताव का भी सम्मान नहीं रखा. केंद्र सरकार जन लोकपाल बिल के नाम पर धोख़ा कर रही है. दो वर्ष का समय बीत गया है, लेकिन जन लोकपाल अभी तक जनता को नहीं मिल पाया है. अन्ना ने सरकार की वादाख़िलाफ़ी से क्षुब्ध होकर कुछ माह बाद (दिसंबर–जनवरी में) फिर से दिल्ली में आंदोलन की राह पकड़ने का ऐलान करके केंद्र सरकार को एलर्ट कर दिया.

अपनी यात्रा के दौरान अन्ना जन लोकपाल के मसले पर जनता को सचेत करते रहे. दूसरी तरफ 2014 के लोकसभा चुनाव में चरित्रवान उम्मीदवारों को जिताने की मुहिम को भी अन्ना ने ख़ूब उछाला. पश्चिम से लेकर पूर्व तक क़रीब डेढ़ दर्जन जिलों (मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, फर्रूखाबाद, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, फ़ैज़ाबाद, सुल्तानपुर, बदलापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर) में जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने अलख जगाया. वह जिधर से भी गुजर रहे थे, जनता मतवालों की तरह उनके आगे–पीछे भाग रही थी. न बारिश उनके मंसूबों पर पानी फेर पाई, न ही आग उगलते हुए सूर्य देवता उनकी राह में व्यवधान खड़ा कर पाए. कोई अन्ना का चेहरा देखना चाहता था, तो कोई उनकी ललकार सुनना चाहता था. कई जगह तो अन्ना को जनता के दबाव में आकर जनसभा करनी पड़ी. सड़कों पर नौजवान उनकी फोटो लेने के लिए होड़ लगाए हुए थे. अन्ना कभी अपने रथ के भीतर चले जाते, तो कभी बाहर आकर ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने लगते. यह नजारा क़रीब–क़रीब पूरी यात्रा में दिखाई दिया. अन्ना के संघर्ष में बच्चे, बूढ़े और जवान, सभी अपनी तरफ़ से कुछ न कुछ आहूति देना चाहते थे. कोई तन से सेवा कर रहा था, तो कोई धन से मदद कर रहा था. अन्ना को जनतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है. अन्ना चाहते तो किसी पूंजीपति से मदद ले सकते थे, लेकिन वह जनता के बीच झोली फैला कर मदद मांगना ज़्यादा बेहतर समझते हैं. यही वजह थी कि जनसभा के दौरान चादर फैला कर चंदा मांगा जाता, तो दानपात्र भी लोगों के बीच घुमाया जा रहा था. लोग श्रद्धाभाव से योगदान दे रहे थे.

अन्ना की जनतंत्र यात्रा का आगाज यूपी के मुरादाबाद से हुआ. भाजपा और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों से दूरी बना कर चल रहे अन्ना यात्रा के दौरान संविधान के साथ हो रहे खिलवाड़ को मुद्दा बनाते रहे. उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा संविधान यह इजाजत नहीं देता है कि कोई भी पार्टी या पक्ष जनतंत्र पर अतिक्रमण करे, लेकिन संविधान को दरकिनार कर ऐसा किया गया. अन्ना जगह–जगह जनता को बताते रहे कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पक्ष या पार्टियां चुनाव लड़ें, सत्ता हासिल करें और देश का राजकाज पक्ष–पार्टियों द्वारा चलाया जाए. राजनीतिक दलों के संविधान के खिलाफ चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए समाजसेवी अन्ना ने देश में फैले भ्रष्टाचार, लूट–पाट, गुंडागर्दी, दहशत और आतंकवाद के लिए राजनीतिक दलों को ज़िम्मेदार ठहराते हुए इतना ही कहा कि आज़ादी के 66 वर्षों के बाद जनता सवाल कर रही है कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद बस फर्क इतना हुआ है कि गोरे चले गए और काले आ गए. जनता अगर जागरूक हो जाए, तो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन से बहुत बड़ी ताक़त का निर्माण होगी. यह ऐसी ताक़त होगी, जो देश के भ्रष्ट, गुंडे, लुटेरों की सरकार को उखाड़ फेंकेगी. पार्टी तंत्र जनतंत्र पर हावी हो गया है. उन्होंने कहा कि जनता यह भूल गई कि राज्य विधानसभा और संसद की अपेक्षा जन संसद सर्वोपरी है. उनका स्थान सबसे ऊंचा है.

बात अन्ना की जनतंत्र यात्रा के प्रभाव कि की जाए, तो उनको जगह–जगह व्यापक समर्थन मिल रहा है. उनकी बातों को जनता गंभीरता से सुन रही है. ओजस्वी अन्ना सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जातिगत रैलियों पर रोक के फ़ैसले को अहम बताते हुए अन्ना पूरे देश में इस फ़ैसले को लागू करने के पक्षधर बने. मुरादाबाद में उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी सांप्रदायिक हैं, तो रामपुर में चीनी घुसपैठ के प्रति उनकी नाराज़गी सामने आई. बरेली में अन्ना को जहां सभा करना था, वहां की लाइट ही ग़ायब हो गई. अन्ना ने यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए देश के मौजूदा हालात पर दुख व्यक्त किया, तो वह इस बात से भी नाराज़ दिखे कि कुछ सांसदों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मोदी को वीजा नहीं देने की मांग की थी. उनका कहना था कि देश के आंतरिक मामले बाहर नहीं जाने चाहिए. अन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव सीधे कराए जाने की वकालत भी की. फर्रूखाबाद पहुंच कर उन्होंने मोदी और राहुल दोनों को ही प्रधानमंत्री पद के अयोग्य क़रार दे दिया. यहां बारिश की वहज से उनकी जनसभा नहीं हो पाई, तो उन्होंने पूरे शहर में जनतंत्र यात्रा को घुमाकर लोगों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराया. शाहजहांपुर में उन्होंने अपने संघर्ष को आज़ादी की दूसरी लड़ाई क़रार देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र को चुनाव से पहले जन लोकपाल लाना पड़ेगा, अन्यथा सत्ता से जाना होगा. सीतापुर में अन्ना ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधा. अन्ना अपनी यात्रा के दौरान जगह–जगह जोर देते रहे कि देहातों के सर्वांगीण विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है. अन्ना ने जनतंत्र की लड़ाई के लिए सदस्यता अभियान भी चला रखा है. करीब पचास हजार लोगों को वह जनतंत्र मोर्चा में शामिल कर चुके हैं. अन्ना के साथ समाजवादी चिंतक और निर्भिक पत्रकार संतोष भारतीय भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे. वह भी देश के ताजा हालात से दुखी दिखे. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यह अवैध लोगों की संसद है. उन्होंने जनता से आज़ादी की दूसरी लड़ाई का सेनानी बनने की अपील ली. ■

feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार, रुपये में गिरावट, खाद्य पदार्थों के मूल्यों में भारी बढ़ोत्तरी और साथ ही सरकार की ग़लत नीतियों ने भारत की आर्थिक स्थिति को बेहद ख़राब कर दिया है. सरकार जिस प्रकार अपनी नाक़ामियां छिपाने का प्रयास कर रही है, इससे तो यही कहा जा सकता है कि यह सरकार ग़रीबों को सरकारी योजनाओं से वंचित करने का षड्यंत्र कर रही है.

थाली पर सियासत

योजना आयोग ने 27 और 33 रुपये से अधिक ख़र्च करने वाले लोगों को अति निर्धन की श्रेणी से बाहर रखा है. देश के अकर्मण्य नेता भी 5 और 12 रुपये में दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में भर पेट खाना मिलने की बात कह रहे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि 2014 के चुनाव से पूर्व यूपीए सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड सुधारना चाहती है और इसी चक्कर में मूल तथ्यों को छिपाते हुए वह भ्रमित रिपोर्ट के द्वारा ग़रीबों के साथ नया खेल खेल रही है...

वसीम राशिद

करमतोड़ महंगाई से आम जनता त्रस्त है और लगभग पूरे भारत का यही हाल है. ऐसी स्थिति में यह कहना कि आप 5 रुपये में दिल्ली या 12 रुपये में मुंबई जैसे शहर में पेट भर खाना खा सकते हैं, तो निश्चित रूप से यह गरीबों के साथ भद्दा मज़ाक लगेगा. रशीद मसूद और राजबब्बर, दोनों ही कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं. ज़ाहिर है, अगर दोनों को योजना आयोग की रिपोर्ट को उचित बताने के लिए चापलूसी करनी पड़े, तो वे करेंगे. भले ही वह भोंडापन लगे. सवाल यह नहीं है कि मुंबई और दिल्ली में 5 और 12 रुपये में खाना मिलता है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि योजना आयोग द्वारा भारत की ग़रीब जनता का इस तरह मज़ाक उड़ाना, यह इशारा करता है कि 2014 के चुनाव से पूर्व यूपीए सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड सुधारना चाहती है और इसी चक्कर में मूल तथ्यों को छिपाते हुए वह भ्रमित रिपोर्ट के द्वारा ग़रीबों के साथ नया खेल खेल रही है. अब सही क्या है और ग़लत क्या है, इससे पहले एक बार इस पर अवश्य नज़र डाल लें कि आख़िर योजना आयोग ने कहा क्या है?

आयोग के अनुसार, 2011–12 में ग़रीबी में उल्लेखनीय कमी आई है. हाल के आंकड़ों के अनुसार, देश में अब ग़रीबों की संख्या 27 करोड़ है. मतलब हर पांच में से एक शहरी ग़रीबी स्तर से नीचे जीवन–यापन करता है. इन आंकड़ों में आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये और नगरों में 33 रुपये से अधिक ख़र्च करने वाले लोगों को अति निर्धन की श्रेणी में नहीं रखा है. आयोग ने ग़रीबी स्तर को मापने के लिए तेंदुलकर फॉर्मूले का प्रयोग किया है. हालांकि सरकार ने ग़रीबी स्तर के लिए जून 2012 में प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार समिति के चेयरमैन रंगराजन के नेतृत्व में एक विशेष समूह गठित किया था, लेकिन सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए साल 2014 के मध्य तक पेश होने वाली इस रिपोर्ट का इंतज़ार करना उचित नहीं समझा और जल्दबाज़ी दिखाते हुए तेंदुलकर प्रक्रिया की बुनियाद पर नये आंकड़े देकर पूरे देश को चौंका दिया. ग़रीब तो ग़रीब, मध्यम वर्ग भी इन आंकड़ों को देखकर भौंचक्का रह गया. अजीब विडंबना तो यह है कि 27 और 33 रुपये, जिसमें इस दौर में एक फुटपाथ पर रहने वाला या रिक्शा चलाने वाला भी पेट नहीं भर सकता, उसे ग़रीबी सीमा से बाहर रखा गया है. 816 रुपये मासिक गांव में और एक हज़ार रुपये मासिक नगर में कमाने वाले कैसे ग़रीबी सीमा से ऊपर उठ गए, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है. पिछले पांच सालों का अवलोकन करें, तो ग़रीबी तो दूर की बात है, मंहगाई में इतनी बढ़ोत्तरी हो चुकी है कि मध्यम वर्ग तो परेशान है ही, अमीर वर्ग भी अब परेशानी महसूस करने लगा है. पेट्रोल, डीज़ल के बढ़ते दामों ने तमाम पदार्थों के दाम बढ़ा दिए हैं. घर में रोटी तो मुश्किल हो ही गई है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई और शादी–ब्याह के ख़र्च भी मध्यम और अमीर वर्ग के लिए मुश्किल हो गए हैं. जिनके पास अंधी कमाई है, जिनके पास काला धन है, राजनीतिज्ञों, ऊंचे पदों पर आसीन सरकारी नौकरीपेशों, भ्रष्टाचारी और बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों को छोड़ दिया जाए, तो साधारण वर्ग महंगाई से त्रस्त है. भारत की ग़रीब जनता का पैसा तो यूपीए सरकार ने घोटालों में लगा दिया. अरबों–खरबों के घोटाले ऐसे हुए कि इन घोटालों की रक़म की गिनती लिखना हम भूल जाएं.

भ्रष्टाचार, रुपये में गिरावट, खाद्य पदार्थों के मूल्यों में भारी बढ़ोत्तरी और साथ ही सरकार की ग़लत नीतियों ने भारत की आर्थिक स्थिति को बेहद ख़राब कर दिया है. ज़ाहिर है, इसका असर प्रत्यक्ष रूप से ग़रीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है. सरकार जिस प्रकार अपनी नाक़ामियां छिपाने का प्रयास कर रही है, इससे तो यही कहा जा सकता है कि यह सरकार ग़रीबों को सरकारी योजनाओं से वंचित करने का षड़यंत्र कर रही है. इस बयान पर बहुत बहस हुई और अधिकतर की यही राय थी कि सरकार सिर्फ और सिर्फ़ तथ्यों को छिपाते हुए 2014 के चुनाव की तैयारी कर रही है.

ज़ाहिर है कि विपक्ष सरकार के विरुद्ध जाएगी, लेकिन कांग्रेस के अपने कुछ राजनीतिज्ञों के पास इसका जवाब नहीं था कि आख़िर किस बुनियाद पर यह आंकड़े दिए गए हैं. भाजपा नेता तो इसके लिए सरकार को खुला चैलेंज कर रहे हैं कि आख़िर कोई भी प्रतिदिन 34 रुपये पर कैसे ज़िंदा रह सकता है. भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि यह एक षड़यंत्र है, ताकि ग़रीबों को ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की योजनाओं से वंचित किया जाए. भाजपा का सवाल है कि आख़िर कोई व्यक्ति 34 रुपये में कैसे पेट भर सकता है. इसका जवाब यही हो सकता है कि संसद की कैंटीन में 18 रुपये की थाली मिलती है, लेकिन क्या आम आदमी का यहां से गुज़र हो सकता है. आम आदमी तो संसद के क़रीब भी नहीं फटक सकता. यानी सबसे अधिक ग़रीब बेचारे नेता हैं. लाखों रुपये महीना कमाने वाले ये नेता हर प्रकार की सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं. ऐसे में आम आदमी के दुख–दर्द का इन भ्रष्ट नेताओं को कैसे पता होगा. दूसरी तरफ़ ग़रीब आदमी मूल सुविधाओं से भी वंचित है. इसके लिए बिजली, पानी, अनाज, दालें, सब्ज़ियां और शिक्षा सब कुछ इतना मंहगा है कि इसकी कमर ही टूट गई है.

अगर हम 20 मार्च, 2012 की रिपोर्ट पर गौर करें, तो इसके अनुसार 2004 से 2012 के बीच पांच करोड़ लोगों को ग़रीबी रेखा से बाहर निकालने की बात उचित नहीं ठहराई जा सकती है. 2011 में भी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दायर हलफ़नामे में कहा था कि 32 रुपये प्रतिदिन कमाई की क्षमता रखने वालों को अति निर्धन की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता.

इस समय सरकार ने सिविल सोसाइटी और राजनीतिक पार्टियों के दबाव के बाद यह आश्वासन दिया था कि ग़रीबों को चिन्हित करके सच्चाई को सामने लाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन आज सरकार फिर वही राग अलाप रही है. मनरेगा जैसी रोज़गार योजना में अगर हर महीने कोई व्यक्ति दस दिन का भी रोज़गार प्राप्त कर ले, तो ग़रीबी रेखा से बाहर निकल जाएगा. मूर्खता की बात यह है कि 2 साल पहले यह पैमाना 26 व 32 और दो साल बाद 27 और 34 रुपये हो गई. केवल एक या दो रुपये की बढ़ोत्तरी पर कोई ग़रीबी रेखा से बाहर कैसे निकल सकता है. क्या किसी को यह नहीं मालूम है कि 2 सालों में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है. दो साल पहले इसी फ़ॉर्मूले को लेकर सरकार को जिल्लत उठानी पड़ी थी. अब पुन: सरकार केवल एक रुपये के अंतर से वही बात क्यों कह रही है. एक बड़ा सवाल यह भी है कि ये नीतियां बनाने वाले अर्थशास्त्री क्या इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि गांव में रहने वाला 5 लोगों का परिवार हर दिन 135 रुपये और हर महीने 4080 रुपये में कैसे गुज़ारा करेगा और शहरों में रहने वाला 5 लोगों का परिवार 5 हज़ार रुपये महीना पर गुज़ारा कर लेगा, तो यह निश्चित ही आंख बंद कर किया जाने वाला सर्वे है और स्वयं मनमोहन सिंह की साख इसे लेकर दांव पर लगी है. बड़ा सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री स्वयं एक अर्थशास्त्री होकर ऐसे आंकड़े कैसे दे सकते हैं?

इस रिपोर्ट में ग़रीबों की संख्या में सबसे अधिक कमी बिहार और उड़ीसा में आई है, जबकि ग़रीबी की दृष्टि से सबसे अधिक ख़राब स्थिति छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में है. गोवा में केवल 5 प्रतिशत लोग ग़रीबी रेखा से नीचे रहते हैं. इसके अलावा केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पांडिचेरी में ग़रीबों की संख्या 10 प्रतिशत से कम हुई है. इन सभी राज्यों से तुलना की जाए, तो यूपी, बिहार, बंगाल में ग़रीबी तेज़ी से बढ़ी है. दिल्ली जैसे शहर में तो 33 रुपये में पेट भरना असंभव है, लेकिन इन राज्यों में एक फुटपाथ पर सोने वाला साधारण मज़दूर या कोई भीख मांगने वाला फ़क़ीर भी 33 रुपये में पेट नहीं भर सकता.

आश्चर्य की बात तो यह है कि 2011–12 में गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति बहुत ख़राब थी. वाइज़न ने कहा था कि मुसलमानों में ग़रीबी और पिछड़ेपन की दर सबसे अधिक है. विशेष रूप से असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात के गांव, वाइज़न के अनुसार, सामूहिक रूप से मज़दूर वर्ग के लोग अधिक संख्या में ग़रीबी रेखा से नीचे हैं. 50 प्रतिशत खेती में लगे हुए मज़दूर और 40 प्रतिशत दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले मज़दूर इस श्रेणी में आते हैं. आज जब योजना आयोग अपनी 2 साल पुरानी रिपोर्ट पेश कर रहा है, तो वाइज़न की इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि नि:संदेह भारत के ख़ात्मे के लिए काफी काम किया है, लेकिन गांव–देहातों में मज़दूरों और किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय है और उन्हें दो वक़्त की रोटी नसीब नहीं.

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री विद्वान अमर्त्य सेन कुछ महीने पहले दिल्ली के आईआईटी हॉल में आयोजित एक प्रोग्राम में आए थे. इसमें उन्होंने भारत सरकार के ग़रीबों में सब्सिडी आवंटित करने की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पैसे देने की यह योजना ग़रीबों को अनाज उपलब्ध नहीं कराती. भ्रष्टाचार से बचने के लिए ग़रीबों के नक़द सब्सिडी की यह योजना और भी ख़तरनाक है, क्योंकि कौन ग़रीब है कौन नहीं, यह साबित करने में ही बहुत भ्रष्टाचार है. जो लोग इन ग़रीबों को चिन्हित करेंगे, वह कितने ईमानदार हैं, इस पर भी सवाल उठाया जा सकता है. योजना आयोग के अनुसार, 2011–12 में गावों में कुल आबादी का 25.7 प्रतिशत ग़रीब थे और शहरों में 13.7 प्रतिशत. आयोग ऐसा मानता है कि हर साल 2 प्रतिशत से अधिक की दर से ग़रीबी कम हो रही है. नये आंकड़ों में 2004–2005 से 2011–12 के सात सालों में ग़रीबी घटने की दर 3 गुना कम हो गई है.

यह आंकड़े केवल सरकार की चाल हैं. सरकार को रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए था. अगर विशेषज्ञों की मानें, तो ग़रीबी रेखा का ग्राफ़ कुछ इस प्रकार बनता है, जिसे दिखाया नहीं गया है.

वर्ष	गांव	शहर	प्रतिशत गांव में	शहर में
1993–94	8 रुपये	10 रुपये	31.8	50.1
2004–05	12 रुपये	18 रुपये	25.7	41.8
2009–10	22 रुपये	28 रुपये	20.9	33.8
2011–12	27 रुपये	33 रुपये	13.7	25.7

आंकड़े वर्तमान में ग़रीबी रेखा की जो भी तस्वीर पेश कर रहे हों, लेकिन अगर हम दिल्ली और सभी राज्यों की समीक्षा करें, तो आज भी हमें ग्रामीण जीवन बहुत ही पिछड़ी नज़र आती है. पांच रुपये, 27 रुपये या कम से कम 100 रुपये में भी एक दिन का ख़र्च नहीं निकल सकता और शहरों में तो यह और भी अधिक है. यहां आटा–दाल का भाव देख कर भी यह साबित किया जा सकता है कि भारत की स्थिति अब भी अत्यंत ख़राब है. महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी पिछले 10 सालों में और अधिक बढ़ी है, घटी नहीं है. हुआ यह है कि ग़रीब और ग़रीब और अमीर और अमीर होता गया.

वृंदा करात के बयान से हम इस पूरी चर्चा का अंत कर सकते हैं कि ग़रीबी के आंकड़े जख़्मों पर नमक छिड़कने के लिए हैं, न कि उनसे हमदर्दी जताने के लिए. सवाल यह उठता है कि क्या राजबब्बर या रशीद मसूद जैसे लोग ग़रीबों के हमदर्द हो सकते हैं? हमारे हिसाब से तो संसद की कैंटीन को ग़रीबों के लिए खोल देना चाहिए. ऐसी सरकार भला कैसे ग़रीबों की हमदर्द हो सकती है और कैसे ग़रीबी के स्तर को माप सकती है, यह गंभीर सवाल है.■

feedback@chauthiduniya.com

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री विद्वान अमर्त्य सेन कुछ महीने पहले दिल्ली के आईआईटी हॉल में आयोजित एक प्रोग्राम में आए थे. इसमें उन्होंने भारत सरकार के ग़रीबों में सब्सिडी आवंटित करने की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पैसे देने की यह योजना ग़रीबों को अनाज उपलब्ध नहीं कराती. भ्रष्टाचार से बचने के लिए ग़रीबों के नक़द सब्सिडी की यह योजना और भी ख़तरनाक है, क्योंकि कौन ग़रीब है कौन नहीं, यह साबित करने में ही बहुत भ्रष्टाचार है. जो लोग इन ग़रीबों को चिन्हित करेंगे, वह कितने ईमानदार हैं, इस पर भी सवाल उठाया जा सकता है.

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

मौजूदा समय में देश की राजनीतिक दशा बेहद ख़राब है. चालू खाते पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है. मुझे याद है, जब 1991 में चालू खाता घाटा लगभग 3 प्रतिशत के क़रीब था और देश पूरी तरह से वित्तीय संकट से घिर गया था. अब यह 4.8 प्रतिशत है. बेशक हमारे पास विदेशी मुद्रा विनिमय कोष है. इसलिए अभी 1991 जैसा संकट नहीं आया है, लेकिन स्थितियां विपरीत भी हो सकती हैं, इसलिए ऐसे माहौल में एक परिपक्व गवर्नेंस की ज़रूरत है.

देश को बेहतर राजनीतिक नेतृत्व की ज़रूरत है

लंबे वक्त के बाद आख़िरकार कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना मामले पर कोई निर्णय लिया है, लेकिन अभी भी इसमें कई पेचीदगियां हैं. मसलन, हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए राजधानी घोषित करने का फ़ैसला बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता. चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की सीमा पर स्थित है, जबकि हैदराबाद गठित होने वाले राज्य तेलंगाना के बिल्कुल केंद्र में होगा और शेष आंध्र प्रदेश राज्य के लिए तक़रीबन दूसरी सीमा पर, जो कि बेहद असुविधाजनक होगा. हालांकि यह तय किया गया है कि हैदराबाद को केवल 10 वर्ष के लिए ही राजधानी बनाया जाएगा, लेकिन बेहतर तो यह होता कि स्थाई व्यवस्था करते हुए कुरनूल या किसी भी अन्य शहर को, जिसे मुफीद समझा जाता, राजधानी घोषित करते.

वास्तव में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाली सरकार ने तीन राज्यों झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का गठन किया था, उसी दौर में सरकार को तेलंगाना और विदर्भ का भी गठन कर देना चाहिए था, जबकि तेलंगाना और विदर्भ दोनों के अलग राज्य के गठन की मांग बहुत पुरानी है. यह मांग तभी से उठ रही है, जब राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत हुई थी, लेकिन एनडीए सरकार ने इसे अनदेखा किया.

अब कई वर्षों के अंतराल के बाद मौजूदा सरकार तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा देने के निर्णय पर पहुंची है, लेकिन इसके पीछे भी एक गुणा–भाग है. पार्टी ने अलग राज्य का गठन चुनावी लाभ लेने के मद्देनज़र किया है. हालांकि यह बेहद अदूरदर्शी सोच है. कोई भी दल किसी राज्य के गठन को आधार बना कर चुनाव नहीं जीत सकता. हां, संभव है कि किसी एक चुनाव में आपको इसका फ़ायदा फौरी तौर पर मिल जाए, लेकिन किसी राज्य के गठन को केवल चुनावी फ़ायदे के तौर पर देखा जाए, तो यह बेहद अफसोसजनक है. जब आपकी भूमिका किसी देश के भाग्यविधाता के तौर पर है, तो आप केवल एक चुनाव के बारे में कैसे सोच सकते हैं?

10–20 सीटों के इधर–उधर होने से क्या फर्क पड़ता है? राज्य के गठन को चुनावी फ़ायदे के तौर पर न लेकर, इस आधार पर लेना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की जनता के लिए क्या बेहतर होगा. अलगाव के बाद दोनों ही राज्य बेहतरी के रास्ते पर हों, यह सोच रखनी चाहिए. यह बात सही है कि छोटे राज्यों में बेहतर विकास हुआ है, इसलिए छोटे राज्यों के गठन का पक्ष मजबूत है, लेकिन फिर राज्यों का गठन इस तरह से नहीं हो सकता कि कोई भानुमती का पिटारा खोल दिया गया और उसमें से छोटे–छोटे राज्य निकाले जा रहे हैं. गोवा का उदाहरण लीजिए, पहली बार या यूं कहें कि लंबे अर्से के बाद वहां एक स्थायी सरकार का गठन हो पाया है. अन्यथा मतदाता हैं 12 लाख और सीटें हैं 40. इसलिए किसी भी विधायक को सीट जीतने के लिए केवल कुछ हज़ार मतों की ज़रूरत होती है. इस तरह से यह बेहद असंतुष्ट करने वाली व्यवस्था है. तेलंगाना के गठन की उम्मीद के बाद अब विदर्भ के गठन की मांग भी और ज़ोर पकड़ेगी. उधर, उध्य प्रदेश में मायावती अपने पिछले कार्यकाल में पहले ही इस आशय का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर चुकी हैं. जाहिर–सी बात है कि इस मांग पर प्राथमिकता के साथ गौर किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि उसे एक शासन के एक केंद्र से संचालित करना कठिन है. इतने बड़े राज्य में ज़िलों और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज्यादा है. उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग तर्कसंगत भी है. पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थितियां एकदम अलग हैं, जबकि राज्य के मध्यभाग की ओर चलें, तो वहां बुंदेलखंड है, उसकी भी स्थितियां बिल्कुल अलग हैं. यहां तक कि इस भाग का कुछ हिस्सा दूसरे राज्य, मध्य प्रदेश में भी है. भारतीय जनता पार्टी का एक पक्ष यहां भी एक अलग राज्य की मांग कर रहा है. हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो वास्तविक रूप में भानुमती का पिटारा खुल जाएगा और हर कोई एक नये राज्य की मांग करने लगेगा. होना तो यह चाहिए कि इस मसले को लेकर एक न्यायिक आयोग का गठन हो, जो कि इसे अपने संज्ञान में ले और अपने विवेक के आधार पर उत्तर प्रदेश से अलग होकर किसी राज्य और विदर्भ के गठन का आधार तैयार करे.

अगला विषय, जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है, वह यह कि संसद के इस सत्र में कांग्रेस की मंशा क्या है, यह तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन यह तो तय है कि कांग्रेस इसी सत्र में खाद्य सुरक्षा बिल पास कराना चाहेगी, लेकिन यह भी है कि कई सारे ऐसे विधेयक हैं, जो पहले ही लोकसभा से पास हो चुके हैं और उनके केवल राज्यसभा से पास होने की औपचारिकता बाक़ी है. संभव है कि यह सब केवल कुछ ही घंटों में हो जाए. कांग्रेस को तय करना चाहिए कि जिन विधेयकों पर किसी तरह का विवाद नहीं है, उन्हें पास होने दें और जिन विधेयकों पर विवाद है, जैसे खाद्य सुरक्षा विधेयक, उन पर बहस होनी चाहिए. उसमें संशोधन होने चाहिए और बहुमत से जो पारित हो, उसे स्वीकार करना चाहिए. सही मायने में यही लोकतंत्र है. भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह है कि जिन विधेयकों के पारित होने की संभावना कम है, उन पर बहस नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि संसद के काम में बाधा आएगी और सदन स्थगित हो जाएगा. हालांकि यह एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका नहीं है. लोगों की प्रतिक्रियाओं पर गौर कीजिए. भ्रष्टाचार और घोटालों के चलते देश की जनता कांग्रेस से नाराज़ है. लोगों में ऐसी ही गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक चेहरे से भी है. उनके नेता अयोध्या जाते हैं और कहते हैं कि हम मंदिर यहीं बनाएंगे. अब, जब यह मामला कोर्ट में है, तो बिना कोर्ट का निर्णय आए कोई भी उस जगह पर मंदिर नहीं बना सकता, लेकिन राजनीतिक पार्टियां मुगालते में हैं कि वे इन मुद्दों को उछालकर मतदाताओं को अपने पक्ष में कर लेंगी. पब्लिक सब समझती है, इसलिए इन मुद्दों को उछालकर पार्टियों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है. मुझे लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अब केवल 7–8 महीने ही बचे हैं, इसलिए देश के दोनों राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे साथ आएं और कुछ मुद्दों का सर्वसम्मति से हल खोजें, जो कि राजनीतिक न हों. मौजूदा समय में देश की राजनीतिक दशा बेहद ख़राब है. चालू खाते पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है. मुझे याद है जब 1991 में चालू खाता घाटा लगभग 3 प्रतिशत के क़रीब था और देश पूरी तरह से वित्तीय संकट से घिर गया था. अब यह 4.8 प्रतिशत है. बेशक हमारे पास विदेशी मुद्रा विनिमय कोष है. इसलिए अभी 1991 जैसा संकट नहीं आया है, लेकिन स्थितियां तेजी से विपरीत भी हो सकती हैं. इसलिए ऐसे माहौल में एक परिपक्व गवर्नेंस की ज़रूरत है. हां, यह ज़रूर है कि इस गवर्नेंस का मतलब केवल उन संदर्भों में न हो, जैसा गुजरात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे हालात में देश के हित के लिए कुछ गंभीर निर्णय लेने की ज़रूरत है.

ऐसे दौर में देश के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी भी उनके प्रति लोगों की विश्वसनीयता है. बेशक उनकी पार्टी भ्रष्टाचार और घोटालों में आकंठ डूबी हुई है, लेकिन अभी भी लोगों में यह भरोसा है कि इस सरकार में वही एक व्यक्ति हैं, जो जितना आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उतना ही राजनीतिक रूप से शिष्ट भी. समय की मांग है कि प्रधानमंत्री अब हस्तक्षेप करें. हो सकता है कि उनकी पार्टी को नागवार गुजरे, लेकिन यह देश के लिए सोचने का वक्त है, पार्टी के लिए नहीं. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व बेहतर नहीं होता, तो सशस्त्र सेनाएं हतोत्साहित होंगी. इस देश में लोकतांत्रिक बदलाव होते रहे हैं. अलग–अलग सरकारों में कई बार बेहतर और बदतर स्थितियां देखने को मिली हैं, लेकिन आज जैसा हो रहा है, भगवान न करे कि ऐसा अगले चुनाव के बाद भी हो. अगर आप सशस्त्र सेनाओं को हतोत्साहित करेंगे, तो ऐसी परेशानी में पड़ जाएंगे, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्पादक को न्याय मिले

ठाकुर दास बंग

कुछ वस्तुओं के बारे में यह भी माना जा सकता है कि उनकी क़ीमत कुछ बढ़ भी सकती है, लेकिन इसका निष्कर्ष यह नहीं हो सकता कि ग्रामीण उत्पाद को न्याय नहीं मिला. महंगाई बढ़ने के कारण सरकारी कर्मचारियों का महंगाई–भत्ता बढ़ाया जाता है या सरकारी कर बढ़ जाने से महंगाई बढ़ती है. उस समय दलील नहीं दी जाती है कि महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए या सरकार अवश्यक ख़र्च न करे. इसी प्रकार उत्पादक को न्याय मिलना चाहिए. व्यापारियों का एवं अन्य उच्च वर्गों का पंचसितारा होटलों, दूरदर्शन, एशियाड या निर्गुट–सम्मेलन पर होने वाला अनाप–शनाप ख़र्च एवं विलास कम किया जाना चाहिए. ऐसा होने से ग्रामीणों के पक्के माल की ओर सेवाओं की क़ीमतें घटेंगी. क़ीमतें घट जाने पर ग्रामीण उत्पादक का लागत–ख़र्च कम होगा. ऐसा होने पर आज की क़ीमतों में ही किसान की लागत–ख़र्च जितना मूल्य मिल जाएगा. जो भी हो, उत्पादक को लागत–ख़र्च जितना दाम न मिले, यह दलील नहीं हो सकती.

अनाज और कच्चा माल महंगा होने के कारण हो सकता है कि उच्च मध्यम वर्ग और अमीरों की महिलाओं को 50 साड़ियों की बजाय 40 साड़ियों से काम चलाना पड़े या रोज मिठाई और 10–12 वस्तुएं भोजन में रखने की बजाय 5–7 चीजों से भोजन करना पड़े. इन सभी चीजों से ज़्यादा फर्क उनके जीवन में नहीं पड़ेगा. निम्न मध्यम वर्ग और नगरों के संगठित मजदूर को रोज सिनेमा की बजाय हफ्ते में दो बार सिनेमा इसकी बजाय देखना पड़े या व्यसनों की मात्रा कुछ कम करनी पड़े. किसी के भोजन–वस्त्र में या आवश्यकताओं में अनाज महंगा होने से या कच्चे माल की क़ीमत थोड़ी बढ़ जाने से कोई कमी नहीं आएगी. माल के दाम के साथ–साथ ग्रामीणों की मजदूरी बढ़ेगी, यह हमने पहले देखा ही है. ऐसी परिस्थिति में बढ़े हुए अनाज की क़ीमतों से ग्रामीण मजदूर या कारीगर के जीवन–स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कई स्थानों पर कृषि– कार्य के लिए मजदूरी का एक हिस्सा मजदूर को अनाज में दिया जाता है, जो सैकड़ों वर्षों से स्थिर है. अत: अनाज का भाव बढ़ने पर भी उन्हें घाटा नहीं होगा.

सवाल पूछा जाता है कि जो छोटे किसान हैं और जिनके पास बाज़ार में बेचने लायक माल रहता ही नहीं, अपने परिवार के ख़र्च जितना ही माल जो पैदा करता है, उसे इस आंदोलन से क्या लाभ? ऐसे ही किसान की संख्या अधिक होने से यह आंदोलन बड़े किसानों का आंदोलन हो जाता है. यह तर्क सही नहीं है. आज हर छोटा किसान कोई न कोई नक़द फसल लगाता है और उसे अपने फसलों को बाज़ार में ले जाना पड़ता है. जो किसान केवल अनाज बोते हैं, मजबूरन उन्हें अपने अनाज सस्ते में बेचना पड़ता है और उसी अनाज को चार माह बाद वे किसान बढ़े दामों में ख़रीदते हैं. सवाल यह है कि आज हर किसान बेचता ही है, तो फिर वह सस्ते में, कम दाम में क्यों बेचे?

लागत मूल्य, देश भर के लिए कैसे तय किया जाए, यह सवाल पूछा जाता है. लागत मूल्य तय करना बहुत पेचीदा और कठिन सवाल है. ज़मीन की किस्म, बारिश, खेती की कुशलता आदि कई बातों पर लागत–ख़र्च निर्भर करेगा, अत: वह भिन्न–भिन्न होगा. तब वाजिब मूल्य क्या हो? इसका उत्तर है कि उद्योग में भी यही सवाल लागू होता है. कारखाने में बने हुए माल का लागत–ख़र्च कारखाने का सुप्रबंध, पूंजी की सुलभता या अभाव, श्रमिकों की कुशलता, मालिक मजदूर– संबंध आदि कई बातों पर निर्भर करता है. तो भी उद्योग में उत्पादन का लागत–ख़र्च निकाला जाता है और उनका औसत निकालकर एवं अधिक से अधिक संख्या के कारखानों को, जो दर लागू होता हो, वह लागत ख़र्च मानकर उसके अधार पर बाज़ार में क़ीमत तय होती है या सरकार इसे ख्याल में रखकर मूल्य–नियंत्रण करती है. जो बात कारखानों पर लागू होती है, वही बात कृषि पर लागू होती है. ज़मीन की किस्म में फर्क ज़रूर रहेगा, लेकिन गांव से लेकर बाज़ार से या सड़क से, जो खेत नजदीक होगा, उसकी या अच्छी ज़मीन की क़ीमत ज़्यादा होगी. और इसलिए इस पूंजी पर सालाना ब्याज की रक़म अधिक आएगी, जो लागत–ख़र्च में शामिल रहेगी. ऐसी ज़मीन पर निराई, जोत, मंडी तक उपज को ले जाना आदि ख़र्च कम आएगा. दूसरी तरफ़, जो ज़मीन सड़क से या गांव से दूर होगी या कम पैदावार वाली होगी, उसकी क़ीमत कम होने से उस पर ब्याज कम होगा, लेकिन ऐसी ज़मीन पर निराई, जोत, मंडी में माल भेजने का व्यय आदि का ख़र्च अधिक आएगा. कुल मिलाकर दोनों ज़मीनों के बारे में लागत ख़र्च का अंतर हम सोचते हैं, उतना अधिक नहीं रहेगा. वैसे ही किसी एक क्षेत्र के 70 प्रतिशत ज़मीनों पर जो लागज ख़र्च मौजूद हो, वह लागत ख़र्च उस क्षेत्र के लिए सही माना जाए. ऐसी कुछ बातें ध्यान में रखकर लागत ख़र्च निकालना असंभव कार्य नहीं माना जाना चाहिए.

एक सवाल यह भी है कि किसान को वाजिब दाम मिलने से किसान की अमीरी और विषमता बढ़ेगी. यह सही नहीं है. हमने पहले देखा कि खेती घाटे का सौदा है. गांवों में अमीर दीखने वाले किसान खेती के कारण अमीर नहीं हैं. कृषि के अलावा दुकानदारी, साहूकारी, उद्योग, ठेकेदारी, डॉक्टरी, वकालत आदि पेशा यह उनकी अमीरी का कारण है. केवल खेती पर कोई 10 सालों में अमीर हुआ हो, यह अपवाद है, नियम नहीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

साथी हाथ बढ़ाना

उत्तराखंड में जल प्रलय के बाद पूरा संसार आज गहरी संवेदना व्यक्त कर रहा है, पर हमारी केन्द्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा मानने से हिचक रही है. इससे सरकार की उन परिवारों के प्रति उदासीनता का सहज अंजादा लगाया जा सकता है. अगर सरकार गंभीर होती, तो वह इस आपदा पर सियासत नहीं करती. सरकार को भ्रष्टाचार और लूट-पाट से फुर्सत हो, तब न वह इस ओर गंभीरता से सोचे. अरबों की लूट सरकार कर सकती है, लेकिन इतनी बड़ी आपदा पर करोड़ों नहीं खर्च कर सकती. उत्–राखंड की सरकार मारे गए लोगों का जो आंकड़ा पेश कर रही है, वह सैकड़ों में है, पर जान-माल का नुकसान उससे कई गुना ज्यादा है. पूरी दुनिया ने देखा और आपदा में फंसे लोगों ने भी देखा कि कैसे आपदा के बाद वहां बदइंतजामी फैली थी. वहां फंसे लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था. वह तो सेना और स्थानीय लोग थे, जो आगे बढ़कर आफत में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए. और तो और, राहत और बचाव कार्य में भी खूब सियासत की गई. आम आदमी से मदद मांगी जा रही है. चंदा-उगाही भी जोर-शोर से किया जा रहा है. जन सेवा का कार्यक्रम चल रहा है, उसके बावजूद भी जनता तक यह फायदा पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा है. अफसोस तो यह है कि स्वार्थी तत्वों का राहत के इस पैसे पर बुरी नजर है. सरकार राहत और बचाव कार्य के नाम पर दिखावा भर कर रही है. इन धार्मिक स्थलों के फिर से निर्माण में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. सबको दिल खोलकर इन कार्यों में सहयोग करना चाहिए. .

-राहुल, भागलपुर

सच्चा भारतीय बनना होगा

जुर्म को नज़रंदाज करना, जुर्म करने से भी बड़ा होता है. चुपचाप जुर्म होते देखते रहना और बेहद खामोशी से आगे बढ़ जाना, हमारे समाज में बढ़ते जा रहे लूट-खसोट, भष्ट्राचार तथा अपराध का प्रधान कारण है. देश का कानून तथा प्राशासन केवल कागज के पन्नों पर ही देखने को मिलता है. सही तरीके से नियम-कानून का पालन नहीं होता, जबकि नियम-कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए. कानून का पालन अगर सख्ती से होता, तो गुनहगार गुनाह करने से पहले हजारों बार सोचता, जबकि आलम यह है कि नेता या बड़े लोगों के अंदर से कानून का खौफ नहीं रहता, जिसके कारण वे गुनाह करने में एक बार भी नहीं सोचते. इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह होता है कि सामान्य लोगों या गरीब लोगों के नजर में कानून के प्रति सम्मान कम होता जा रहा है और ऐसे लोगों के जेहन में यह सोच घर करती जा रही है कि कानून बड़े लोगों का रखवाला है और यह छोटे लोगों को दंड देने के लिए बना है. दूसरी तरफ नेता केवल झूठे नारों एवं वादों के सहारे जनता को बरगलाते हैं. अगर वे मूलभूत समस्यायों के समाधान का प्रयास करते, तो जनता की यह स्थिति नहीं होती. हमारे नेताओं को सच्चा देशभक्त बन कर अपनी देश की सेवा करनी चाहिए. केवल झूठे नारों और वादों के सहारे आखिर यह देश कब तक चल सकता है. सच्चाई तो किसी न किसी दिन लोगों के सामने आ ही जाती है. अगर हम एक खुशहाल भारत देखना चाहते हैं, तो सभी लोगों को भारतीय बन कर सच्चे दिल से काम करना होगा, तभी सच्चे भारत का निर्माण संभव है. *-ईशान, मुजफ्फरपुर*

अन्ना को धर्म के चश्मे से न देखें

पिछले अंक में एक लेख पढ़ा, जिसका शीर्षक था अन्ना और मुसलमान. इस लेख में बहुत सारे मुस्लिम विद्धानों की राय भी छपी थी. सभी अन्ना के समर्थन में खड़े दिख रहे थे, लेकिन उनमें कुछ लोग अन्ना के विचारों को लेकर यह भी सवाल उठाया कि अन्ना मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार पर नहीं बोलते. बहरहाल, जो भी हो, मेरा यह मानना है कि अन्ना के आंदोलन को जाति या धर्म का रूप नहीं देना चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट और देश को तोड़ने वाली पार्टियां यही चाहती हैं कि देश इन मुद्दों में फंसा रहे और वे देश को लूटते रहें. अन्ना जिस मुद्दे को उठा कर यह लड़ाई लड़ रहे है, वह दूसरी आजादी से कम नहीं है. सच मायनों में यह एक आम हिंदुस्तानी का मुद्दा है. आज हमारे देश में न कोई ऐसा चेहरा है, न ही कोई ऐसा झंडा, जिसे देखकर लोग एक जगह एकत्रित हो सकें. अन्ना ने एक मंच के नीचे लोगों को लाकर यह कर दिखाया. उन्होंने लोगों को एहसास कराया कि उनका आंदोलन आम लोगों के लिए है. *-राजू, समस्तीपुर*

प्रधानमंत्री पद की मारामारी

पिछले अंक में मैंने एक लेख पढ़ा, जिसका शीर्षक था कांग्रेस से ज़्यादा भ्रष्ट है भाजपा. लेखक ने इस लेख में बड़ी बेबाकी और निर्भिकता के साथ बीजेपी की अन्दर की बात को बताया है, जो अन्य अख़बारों में नहीं दिखता. आज हमारे देश में समस्याओं की कमी नहीं है. अफसोस की बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए समस्या प्रधान मुद्दों का कोई महत्व नहीं हैं, बल्कि सभी यह सोचने में लगे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा. इस जद्दोजहद में पार्टियां दूसरे पर्टियों को नीचा दिखाने में लगी हैं. प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए पार्टी के अन्दर भी घमासान जारी है, जिसका बीजेपी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है. आज देश की दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी राहुल और मोदी गान में लगी हैं. इस गान में देश के विकास के मुद्दे गौण होते जा रहे हैं और इन पर व्यक्तिगत मुद्दे हावी होते जा रहे हैं. भारत के लोगों को सोचना होगा कि उसे राहुल–मोदी चाहिए या देश का विकास

-मोदस्सीर, मुंगेर

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

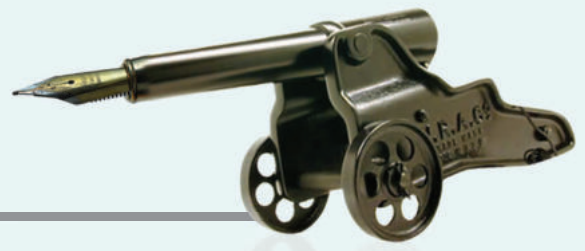

अब स्वतंत्रता दिवस हमें डराता है

तारीख 15 अगस्त, 1947– इस तारीख ने उस दौर के हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी थी, क्योंकि हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए थे. सपने थे, दुखों से निजात पाने की आकांक्षा थी. आंखों में नये हिंदुस्तान का सपना था और हर व्यक्ति यह मानकर चलने लगा था कि देश में अब घी–दूध की नदियां बहेंगी, क्योंकि सभी को उस वक्त देश के नेताओं पर भरोसा था. उन्हें यह अंदेशा नहीं था कि भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है?

तारीख 15 अगस्त, 2013–अब इस स्वतंत्रता दिवस पर बहुत कोशिश करने के बाद भी मन प्रफुल्लित नहीं हो पाता है. लालकिले पर भाषण सुनने की इच्छा नहीं होती. सरकारी विज्ञापनों को पढ़ना उबाऊ लगता है. कुल मिलाकर लगता यह है कि जैसे हम एक ऐसी अंधेरी सुरंग में चले गए हैं, जहां जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था. आज देश का कौन–सा तबका है, जो खुश है. मेहनतकश हों, किसान हों, छात्र हों, बड़ी–बड़ी डिग्रियां लिए हुए नौजवान हों, बिना डिग्री लिए हुए बेक़ार–बेरोज़गार हों, या फिर नौकरी में रहने वाले सरकारी कर्मचारी हों, कोई भी खुश नहीं है. उनसे बड़े तबकों को देखें, तो व्यापारी, उद्योगपति, बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग, कोई भी तो खुश नहीं है. हर किसी को लगता है कि कहीं कोई कमी है. इस कमी को दूर करने का उपाय किसी के पास नज़र नहीं आता.

अगर कोई खुश नज़र आता है, तो वह है राजनीतिक दलों के सर्वोच्च वर्ग के नेताओं की जमात. उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं है. वह चाहे सत्ता में हों या विपक्ष में, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान दिखाई देती है. उन्हें हारने का ग़म नहीं. हार भी उन्हें जीत जैसा मज़ा और उसमें हिस्सेदारी दोनों देती है.

लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता कतई खुश नहीं हैं, क्योंकि उनकी स्थिति अपने–अपने राजनीतिक दलों में दलाल जैसी हो गई है. अगर वे अपनी पार्टी के किसी सांसद, विधायक या मंत्री के पास खाली हाथ जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को साथ ले जाते हों, जो उन्हें कोई उपहार न दे सकता हो, तो वहां उनकी पूछ नहीं होती. टिकट मिलना तो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दूर की कौड़ी है. पहले टिकट परिवार के लोगों के लिए, उसके बाद टिकट नौकर, ड्राइवर और मुनीम के लिए और फिर जो जितने बड़े दाम में ख़रीद सके, उसके लिए टिकट उपलब्ध है. तभी तो राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह अनजाने में ख़ुलासा कर गए कि राज्यसभा की सीट की क़ीमत है तो 100 करोड़, लेकिन उन्हें 80 करोड़ में मिल गई.

बातों से सभी पलटते हैं, वीरेंद्र सिंह भी पलट गए, लेकिन वीरेंद्र राजनीति में ख़रीद–बिक्री का पर्दा हटा गए. क्या इसीलिए स्वतंत्रता की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी. क्या इसी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना बनाई थी, क्या इसलिए भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु या उससे पहले अशफाक़उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह व रामप्रसाद बिस्मिल जैसे कई अन्य वीर सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी.

मुझे लगता है कि जो लोग भी आजकल भगत सिंह सुखदेव या रामप्रसाद बिस्मिल का नाम लेते हैं, उन्हें ये राजनेता महान मूर्ख मानते हैं. उन्हें लगता है कि उनके दिमाग़ में कोई ख़राबी आ गई है या दिमाग़ का कोई कल–पुर्जा ढीला हो गया है, जो आज़ादी के शहीदों का नाम लेते घूम रहे हैं. मैंने अपने संवाददाताओं से एक सर्वे कराया, जिसमें ख़ुलासा हुआ कि किसी भी नेता के घर में भारत की आज़ादी के लिए शहीद हुए किसी भी बलिदानी का चित्र नहीं है. चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक़उल्ला, ठाकुर रोशन सिंह व रामप्रसाद बिस्मिल ऐसे नाम हैं, जिनके पीछे सैकड़ों की कतार है, जिन्होंने आज़ादी के लिए गोली खाई या फांसी का फंदा चूमा. मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर किसी सांसद से या मंत्री से आज़ादी की लड़ाई के बलिदानियों का नाम पूछें, तो उन्हें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा कोई तीसरा नाम शायद ही याद हो.

यह है 15 अगस्त, 1947 और 15 अगस्त, 2013 का फर्क. बेरोज़गारी ख़त्म करने की कोई योजना किसी सरकार या किसी दल के पास नहीं है. महंगाई समाप्त की नहीं जा सकती, क्योंकि सारे राजनीतिक दल महंगाई नाम की कंपनी के शेयर होल्डर हैं और भ्रष्टाचार सबके लिए आसान रास्ता है. इन्हें यह बिल्कुल नहीं लगता कि देश की जनता कभी गुस्सा या नाराज़ भी होगी. इन्हें देश की आवाम निरीह, लाचार व बेवकूफ नज़र आती है. इसीलिए देश का सारा शिक्षा तंत्र इन्होंने बर्बाद कर दिया, ताकि बड़े पैसे वाले ही शिक्षा हासिल कर सके. दो–तिहाई हिंदुस्तान अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजने के बारे में सोच भी न सकें और वही हाल इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था का कर रखा है. अब लोग काग़ज़ पर साक्षर हो रहे हैं, स्कूलों में नहीं जाते. अब उन्हें सामान्य बुखार की दवाइयां भी नक़ली मिलती हैं. ग़रीब आदमी अब ज़िंदा रहने के बारे में सोचता ही नहीं. अगर किसी ग़रीब के परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो वह मन ही मन सोचता है कि बीमार जल्द ही दुनिया से रुख़सत ले ले, नहीं तो इलाज में कितना पैसा ख़र्च होगा, कोई अंदाज़ा नहीं. अब तो अड़ोस–पड़ोस के लोग सामाजिक ताना भी नहीं देते कि तुम इलाज क्यों नहीं करा पा रहे हो, क्योंकि उनकी हालत भी कुछ जुदा नहीं है.

2013 में किसान हर आधे घंटे पर आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है. खेती बर्बाद हो चुकी है. जो खेती करते हैं, उन्हें फसल का लाभ नहीं मिलता. उनकी ज़िंदगी निम्न मध्यम वर्ग की हो गई है. धीरे–धीरे सब कुछ गिरवी रखा जा रहा है और इस स्थिति ने हिंदुस्तान के ताने–बाने को छिन्न–भिन्न कर दिया है. नौजवान इसलिए रास्ते से भटक रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है. नौकरियां कम हो रही हैं, लेकिन हमारे राजनेता और सरकारी अधिकारी चेतना ही नहीं चाहते. 2013 आधा बीत गया, आधा बाक़ी है. इन बचे पांच महीनों में अगर देश के लोग खड़े हो गए और उन्होंने राजनेताओं से हिसाब पूछना शुरू कर किया, तो देश की कैसी तस्वीर होगी? सोचकर भी डर लगता है. अन्ना हजारे देश के लोगों को धैर्य रखने और देश के लोगों को अहिंसात्मक रास्ता अपनाने की सलाह दे रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ नक्सलवादी लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. अन्ना हजारे की बात न मीडिया सुन रहा है और न अन्ना हजारे की बात सरकार सुन रही है. राजनीतिक दल उन्हें चुका हुआ व्यक्ति मानते हैं. जनता तकलीफ में है. परेशान है. कोई भी वर्ग खुश नहीं है. इस स्थिति से घबराकर अगर जनता देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दे. अगर रेल, सड़क यातायात रोकना शुरू कर दे और बहकावे में आकर हिंसा पर उतर आए, तो क्या तस्वीर बनेगी, डर लगता है. बहुत डर लगता है. हमारे देश में लोकतंत्र का धागा बहुत मजूबत है, लेकिन देश में जो लोकतंत्र चल रहा है, वह संविधान विरोधी है. जब अन्ना हजारे सारे देश में घूम कर संविधान के विपरीत चल रहे लोकतंत्र के विकृत स्वरूप को लोगों के सामने रखते हैं, तो लोग उत्साह से खूब तालियां बजाते हैं. आजकल किसी भी पार्टी के नेता की सभा में भीड़ नहीं हो रही है. भीड़ लाने के लिए बसों का, खाने का, दैनिक भत्ते का और कुछ इतर भी बहुत कुछ का लालच दिया जाता है, जबकि अन्ना हजारे की सभा में लोग अपना पैसा ख़र्च कर उनका भाषण सुनने जाते हैं.

मुझे लगता है कि जो लोग भी आजकल भगत सिंह सुखदेव या रामप्रसाद बिस्मिल का नाम लेते हैं, उन्हें ये राजनेता महान मूर्ख मानते हैं. उन्हें लगता है कि इनके दिमाग़ में कोई ख़राबी आ गई है या दिमाग़ का कोई कल-पुर्जा ढीला हो गया है, जो आज़ादी के शहीदों का नाम लेते घूम रहे हैं. मैंने अपने संवाददाताओं से एक सर्वे कराया, जिसमें ख़ुलासा हुआ कि किसी भी नेता के घर में भारत की आज़ादी के लिए शहीद हुए किसी भी बलिदानी का चित्र तक नहीं है.

मुझे डर सिर्फ़ एक बात की है कि सरकार और राजनीतिक दलों की उदासीनता की वजह से अगर कहीं छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ. नौजवानों का आंदोलन शुरू हुआ. अगर कहीं किसानों ने यह सोच लिया कि आंदोलन करने से पहले आत्महत्या के कारकों में से किसी एक की जान ले लेनी है, क्योंकि वे तो जान देने ही जा रहे हैं, तो इस देश में क्या होगा. राजनीतिक दल भूल जाते हैं कि किसानों के बच्चे ही सबसे ज़्यादा सिपाही के रूप में सेना और पुलिस में भर्ती हैं. वो अपने घर के हालात से दिमाग़ी रूप से बहुत परेशान हैं. उन नौजवानों के ऊपर आज अनुशासन की हथकड़ी और बेड़ियां हैं, लेकिन अगर उन्हें अपने घरों से रोने की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, तो बहुत दिनों तक अनुशासन की हथकड़ी और बेड़ियां उन्हें बांध नहीं पाएंगी. वो अपने आप इन हथकड़ियों और बेड़ियों को तोड़ देंगे.

2013 का 15 अगस्त हमें खुशियां नहीं देता, डराता है, लेकिन सत्ता में और विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों को शायद 15 अगस्त, 2013 वैसा ही आम 15 अगस्त लगे, जैसा वो 1947 के बाद हर एक बार रिचुअल के रूप में मनाते आए हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

जातीय समाज की बेड़ियों को तोड़िए

मेघनाद देसाई

भारत ने राजनीतिक स्तर पर जिस समानता को ग्रहण किया, वह है एक व्यक्ति, एक वोट. हालांकि गंभीर चिंता का विषय यह है कि सामाजिक आधार पर भारत में आज भी जातीय और वर्ग विभेद मौजूद है.

वर्ष 1959 में एक फिल्म आई थी अनाड़ी. इस फिल्म में एक दृश्य था, जिसमें हीरो राजकपूर एक रेस्टोरेंट में काम करता है. एक दिन हीरो को रेस्टोरेंट की दाल में कॉक्रोच मिलता है और वह दाल फेंक देता है. इससे ख़फ़ा होकर रेस्टोरेंट का मालिक उसे यह कहते हुए नौकरी से निकाल देता है कि अगर दाल में कॉक्रोच था, तो कॉक्रोच निकालकर फेंक देते, दाल फेंकने की क्या ज़रूरत थी? देखा जाए, तो आज भारत में बच्चों की बड़ी संख्या इसी तरह के भोजन पर निर्भर है. ख़ासकर मिड–डे–मील की बात की जाए, तो आए दिन इसमें कीड़े–मकोड़े, छिपकली, सांप और कॉक्रोच के मिलने की ख़बरें आ रही हैं. और छपरा का मिड–डे–मील प्रकरण तो इस दिशा में हो रही लापरवाहियों का चरम था. बावजूद इसके, दूसरे राज्यों से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति यह साबित करती है कि सरकार और माई–बाप ऐसी घटनाओं को लेकर उदासीन रहेंगे. ऐसे में हजारों–करोड़ों ख़र्च करके चलाई जा रही इन योजनाओं पर सवालियां निशान लाजिमी है कि क्या ये योजनाएं जीवन देने के लिए हैं या जीवन लेने के लिए? साथ ही सवाल यह भी है कि सरकारें ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन में इतनी असफल क्यों हो जाती हैं? अपनी हालिया किताब में ज्यां द्रेज और अमर्त्य सेन ने स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल दिया है, लेकिन साथ में उन्होंने यह आशंका भी जताई है कि सरकार इन मसलों को लेकर गंभीर नहीं हैं. ऐसी आशंका इसलिए है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश की सरकारें पिछले 20 वर्ष के नव उदारवादी दौर से ही नहीं, नेहरु–गांधी के समाजवादी दौर से ही हर मसलों पर असफल साबित होती रही हैं. हो सकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर हम इसलिए भी उतना बेहतर न कर पाएं हों, क्योंकि आज़ादी के बाद के शुरुआती 40 साल तो हम केवल स्टील मिलों, बांधों और मशीनों के निर्माण व विकास पर ही केंद्रित रहे, न कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मसलों पर. आईआईटी और आईआईएम संस्थानों ने भी इन्हीं विभागों पर केंद्रित नौकरियां सृजित कीं।

आज हालात यह है कि हम परमाणु बम बना सकते हैं. उपग्रह छोड़ सकते हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य देने में हम आज भी नाक़ाम हैं. यह सब अचानक नहीं हुआ है. यह हमारे पिछले 60 वर्षों की सोच का नतीजा है, जिसमें संभ्रात वर्ग शासन पर क़ब्ज़ा जमाए बैठा है और देश उनके मन–मुताबिक़ नीतियों का दंश झेल रहा है. भारतीय प्रगतिशील विचारक समाजवाद की बात तो करते हैं, लेकिन उससे जो अर्थ निकलकर आता है, उसके मायने पश्चिमी समाजवादी विचारधारा से बिल्कुल अलग हैं. पश्चिमी समाजवादी विचारधारा इस बात पर केंद्रित है कि लाभ समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचे. भारत में समाजवादी विचारधारा इस बात की ओर उन्मुख है कि समाजवाद का लाभ समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग को मिले. यही वजह है कि भारतीय समाज में आधारभूत सुविधाओं का बेहद अभाव है. समानता का बेहद सीधा–सा सिद्धांत है कि सबको समान अवसर व समान आधार मिले, लेकिन हम इस बुनियादी सिद्धांत के साथ भी नहीं चल पा रहे हैं.

गौरतलब है कि भारतीय समाज जाति आधारित है और जाति आधारित समाज की शुरुआत ही असमानता के आधार पर होती है. वर्ग आधारित समाज में आय और धन की असमानता होती है, लेकिन सामंतवाद के अंत के बाद इन आधारों पर बनी असमानता समाप्त हो गई. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी नस्ल के आधार पर विभेद होता था, लेकिन सिविल राइट्स के लिए हुए संघर्षों ने इन असमानताओं को ख़त्म कर दिया. भारत ने राजनीतिक स्तर पर जिस समानता को ग्रहण किया, वह है एक वयस्क व्यक्ति, एक वोट, लेकिन सामाजिक आधार पर जातीय विभेद और वर्ग विभेद मौजूद हैं. भारत में अभी भी राज्य उच्च वर्ग द्वारा शासित है और उनके विचारों में निम्न वर्गीय जनसंख्या शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं में शामिल नहीं होती. ज्या द्रेंज और अमर्त्य सेन ने बताते हैं कि किस तरह से जापान ने पिछले मेजी क्रांति के 40 वर्षों के भीतर ही 100 प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को हासिल कर लिया. ऐसा इसलिए, क्योंकि जापान की सरकार के दृष्टिकोण में देश का हर नागरिक समान है, जबकि भारत में अभी तक हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत जैसे विभेदों पर ही अटके हुए हैं. मिड–डे–मील से बात शुरू हुई थी, उसी का उदाहरण लें, तो दक्षिण में तमिलनाडु ने इसे उत्तर भारतीय राज्यों से काफी पहले शुरू किया. ऐसा इसलिए, क्योंकि दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोध मूवमेंट के चलते जाति और अगड़े–पिछड़े जैसे मसले काफ़ी पहले ही हल हो चुके हैं. हालांकि आज तमिलनाडु में चलाए जा रहे सभी वेलफेयर कार्यक्रमों में राज्य सरकार की छाप दिख रही है.

जबकि इधर उत्तर भारत में ब्राह्मण आज भी सर्वोच्च जाति के तौर पर हावी हैं. और सरकारी महक़मों में शामिल उच्च वर्ग के लोग आज भी पिछड़ी जातियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा ख़र्च नहीं करना चाहते. 80 के दशक के आख़िरी दिनों मे जब कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व ख़त्म हुआ और पिछड़ी जातियों के नेतृत्व वाली पार्टियां सत्ता में आईं, तब से यह प्रभुत्व धीरे–धीरे टूट रहा है. इसीलिए मैने कहा कि आज़ादी के बाद के पचास वर्ष हम जातीय संप्रभुता की लड़ाई में ख़र्च किए. अब, जब हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, तो इन बेड़ियों को तोड़कर आगे आने की ज़रूरत है. ■

feedback@chauthiduniya.com

आज हालात यह है कि हम परमाणु बम बना सकते हैं. उपग्रह छोड़ सकते हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य देने में हम आज भी नाक़ाम हैं. यह सब अचानक नहीं हुआ है. यह हमारे पिछले 60 वर्षों की सोच का नतीजा है, जिसमें सभ्रांत वर्ग शासन पर क़ब्ज़ा जमाए बैठा है और देश उनके मन-मुताबिक़ नीतियों का दंश झेल रहा है. भारतीय प्रगतिशील विचारक समाजवाद की बात तो करते हैं, लेकिन उससे जो अर्थ निकलकर आता है, उसके मायने पश्चिमी समाजवादी विचारधारा से बिल्कुल अलग हैं.

आरटीआई आवेदन

आधारभूत बातों की जानकारी ज़रूरी

चौथी दुनिया ब्यूरो

आरटीआई सूचना प्राप्त करने का एक माध्यम ही नहीं, बल्कि अधिकार है, जिसके द्वारा सूचना प्राप्त कर हम अपने अधिकारों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज भी आरटीआई को लेकर शिक्षित लोगों में भी हिचक या भ्रम देखने को मिलती है. इसके पीछे मूल कारण जागरुकता का अभाव है. सबसे पहले आरटीआई आवेदक को इसके कुछ आधारभूत पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए. मसलन, आरटीआई क़ानून के तहत शिकायत का क्या अर्थ होता है. शिकायत कब, कहां और कैसे दाख़िल की जाती है. दरअसल, अपील और शिकायत में एक बुनियादी फर्क़ है. कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने आरटीआई आवेदन में जो सवाल पूछा है, उसका जवाब आपको ग़लत दे दिया जाता है. और, आपको पूर्ण विश्वास है कि जो जवाब दिया गया है, वह ग़लत, अपूर्ण या भ्रामक है. इसके अलावा, आप किसी सरकारी महक़मे में आरटीआई आवेदन जमा करने जाते हैं और पता चलता है कि वहां तो लोक सूचना अधिकारी ही नियुक्त नहीं किया गया है. या फिर आपसे ग़लत फीस वसूली जाती है. तो, ऐसे मामलों में हम सीधे राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत कर सकते हैं. ऐसे मामलों में अपील की जगह सीधे शिकायत करना ही समाधान है. आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को एक लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है. यदि आपको कोई जानकारी देने से मना किया गया है, तो आप केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग (जैसा मामला हो) में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

सूचना क़ानून की धारा 18 (1) के तहत यह केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य है, जैसा भी मामला हो, कि वे एक व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें और पूछताछ करें. जो केंद्रीय सूचना लोक अधिकारी या राज्य सूचना लोक अधिकारी के पास अपना अनुरोध जमा करने में सफल नहीं होते, जैसा भी मामला हो, इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि उक्त अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के तहत नियुक्त न किया गया हो, जैसा भी मामला हो, ने इस अधिनियम के तहत अग्रेषित करने के लिए कोई सूचना या अपील के लिए उसके आवेदन को स्वीकार करने से मना कर दिया हो, जिसे वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास न भेजे या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग में अग्रेषित न करें, जैसा भी मामला हो.

जिस व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत कोई

जानकारी देने से मना कर दिया गया हो, जिस व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर सूचना के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया हो. जिसे शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता हो, जिसे वह अनुपयुक्त मानता/मानती है. जिसे विश्वास है कि उसे इस अधिनियम के तहत अपूर्ण, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है. इस अधिनियम के तहत अभिलेख तक पहुंच प्राप्त करने या अनुरोध करने से संबंधित किसी मामले के विषय में.

पाठकों के पत्र

पांच साल बाद सूचना मुफ्त मिली

पीएमओ से मैंने कुछ सूचनाएं मांगी थीं. 8 पेज की सूचना के लिए मुझसे 16 रुपये जमा कराने को कहा गया था. यह पांच साल पुरानी घटना है, लेकिन मैंने 16 रुपये जमा कराना उचित नहीं समझा और इस मामले को केंद्रीय सूचना आयोग में ले गया. आयोग ने सुनवाई के लिए दो बार नोटिस जारी कर दोनों पक्षों को उपस्थित होने का आदेश दिया, लेकिन बेगूसराय स्थित एनआईसी स्टूडियो के ख़राब होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी.

इसके बाद 20 जून, 2011 को दिल्ली स्थित सूचना आयोग में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद आयोग ने सूचना नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

–गिरीश प्रसाद गुप्ता, *बेगूसराय, बिहार*

शिक्षक नियोजन पत्र नहीं मिला

मैंने सरायरंजन प्रखंड, समस्तीपुर में सामान्य शिक्षक पद के लिए साल 2008 में द्वितीय शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन किया था, जिसमें मेरा चयन भी हो गया था, लेकिन जब मैं नियोजन पत्र के लिए चयनित स्थल पर गया, तो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने मानव संसाधन विकास विभाग की अगली प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नियोजन पत्र देने की बात कही. जब आरटीआई के तहत मैंने इस संबंध में सूचना मांगी, तो आधी–अधूरी सूचना दी गई, वह भी छह महीने बाद. भेजी गई सूची में मेरा नाम प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ अंतिम मेधा सूची में भी है और प्रतीक्षा सूची में भी है. आरटीआई के तहत यह भी जानकारी मिली कि 12/8/2010 तक पांच सीटें बची हुई थीं, फिर भी एक प्रशिक्षित उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं दी गई. आख़िर ऐसा क्यों हुआ, यह सूचना अब तक नहीं मिल सकी है.

–राजीव कुमार शर्मा, *समस्तीपुर, बिहार*

आप इस मामले में अपेक्षित सूचना पाने के लिए राज्य सूचना आयोग में भी अपील कर सकते हैं. सूचना आयोग के पते/फोन नं.

केंद्रीय सूचना आयोग
मुख्य सूचना आयुक्त
क्लब बिल्डिंग
ओल्ड जेएनयू कैंपस
बेर सराय, नई दिल्ली–67
011–26161137

बिहार राज्य सूचना आयोग
मुख्य सूचना आयुक्त
चौथा तल, सूचना भवन
(नये सचिवालय के सामने)
पटना–1
0612–2235466

झारखंड राज्य सूचना आयोग
मुख्य सूचना आयुक्त
इंजीनियरिंग हॉस्टल
धुर्वा, रांची
09431364947
फैक्स–0651–2401418 ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें. तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें. नौकरीपेशा व्यापारी अपने-अपने धंधे में ज्यादा मेहनत करेंगे. आप अपने दांपत्य जीवन में भी सुख का अनुभव करेंगे. इस सप्ताह अपने निजी संबंधों को भी अच्छी तरह सुधारेंगे. इस सप्ताह अपने अन्दर नयापन को भी लाएंगे. लम्बी यात्रा से यथासंभव बचें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह आपके खर्चे भी अनियंत्रित तरीके से बढ़ेंगे. आप उन्नति के लिए हद से ज्यादा मेहनत करेंगे. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों वर्ग आर्थिक रूप से थोड़े चिंतित रहेंगे. आप अपनी वाणी पर पूर्णतया नियंत्रण रखें, अन्यथा संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा. पारिवारिक सुख की दृष्टि से अच्छा समय रहेगा. जोखिम लेने से बचें.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह शत्रुओं पर आपकी विजय होगी. आपका कोई अटका हुआ धन प्राप्त होगा. व्यापारी और नौकरीपेशा, दोनों लोगों के लिए समय ठीक रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी परेशानी वाला समय रहेगा. कार्य मनोयोग से करते रहें, विचलन की जरूरत नहीं है. अनावश्यक निवेश से बचें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह आपके मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी. लोगों को परामर्श देने की आपकी क्षमता भी बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा प्रमोशन और स्थानांतरण मिल सकता है. संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें. आकस्मिक धन लाभ का भी प्रबल योग है. सारे सगे-संबंधियों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह गृह निर्माण से संबंधित कोई योजना बनेगी. आपके कार्य करने के तरीकों में भी थोड़ा धीमापन रहेगा. पठन-पाठन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कोई भी नई खरीद-बिक्री में थोड़ी सतर्कता रखें. शत्रु पक्ष से सावधान रहें. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
इस सप्ताह किसी नई योजना में आपके प्रयास सार्थक रहेंगे. व्यय की अधिकता रहेगी. रिश्तेदारों से लाभ मिलेगा. संतान सुख सर्वोत्तम होगा. व्यवसायी थोड़े उतार-चढ़ाव महसूस करेंगे. किसी भी खरीद-बिक्री में कागजी दस्तावेजों का ध्यान रखें. कोर्ट-कचहरी के मामलों में नतीजे आपके साथ होंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह किसी प्राकृतिक या दार्शनिक जगह की यात्रा का योग बनेगा. आपकी अभिलाषा की पूर्ति होगी. पुरानी संपत्ति का विवाद आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बन सकता है. व्यापारी किसी भी नये योजना को थोड़ा आगे बढ़ा दें. लेन-देन के मामलों से बचें, अन्यथा चिंता बढ़ेगी. विरोधी भी इस सप्ताह आपके साथ होंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह पुरानी संपत्ति के क्रय-विक्रय से आगे की योजना बनेगी. आपका परिश्रम बढ़ेगा. आपके व्यवसाय में बदलाव का समय रहेगा और प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में भी प्रसिद्धि बढ़ेगी. विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य में हलके उतार-चढ़ाव महसूस करेंगे. पैसे के लेन-देन से बचें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी. साझेदारी में व्यापार करने वाले लोग थोड़े तनाव में रहेंगे. इस सप्ताह आपके परिश्रम के अनुपात में सामान्य फल प्राप्त होगा. कुछ पारिवारिक तौर पर नई परेशानी दिख सकती है. नौकरीपेशा और व्यापारी, दोनों वर्ग आर्थिक रूप से अच्छा करेंगे.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों को उन्नति से संबंधित समाचार मिलेगा. तेज मसाले वाला खाना खाने से बचें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. इस सप्ताह कई समस्याओं से निजात मिलेगा और आप उत्साहित रहेंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से मिला-जुला फल वाला समय रहेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह पारिवारिक तौर पर थोड़ा उतार-चढ़ाव महसूस करेंगे. नौकरीपेशा लोग इस सप्ताह प्रशंसा के हक़दार रहेंगे. इस सप्ताह आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. इस सप्ताह आप वाहन चलाने में सावधानी रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा परेशानी वाला समय रहेगा. संपत्ति की खरीद अच्छी तरह से सोच-समझ कर करें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस सप्ताह आपका मन अत्यधिक प्रसन्न रहेगा. परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं. विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान देंगे. इस सप्ताह आपकी तर्कशक्ति में बढ़ोत्तरी होगी. व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा. स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा. नौकरीपेशा लोग थोड़े तनाव में रहेंगे.

मनोवैज्ञानिक उपचार से छुड़ाएं धूम्रपान

चौथी दुनिया ब्यूरो

धूम्रपान की लत से छुटकारा दिलाने में मनोवैज्ञानिक उपचार एवं मनो–सामाजिक उपाय कारगर पाए गए हैं. मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, हृदय रोगों, फेफड़े एवं मुंह के कैंसर तथा अन्य जानलेवा बीमारियों का कारण बनने वाले धूम्रपान की लत से छुटकारा दिलाने के लिए बिहैवियरल थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं स्व–सहायता उपाय कारगर पाए गए हैं. भारत में 12 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं और दुनिया भर में धूम्रपान करने वाले लोगों में से 10 प्रतिशत भारत में रहते हैं और धूम्रपान करने वालों की संख्या के हिसाब से चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है. मनोचिकित्सक डॉ. सुनील मित्तल का कहना है कि धूम्रपान मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक लत है. हमारे देश में लोगों के मन में धूम्रपान एक आम रिवाज बन गया है. साथ ही साथ सिगरेट में मौजूद निकोटीन इस लत को और मजबूत बनाता है. अध्ययनों से ऐसे सबूत मिले हैं कि मनोवैज्ञानिक उपचार एवं उपाय से धूम्रपान छोड़ने की दर बढ़ जाती है. कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहैवियरल साइंसेस की साइकोलॉजिस्ट सुश्री संस्कृति सिंह के अनुसार, शरीर को निकोटीन की नियमित मात्रा मिलना बंद हो जाने पर शारीरिक लक्षण उभरते हैं और धूम्रपान करने की तीव्र चाह पैदा होती है. इसलिए धूम्रपान की लत के परित्याग को कामयाब करने के लिए व्यवहार संबंधी परिवर्तन करने के साथ–साथ निकोटीन बंद करने से होने वाली समस्याओं से निबटना भी ज़रूरी होता है. डॉ. मित्तल के अनुसार, धूम्रपान को छोड़ने में मनोवैज्ञानिक उपचार काफ़ी कारगर रहे हैं. डिप्रेशन से ग्रस्त धूम्रपान करने वालों के लिए अनेक लाभदायक मनोवैज्ञानिक उपचार विधियां विकसित हो चुकी हैं और जो लोग धूम्रपान की लत को छोड़ना नहीं चाहते, उनकी धूम्रपान करने की लत तथा तौर–तरीक़ों में बदलाव लाया जा सकता है. डॉ. मित्तल ने इस बात पर चिंता जताई कि हर साल धूम्रपान के कारण 10 लाख से अधिक भारतीयों की मौत होती है. यह अत्यंत भयावह है और इसलिए धूम्रपान तथा तंबाकू सेवन को बंद करने तथा इससे होने वाले दुष्परिणामों को कम करने के लिए जागरुकता क़ायम किया जाना अत्यंत ज़रूरी है. हर व्यक्ति धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानता है, लेकिन लोग सबकुछ जानते हुए धूम्रपान करते हैं, जिसका मुख्य कारण मनोवैज्ञानिक है. निकोटीन की लत लग जाने पर धूम्रपान को छोड़ना मुश्किल होता है, पर अगर धूम्रपान के मनोवैज्ञानिक कारणों को समाप्त कर दिया जाए, तो दो सप्ताह में इस लत से छुटकारा दिलाया जा सकता है.

गौरतलब है कि तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी ख़तरों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए 31 मई, 2013 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में चिह्नित किया गया है. इस वर्ष का विषय तंबाकू विज्ञापन, प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप पर प्रतिबंध लगाना है. अध्ययनों से पता चला है कि धूम्रपान विभिन्न तरह के कैंसर के खतरों को 2 से 5 गुना बढ़ा देता है और धूम्रपान करने वाले लोगों के धूम्रपान नहीं करने वालों की तुलना में कैंसर से मरने की संभावना 7 गुना अधिक होती है. साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि तनाव, डिप्रेशन, अकेलापन, डर और चिंता जैसे कुछ अप्रिय एहसास एवं भावनाएं हैं, जिनसे उबरने के लिए कोई व्यक्ति धूम्रपान करने लगता है. जब किसी व्यक्ति का कोई दिन ख़राब होता है, तो वह सिगरेट को अपना साथी बनाता है और हो सकता है कि सिगरेट पीने पर कुछ समय के लिए उदासी, तनाव, चिंता, डिप्रेशन एवं बोरियत गायब हो जाए, लेकिन इसके घातक परिणाम हो सकते हैं. वैसे, अप्रिय भावनाओं एवं एहसास को दूर करने के लिए कई स्वास्थ्यकारी उपाय हैं और ये उपाय कारगर हैं. इन उपायों में व्यायाम, ध्यान, रिलेक्सेशन तकनीक तथा श्वसन एक्सरसाइज आदि प्रमुख हैं.

अनेक लोगों के लिए धूम्रपान के परित्याग का एक महत्वपूर्ण तरीक़ा यह है कि धूम्रपान के बग़ैर ही नाकारात्मक विचारों से निबटने का वैकल्पिक उपाय खोजा जाए. हालांकि जब आप सिगरेट नहीं पिएंगे, तब भी अतीत में आपको सिगरेट पीने के लिए विवश करने वाले अप्रिय विचार एवं भावनाएं बने रहेंगे, इसलिए यह भी ज़रूरी है कि तनावपूर्ण स्थितियों से मुक़ाबला करने के लिए अलग तरीक़ों के बारे में सोचा जाए.

डॉ. सुनील कहते हैं कि अनुसंधानों के आधार पर इस बात की पुष्टि की गई है कि निकोटीन हेरोइन और कोकीन जैसी कड़ी दवाओं की तरह ही नशीली है. इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी को भी विशेषकर कम उम्र के लोगों को किसी भी कारण से इसे शुरू नहीं करना चाहिए. इसके अलावा, शराब और अन्य पदार्थों के साथ तंबाकू का सेवन तंबाकू के दुष्प्रभाव को और बढ़ा देता है. डॉक्टर सुनील कहते हैं कि लोगों को तंबाकू के सेवन से परहेज करने के लिए प्रेरित करना सामाजिक ज़िम्मेदारी भी है. हम देखते हैं कि जिन परिवारों में तंबाकू का सेवन होता है, वे इसके दुष्परिणामों को लेकर कम चिंतित होते हैं. तंबाकू छोड़ने के उल्लेखनीय परिणाम देखे गए हैं और इसे जल्द से जल्द छोड़ना बेहतर होता है. ■

ज़रा हट के

रोती है ख़ून के आंसू

जब कोई रोता है, तो उसकी आंखों से आंसू के रूप में पानी की धारा बहती है, जिसे देखकर कोई अचरज नहीं होता, लेकिन अगर रोने पर किसी की आंखों से ख़ून की धारा बहने लगे, तो कोई भी व्यक्ति डर जाएगा, क्योंकि अब तक ख़ून के आंखों रोने की बात हमने अपने देश में कहावतों में ही सुना था. वह लड़की है चिली की, जिसकी उम्र अभी 20 साल है. वह लड़की जब रोती है, तो उसकी आंखों से आंसू नहीं, ख़ून निकलते हैं. इस विचित्र मामले को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए हैं. चिली के लॉस लागोस क्षेत्र के ओसोर्नो प्रांत के शहर परांक की रहने वाली यारिजा ऑलिवा के साथ इसी महीने के शुरुआत में यह घटना घटी और अब वह दिन में कई बार ख़ून के आंसू रोती हैं. ऑलिवा जब अपनी शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंची, तो डॉक्टर को उसकी आंखों में किसी तरह का इंफेक्शन नहीं मिला. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

कुवैत का संविधान महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने के प्रति भी अन्य अरब देशों के विपरीत लचीला है. यही कारण है कि विख्यात राजनीतिक विश्लेषक माइकल हेरिफ़ अपने विश्लेषण में लिखते हैं कि खाड़ी देशों में कुवैत एकमात्र ऐसा देश है, जहां बहुत ही ठोस बुनियादों पर लोकतंत्र का तजुर्बा हासिल किया जा रहा है. यही कारण है कि कुवैत की महिलाएं विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकती हैं.

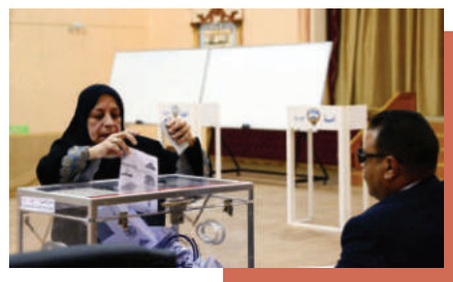

कुवैत में नया शासन

भारत के लिए अहम क्यों

भारत और कुवैत के संविधान में राजनीतिक दलों द्वारा जनता का प्रतिनिधित्व का न होना कॉमन फैक्टर है. अन्ना हज़ारे भी यही बात समझाने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं. अन्ना हज़ारे का कुवैत का एक दौरा आपसी संबंधों को एक नई दिशा दे सकता है. संसदीय चुनावों के बाद परिस्थितियों का जायज़ा लेती यह रिपोर्ट...

वसीम अहमद

कुवैती व्यवस्था यद्यपि राजशाही है और यहां सभी अधिकार अमीर (राष्ट्राध्यक्ष) के पास होते हैं, लेकिन जनता के प्रतिनिधित्व के लिए 50 सदस्यों की संसद (मजलिस अल उम्मा) स्थापित है, जिसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं. यहां किसी भी क़बीले, तबक़े और हिस्से से कोई भी व्यक्ति निर्वाचित होकर संसद जा सकता है, लेकिन किसी को भी राजनीतिक दल गठित करने की अनुमति नहीं है. यानी कुवैत के संविधान के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को जनता पसंद करती है और उसे लगता है कि वह व्यक्ति संसद जाकर उनकी समस्याओं को उठाएगा, तो वह उस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन सकती है.

कुवैत का यह क़ानून हमारे संविधान से बहुत हद तक मेल खाता है, क्योंकि संविधान में भी किसी राजनीतिक पार्टी के गठन का स्पष्टीकरण नहीं है और विख्यात समाजसेवी अन्ना हज़ारे इसी संदेश को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं कि बिना किसी राजनीतिक दल के गठन के, समाज में जो आदमी उन्हें ईमानदार लगता हो और यह विश्वास दिलाता हो कि वह संसद में जाने के बाद उनकी समस्याओं को उठाएगा, तो जनता उसे सर्वसम्मति से प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजे.

पार्टी गठित न करने के संबंध में भारत-कुवैत के संविधान में समानता, दोनों राष्ट्र की चिंता व मानसिकता में एकरुपता को चिन्हित कर रही है और ज़ाहिर है कि समानता के कारण ही दोनों के बीच सदियों से व्यापारिक रिश्ते स्थापित हैं और न केवल व्यापार बल्कि मैनपॉवर का अदान-प्रदान उच्च स्तर पर होता है.

संसद को भंग करने का अधिकार राष्ट्राध्यक्ष के पास होता है और वह ही इस बात पर नज़र रखता है कि संसदीय प्रतिनिधि जनता की आशाओं पर ख़रा उतर रहे हैं या नहीं. अर्थात् जब कभी कुवैत के राष्ट्राध्यक्ष को ऐसा लगता है कि सांसद अपनी जिम्मेदारियों का संपूर्ण निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरी संसद भंग कर दी जाती है. यही कारण है कि 2006 से अब तक कुवैत की संसद 7 बार भंग की जा चुकी है. ज़्यादातर संसद भंग सत्तारूढ़ सबाही परिवार से सांसदों के मतभेदों के कारण हुई है, लेकिन इसके साथ ही यह भी सत्य है कि कुवैत की राजनीति अन्य अरब देशों के मुक़ाबले कुछ अधिक लचीली है और इसी लचीलेपन की वजह से कुवैत के युवा सरकार के विरुद्ध विद्रोही तेवर नहीं अपनाते.

यही कारण है कि जिस समय अरब में हर तरफ़ अरब बसंत का भय फैला हुआ था और युवाओं में बेरोज़गारी को लेकर शासकों से कड़ी नाराज़गी थी. यहां तक कि सउदी अरब जहां शाही व्यवस्था के विरुद्ध बोलना भी महापाप माना जाता है, वहां भी अरब बसंत की लहर महसूस की जा रही थी और क़तर में युवाओं के आक्रामक तेवरों की ख़बरें आ रही थीं. ऐसे समय में भी कुवैत में कोई विद्रोह-प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि कुवैत का क़ानून लचीला है और नीति में जन विचारों को ध्यान में रखा जाता है. इसके अलावा, कुवैत की सरकार जनता के लिए आर्थिक सुधारों के लिए निवेश करती रहती है. इसीलिए अरब बसंत के समय, जब खाड़ी देशों की सभी सरकारें अपने बचाव और बसंत को रोकने के उपायों के बारे में विचार कर रही थीं, तो इस समय, यानी 2010 में कुवैत सरकार 105 अरब डॉलर की आर्थिक योजना का प्रस्ताव पेश कर रही थी.

इसके अलावा, कुवैत का संविधान महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने के प्रति भी अन्य अरब देशों के विपरीत लचीला है. यही कारण है कि विख्यात राजनीतिक विश्लेषक माइकल हेरिफ़ अपने विश्लेषण में लिखते हैं कि खाड़ी देशों में कुवैत एकमात्र ऐसा देश है, जहां बहुत ही ठोस बुनियादों पर लोकतंत्र का तजुर्बा हासिल किया जा रहा है. यही कारण है कि कुवैत की महिलाएं विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकती हैं. हालांकि उन्हें यह अधिकार 2005 के बाद प्राप्त हुआ है, लेकिन देर से ही सही, कुवैत की संसदीय व्यवस्था में महिलाएं निरंतर प्रतिनिधित्व कर रही हैं. यहां एक वर्ग ऐसा भी है, जो धार्मिक रुझानों में विश्वास रखता है और वह यह नहीं चाहता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में हो. 2005 में जब महिला विधेयक पारित किया जा रहा था, तो इसी वर्ग विशेष ने उसका कड़ा विरोध किया था और वही वर्ग आज भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विरोध कर रहा है. उसी का असर है कि 2012 में हुए चुनावों के मुक़ाबले इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम हुआ है.

2012 के चुनावों में 3 महिलाएं सांसद चुनी गई थीं, जबकि इस बार के चुनावों में केवल 2 महिलाएं ही सफल हो सकी हैं. इनमें चर्चित नाम डॉक्टर मासूमा मुबारक का है. डॉक्टर मासूमा 2005 से ही संसद की सदस्य रही हैं, जबकि सफल होने वाली दूसरी महिला सांसद सफ़ा अल हाशिम हैं, जो पूर्व में भी संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं.

इस साल 50 सीटों की संसद में कुल 318 उम्मीदवारों में 8 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं, लेकिन मतदाताओं का स्वभाव कुछ बदला हुआ था, जिससे न केवल महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व मिला, बल्कि देश में शियाओं की लगभ 20-30 प्रतिशत आबादी होने के बावजूद उन्हें केवल 8 सीटें ही मिलीं, जबकि पिछले चुनावों में 17 शिया प्रतिनिधियों को संसद में भेजा गया था. निर्वाचित सांसदों में 10 ऐसे भी सदस्य हैं, जो लंबे समय से राजनीति से अलग-थलग थे, लेकिन इस बार उन्हें भी संसद के लिए चुना गया है. लिब्रल ब्लॉक ने पिछले चुनावों का बहिष्कार किया था, लेकिन इस बार उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है. सुन्नी इस्लाम प्रिय उम्मीदवारों को 10 सीटें प्राप्त हुई हैं. कुवैत के छोटे-छोटे क़बीलों का चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने और उनके उम्मीदवारों की सफलता को महत्वपूर्ण सफलता माना गया है. बहरहाल, सबाही परिवार की घोषणा के अनुसार, नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ संसद का नया सत्र 6 अगस्त से शुरू किया जाएगा.

कुवैत की जनता चुनावों के प्रति काफ़ी भावुक होती हैं और उत्साह के साथ ऐसे प्रतिनिधियों को चुनती है, जिनसे उन्हें आशा होती है कि वह उनकी आवाज़ को आलाकमान तक पहुंचाएंगे. पिछले वोटों की दर केवल 40 प्रतिशत थी, जबकि हालिया चुनावों में मतदान औसत बढ़कर 52 प्रतिशत हो गया, जो कुवैती जनता की मतदान में बढ़ती हुई रुचि की ओर इशारा करता है. इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जनता ने 26 ऐसे लोगों को चुना है, जो पहली बार संसद में जा रहे हैं. उनमें से 9 ऐसे हैं, जो पिछले चुनावों में जीत तो गए थे, लेकिन संसद भंग होने के कारण किसी सत्र में शामिल नहीं हो सके थे. इस बार 4 ऐसे सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जो सरकार के विरोधियों में गिने जाते हैं और पिछले चुनाव का उन्होंने बहिष्कार किया था, लेकिन इस बार सफल होकर संसद में पहुंचे हैं.

कुवैत के संविधान की धारा 56, जिसको 1962 में बनाया गया था, के अनुसार, राष्ट्राध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मजलिस अल वुज़रा (मंत्रिमंडल) के सर्वेसर्वा की नियुक्ति करे और कैबिनेट की सूची तैयार करके राष्ट्राध्यक्ष के पास स्वीकृति के लिए भेजे. इस बार कुवैत के राष्ट्राध्यक्ष ने शेख़ जाबिर अल मुबारक को यह उच्च पद सौंपा है और उनसे नया मंत्रिमंडल गठित करने के लिए कहा है. शेख़ जाबिर अल मुबारक 71 साल के हैं और उनके पास राजनीति का लंबा अनुभव है. उन्हें नवंबर 2011 में इसी पद के लिए चुना गया था और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उचित ढंग से निभाई थी. वह सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. आशा है कि उनके नेतृत्व में संसदीय व्यवस्था उचित ढंग से चलेगी. संसदीय चुनावों के बाद जो नया सत्ताधारी ग्रुप होगा, इसके तहत भारत-कुवैत पारंपरिक संबंध अधिक मज़बूत व स्थिर होंगे. आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर पर संबंधों के अलावा जन स्तर पर भी संबंध विकसित हो, ताकि दोनों देशों के संविधान में राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में जो समानता है, उसमें व्यवहारिक तालमेल पैदा किया जा सके.

होना तो यह चाहिए कि अन्ना हज़ारे कुवैत का दौरा करें, ताकि दोनों देशों में संविधान में राजनीतिक दलों का कोई हवाला न होने की बुनियाद पर जनप्रतिनिधित्व की उचित कल्पना विश्व के सामने और अधिक मज़बूती से आए और दोनों देशों में सरकारी व जन-स्तर पर चर्चा का विषय बन सके.

वैसे अन्ना हज़ारे बिना राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि को चुनने की बात कर रहे हैं. वह कोई नई बात नहीं है, बल्कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व नहीं हैं, क्योंकि यह भी एक कटू सत्य है कि इन राजनीतिक पार्टियों के कारण ही बहुत सी समस्याएं जन्म लेती हैं. विश्व में ऐसे राष्ट्रों की संख्या तीन दर्जन के क़रीब हैं, जहां राजनीतिक दल मौजूद नहीं हैं.

वह राष्ट्र अलडेमी, एससेंशन, बहरैन, बेलारूस, बोसनिया हर्जेगोविना, ब्रिटिश इंडियन ओशियंस टेरीटरी, ब्रिटिश सोवरियन बेस क्षेत्र, ब्रूनेई, म्यांमार, चेचेनया, क्रीस्टमस आइलैंड्स, कोकोज़ आईलैंड्स, ईस्टर आईलैंड, फॉलक लैंड आईलैंड, ग्वानटानामोबे, ग्वाएरेंसी, जर्सी, कुवैत, मैन, जॉर्डन, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेसिया, नाइरो, न्यो, नार्फोलिक आईलैंड, ओकरानिया (ओमान), पालाओ, पेटकेम आईलैंड, क़तर, सउदी अरब, सोमालिया, स्वाज़ीलैंड, टूकेलाओ, वेटीकन सिटी, अरब अमीरात और वालीस एंड फुटोना आदि हैं. ■

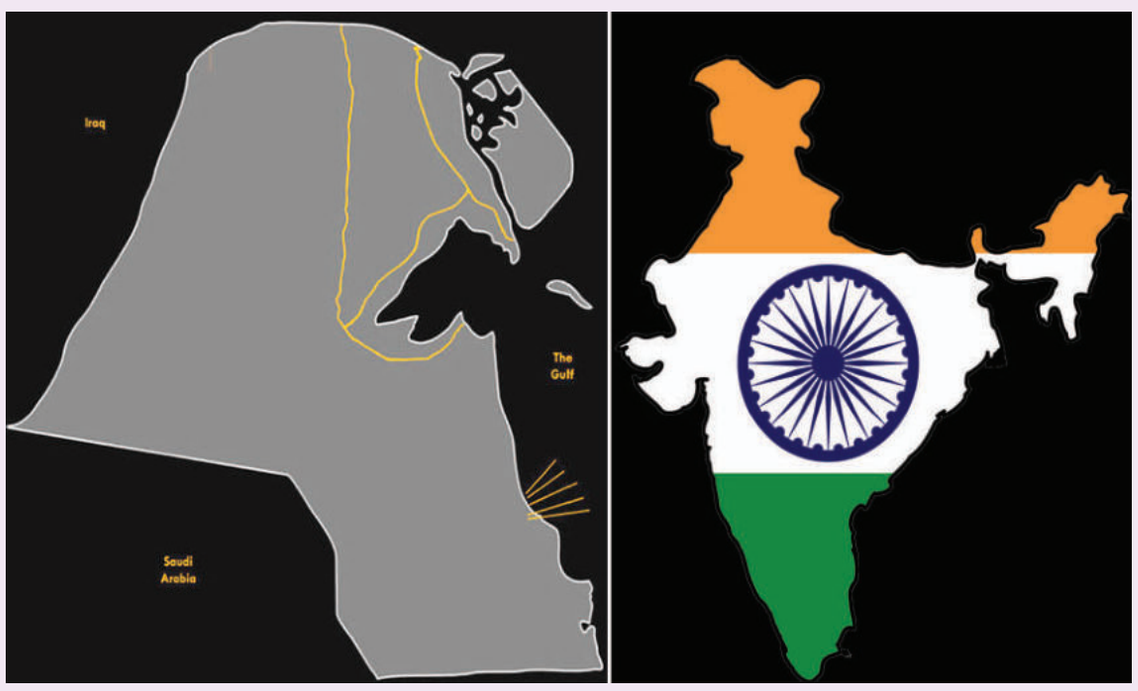

feedback@chauthiduniya.com

साई

आस्था

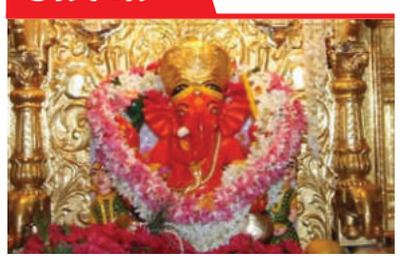

एक बार

सिद्धिविनायक मंदिर में देश–विदेश से नामचीन हस्तियां अपनी झोली फैलाए सभी के साथ खड़ी होती हैं. यह मंदिर लगभग दो शताब्दी पुराना है. इस मंदिर से देश ही नहीं, विदेशी धर्मावलंबियों की आस्था और श्रद्धा भी जुड़ी है. भगवान गणेश महाराष्ट्र ही नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवताओं में एक माने जाते हैं.

साई रक्षा मंत्र

चौथी दुनिया ब्यूरो

जिनकी धूनी जले निरंतर, वर दे जिनके हाथ ।
सो हमरी रक्षा करें, सद्गुरु साई नाथ ।। 1।।

जिनकी जीवन लीला से मिलते निर्मल ज्ञान ।
सो हमरी रक्षा करें, साई कृपानिधान ।।2।।

जिनके चरणों में बसें सारे तीर्थ महान ।
सो हमरी रक्षा करें, साई करुणावान ।।3।।

द्वारका माई मस्जिद से लखें, जो आठों याम ।
सो हमरी रक्षा करें, साई नाथ घनश्याम ।।4।।

कभी पुकारे भक्त तो, जो आयें तत्काल ।
सो हमरी रक्षा करें, साई परम कृपाल ।।5।।

एक दृष्टि से जो हरें, तन के क़ष्ट तमाम ।
सो हमरी रक्षा करें, ब्रह्म रूप साईराम ।।6।।

भिक्षा लेने आएं जो, करें दूर अज्ञान ।
सो हमरी रक्षा करें, साई नाथ भगवान ।।7।।

मनसा पूरी जो करें, भर दें घर–भंडार ।
सो हमरी रक्षा करें, दीनबंधु दातार ।।8।।

सभी इष्ट जिनमें बसें, जिनके हैं सब रूप ।
सो हमरी रक्षा करें, सकल सृष्टि के भूप ।।9।।

अहम हरें, सद्गुण भरें, दें करुणा का हाथ ।
सो हमरी रक्षा करें, साई सब के नाथ ।।10।।

जो समाधि से सक्रिय हैं, करें चित्र में वास ।
सो हमरी रक्षा करें, करें पूर्ण अभिलाष ।।11।।

सपनें में आ जाएं जो, ध्यान में दें जो भान ।
सो हमरी रक्षा करें, माता–पिता समान ।।12।।

जो हैं शामा के सखा, म्हालसापति के नाथ ।
सो हमरी रक्षा करें, सद्गुरु साई नाथ ।।13।।

रोग–शोक जो दूर करें, दें संकट को टाल।
सो हमरी रक्षा करें, दीनानाथ दयाल ।।14।।

जो बांटें उदी सदा, रक्खे सिर पे हाथ ।
सो हमरी रक्षा करें, रहें सर्वदा साथ ।।15।।

प्रसव–वेदना जो हरें, करें प्रसव आसान ।
सो हमरी रक्षा करें, बालक अपना जान ।।16।।

हरण किए जो पल भर में, सोमदेव के भरम ।
सो हमरी रक्षा करें, साई नाथ स्वयं ।।17।।

संगम जल जो टपकाए, दासगणु के हाथ ।
सो हमरी रक्षा करें, विष्णु रूप साई नाथ ।।18।।

बच्चे की रक्षा किए, हाथ धुनी में डाल ।
सो हमरी रक्षा करें, रक्षक साई कृपाल ।।19।।

सकल चराचर में बसें, समझें सबकी बात ।
सो हमरी रक्षा करें, सुबह–शाम अरु रात ।।20।।

ज्ञान दिए जो नाना को, किए अहम का नाश ।
सो हमरी रक्षा करें, अटल करें विश्वास ।।21।।

पल–पल जो रक्षा करें, सदा रहें जो साथ ।
सो हमरी रक्षा करें, समर्थ साई नाथ ।।22।।

जो निज तन में दिखलाएं, राम, कृष्ण, हनुमान ।
सो हमरी रक्षा करें, साई नाथ भगवान ।।23।।

दामू अण्णा को दिए जो संतति वरदान ।
सो हमरी रक्षा करें, साई सुहृद सुजान ।।24।।

मेघा को दर्शन दिए जो बनाया शम्भू महान ।
सो हमरी रक्षा करें, साई कृपानिधान ।।25।।

जिनके सुमिरन भजन से कृपा मिले भरपूर ।
सो हमरी रक्षा करें, करें कष्ट सब दूर ।।26।।

कृपा करें और राख लें जो भक्तों की लाज ।
सो हमरी रक्षा करें, साईनाथ महाराज ।।27।।

जो भक्तों पर दया करें, पावन करें हृदय ।
सो हमरी रक्षा करें, करें हमें निर्भय ।।28।।

जिनके भय से जादू–टोना, भूत–प्रेत हो नाश ।
सो हमरी रक्षा करें, हर लें सारा कष्ट ।।29।।

नारायण के रूप में, जो धारे नर तन ।
सो हमरी रक्षा करें, सुखद करें जीवन ।।30।।

जा के चरित–पारायण से सबका हो कल्याण ।
सो हमरी रक्षा करें, साई नाथ महान ।।31।।

बाला गनपत को मलेरिया से जो मुक्त किए ।
सो हमरी रक्षा करें, बिना विलंब किए ।।32।।

दत्तोपंत के पेट दर्द को, जो चट दूर किए ।
सो हमरी रक्षा करें, सटका हाथ लिए ।।33।।

जो काकाजी वैद्य के मन को शांत किए ।
सो हमरी रक्षा करें, बिना पुकार किए ।।34।।

जिनके सुमिरन से बजें, सारे बिगड़े काम ।
सो हमरी रक्षा करें, साईनाथ सुजान ।।35।।

सकल जगत में जिनके चलते बही प्रेम की धारा ।
सो हमरी रक्षा करें, हरें दर्द–दुख सारा ।।36।।

जिनकी महिमा गाकर–सुनकर भक्त परम सुख पाए ।
सो हमरी रक्षा करें, हमारा पर दया दिखाएं ।।37।।

जो नाना अरु दासगणु को दिए अभय वरदान ।
सो हमरी रक्षा करें, चिदानंद साईराम ।।38।।

जिनकी माता बायजाबाई, तात्या जिनका भाई ।
सो हमरी रक्षा करें, बैठ द्वारिकामाई ।।39।।

जो ढोते हैं भक्तों का सारा जीवन–भार ।
सो हमरी रक्षा करें, साई पतित उधार ।।40।।

श्रद्धा और सबुरी के संग, जो दें भक्ति महान ।
सो हमरी रक्षा करें, तम में ज्योति समान ।।41।।

जो सिखलाएं सादा जीवन, सच्चाई–ईमान ।
सो हमरी रक्षा करें, साई कृपानिधान ।।42।।

शरणागत के अपराधों को, क्षमा करें जो स्वामी ।
सो हमरी रक्षा करें, साई अंतर्यामी ।।43।।

शिरडी में जिनके दर्शन से जाएं सभी क्लेश ।
सो हमरी रक्षा करें, साईरूप गणेश ।।44।।

जिनकी कृपा से जन जाने घट में पूरन ब्रह्म ।
सो हमरी रक्षा करें, कर दें नष्ट अहम ।।45।।

जिनसे मिलती शांति सुरक्षा, जीवन में उत्थान ।
सो हमरी रक्षा करें, साई दत्त भगवान ।।46।।

परम ज्योति ही रूप है जिनका, जो जग का आधार ।
सो हमरी रक्षा करें, साई अगम अपार ।।47।।

जिनकी कृपा से जाता है, जन का मोह–अज्ञान ।
सो हमरी रक्षा करें, हमको अपना जान ।।48।।

जो है दाताओं का दाता, सब जग जिनके हाथ ।
सो हमरी रक्षा करें, बाबा साई नाथ ।।49।।

जिनकी इच्छा के बिना, कुछ भी नाही होय ।
सो हमरी रक्षा करें, परम सहायक होय ।।50।।

जिनके अंदर है जड़–चेतन, आज्ञा में जग सारा ।
सो हमरी रक्षा करें, साई राखनहारा ।।51 ।।

जिनका चिंतन करने से पूर्ण होय सब आस ।
सो हमरी रक्षा करें, साई परम प्रकाश ।।52।।

घट के भीतर ही जो बसता, जो है पालनहारा ।
सो हमरी रक्षा करें, साई प्राण प्यारा ।।53।।

सच्चे मन से हम दोहराएं, साई–साई–साई ।
रक्षा करने आओ साई, छोड़ द्वारकामाई ।।54।।

कृपा करो, करुणा बरसाओ, हे परमेश्वर साई ।
रक्षा करो हमारी, तुम ही एक सहारा साई ।। 55 ।।

हमारा हैं शरण तुम्हारी साई, हमें बचाओ साई ।
हमें संवारो, हमें सुधारो, रक्षा करो हमारी ।।56।।

साई रक्षा मंत्र तुम्हारा, कृपाशीष है साई ।
जो भी करे परायण, उसकी रक्षा करना साई ।।57।।

मनोकामना पूरी करना, करुणा करना साई ।
अपना बच्चा जान, मुक्ति का मार्ग दिखाना साई ।।58।।

श्री साई श्री साई साई श्री साई ।
जय साई जय साई साई जय साई।। ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर),
उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

आस्था

सिद्धिविनायक मंदिर

मनोकामनाएं हो जाती हैं पूरी

विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद अगर भक्तों को मिल जाए, तो आधी मुश्किल यूं ही आसान हो जाती है. सिद्धिविनायक मंदिर में नामचीन हस्तियां भी अपनी मुरादें लेकर आती हैं, तो क्यों न चलें हम भी, अपनी मनोकामनाएं लेकर सिद्धिविनायक के दर पर...

राजीव रंजन

धार्मिक और मंगल कार्यों में सफलता पाने के लिए श्री गणेश को सबसे पहले पूजा जाता है. चाहे शादी हो या विवाह या फिर गृह प्रवेश, हर शुभ कार्य को गणेश ही पार लगाते हैं. भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है. श्री गणेश के आशीर्वाद से हर शुभ कार्य बिना बाधा के ही पूरा हो जाता है. कार्य और मनोकामना सिद्ध करने वाले देवता होने के कारण ही वह सिद्धिविनायक कहलाते हैं. भारत में ऐसे बहुत ही कम मंदिर हैं, जहां हर धर्म के लोग दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन यह एक ऐसा मंदिर है, जिसके दर पर हर धर्म के लोग अपनी मुरादें पूरी होने की हसरत लिए जाते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं. इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि देश–विदेश से नामचीन हस्तियां यहां अपनी झोली फैलाए सभी के साथ खड़ी होती हैं. इस मंदिर का नाम है सिद्धिविनायक मंदिर, जो महाराष्ट्र के मुंबई में दादर प्रभादेवी में स्थित है. यह मंदिर लगभग दो शताब्दी पुराना है. इस मंदिर से देश ही नहीं, विदेशी धर्मावलंबियों की आस्था और श्रद्धा भी जुड़ी है. भगवान गणेश महाराष्ट्र ही नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवताओं में एक माने जाते हैं. हालांकि महाराष्ट्र के लोगों में गणेश पूजा ख़ासा प्रचलित है.

इस मंदिर में भगवान गणेश की अति सुंदर प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई है, जो देखने में बहुत ही मनभावन लगती है. इस मंदिर के गर्भगृह के लकड़ी के दरवाज़ों पर अष्टविनायक की छाप देखने को मिलती है. मंदिर की शिल्पकारी पूरे मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देती है. मंदिर की छतें स्वर्ण निर्मित हैं. जब इन छतों पर लाइट पड़ती है, तो यह देखने में अति सुंदर लगती हैं और इनकी चमचमाहट हमें बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है.

मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश की मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया गया है. हिंदू मंदिरों में प्राय: देखा गया है कि भगवान के हाथों की संख्या दो से अधिक होती है. यहां भी भगवान गणेश को विभिन्न हाथों के साथ दिखाया गया है. गणेश के ऊपरी दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में अंकुश है और नीचे के दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में लड्डुओं से भरा कटोरा है. प्राचीन ग्रंथों में गणेश की दो पत्नियों के बारे में बताया गया है, जिनका नाम है रिद्धि और सिद्धि, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये धन, ऐश्वर्य, सफलता और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं. भगवान गणेश के बाएं भाग में सिद्धि और दाएं भाग में रिद्धि का वास माना जाता है. यही कारण है कि श्री

सिद्धिविनायक मंदिर

सिद्धिविनायक की आराधना और दर्शन से मन और बुद्धि का जागरण होता है.

महत्ता

वैसे तो गणेश के विभिन्न रूप हैं, लेकिन इन सबमें सबसे विशिष्ट रूप उनका सिद्धिविनायक है. हम देखते हैं कि गणेश जी की प्रतिमाओं की सूड़ दाईं तरफ मुड़ी होती है, वास्तव में वह सिद्धपीठ से जुड़ी होती है. कहा जाता है कि सिद्धिविनायक भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है. मान्यता तो यहां तक है कि सिद्धिविनायक गणपति के वह रूप हैं, जो प्रसन्न भी बहुत जल्द होते हैं और कुपित भी बहुत जल्द होते हैं.

सिद्ध–पीठ से कम नहीं

सिद्धिविनायक चतुर्भुजी विग्रह हैं. भले ही सिद्धिविनायक की गिनती महाराष्ट्र के आठ गणेश सिद्ध–पीठ स्थलों में नहीं होती. बावजूद इसके, इस मंदिर की महता बहुत ज़्यादा है. तभी तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, सलमान ख़ान और ऐश्वर्या राय जैसी हस्तियां इस मंदिर के दर पर शिश झुकाने हमेशा जाती रहती हैं. सचमुच अष्टविनायकों से अलग होते हुए भी इस मंदिर की महत्ता किसी सिद्ध–पीठ से कम नहीं.

कब जाएं

इस मंदिर के दर्शन के लिए आप किसी भी दिन जा सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन इस मंदिर में बड़े पैमाने पर श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. हालांकि मंगलवार के दिन यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. हर साल गणपति पूजा महोत्सव यहां भाद्रपद की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक धूमधाम से मनाया जाता है. इस मंदिर में अंगारकी और संकाष्टि चतुर्थी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. सिद्धिविनायक मंदिर तक एक संकरी गली जाती है, जिसे फूल गली के नाम से जाना जाता है. पूरा रास्ता ही पूजन सामग्री की दुकानों से पटा पड़ा है.

धन–धान्य से भरपूर

सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इस मंदिर में हर साल लगभग 52 करोड़ रुपये की आय होती है और 10–15 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष चढ़ावा चढ़ाया जाता है. इसकी गिनती महाराष्ट्र के दूसरे सबसे अमीर मंदिरों में होती है.

कैसे पहुंचें

आप हवाई, रेल और सड़क के रास्ते यहां आसानी से पहुंच सकते हैं. चूंकि यह मुंबई में स्थित है, इसलिए देश के किसी भी बड़े शहर से रेल यातायात से पहुंचना आसान है. छोटे शहरों से भी मुंबई के लिए रेलगाड़िया चलती हैं. हवाई यातायात के लिए भी मुंबई सुगम है. देश के अन्य शहरों से टूरिस्ट बसें भी चलती हैं.

कहां ठहरें

ठहरने के लिए यहां धर्मशालाएं और होटलों की कोई कमी नहीं है. जलपान और खाने–पीने के लिए रेस्तरां और होटल भी उपलब्ध हैं. बड़ा पाव मुंबई में काफ़ी चर्चित है, जिसका लुत्फ उठाया जा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक बार

मूर्ख ब्राह्मण

किसी गांव में संभुदयाल नामक एक ब्राह्मण रहता था. एक बार वह अपने यजमान से एक बकरा लेकर अपने घर जा रहा था. रास्ता लंबा और सुनसान था. आगे जाने पर रास्ते में उसे तीन ठग मिले. ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर तीनों ने उसे हथियाने की योजना बनाई.

एक ने ब्राह्मण को रोककर कहा, पंडित जी यह आप अपने कंधे पर क्या उठा कर ले जा रहे हैं. यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधों पर बैठा कर ले जा रहे हैं. ब्राह्मण ने उसे झिड़कते हुए कहा, अंधा हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता, यह बकरा है.

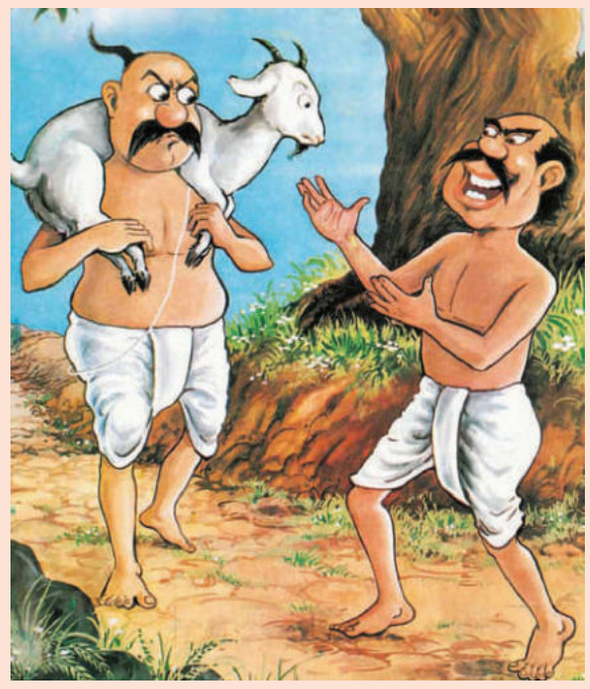

पहले ठग ने फिर कहा, खैर मेरा काम आपको बताना था. अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर ले जाना है, तो मुझे क्या? आप जानें और आपका काम. थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला. उसने ब्राह्मण को रोका और कहा, पंडित जी, क्या आपको पता नहीं कि उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं लादना चाहिए.

पंडित उसे भी झिड़क कर आगे बढ़ गया. आगे जाने पर उसे तीसरा ठग मिला. उसने भी ब्राह्मण से उसके कंधे पर कुत्ता ले जाने का कारण पूछा. इस बार ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि उसने बकरा नहीं, बल्कि कुत्ते को अपने कंधे पर बैठा रखा है. थोड़ी दूर जाकर, उसने बकरे को कंधे से उतार दिया और आगे बढ़ गया. इधर, तीनों ठग ने उस बकरे को मार कर ख़ूब दावत उड़ाई. ■

शिक्षा : अपने दिमाग़ से काम लें और अपने आप पर विश्वास करें.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

समीक्षा

बुजुर्ग गीतकार का यह पहला ही गीत संग्रह है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद लगता है कि यह कई वर्षों के अनुभव के बाद लिखी गई रचना है. गीत के बोल बहुत ही मिठास लिए हुए हैं. इसमें उनके जीवन के 5 दशकों के लंबे अंतराल के गीत संकलित हैं, जो पाठकों को सुखद अनुभूति का एहसास कराते हैं.

कविता

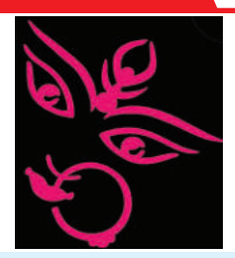

छद्मनामी लेखन का तिलिस्म

इन दिनों मशहूर ब्रिटिश उपन्यासकार जेके रॉलिंग ने अपने क्राइम थ्रिलर–द कुक्कूज कॉलिंग को छद्म नाम से लिखा है. यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि फैंटेसी लेखिका रॉलिंग को पाठक ज़्यादा पसंद करते हैं या क्राइम थ्रिलर लेखिका को पाठकों का ज़्यादा प्यार मिलता है.

अनंत विजय

अंग्रेजी साहित्य में इन दिनों एक दिलचस्प वाकये पर जमकर चर्चा हो रही है. चर्चा के केंद्र में हैं, जे के रॉलिंग. जेके रॉलिंग ब्रिटिश उपन्यासकार हैं और उनके हैरी पॉटर सीरीज ने दुनिया भर में धूम मचाई हुई है. पिछले सोलह साल से रॉलिंग साहित्य की दुनिया में अपना राज कायम रखे हुए हैं, लेकिन इन दिनों रॉलिंग गुस्से में हैं. हुआ यह है कि जेके रॉलिंग ने रॉबर्ट गॉलब्रेथ के नाम से एक क्राइम थ्रिलर–द कुक्कूज कॉलिंग लिखा. माना यह गया कि इस क्राइम थ्रिलर का लेखक सेना या फिर नागरिक सुरक्षा से जुड़ा कोई ऐसा शख्स है, जो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता है. आलोचकों ने रॉबर्ट गॉलब्रेथ की जमकर सराहना की. इस बीच एक अखबार ने ख़ुलासा कर दिया कि रॉबर्ट गॉलब्रेथ दरअसल कोई और नहीं, बल्कि जेके रॉलिंग हैं. उसके बाद तो साहित्य की दुनिया में भूचाल आ गया. कुछ लोगों ने जेके रॉलिंग पर छद्म नाम से लेखन कर पैसे कमाने का आरोप भी जड़ा. आलोचना बढ़ता देख रॉलिंग ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही रॉबर्ट गॉलब्रेथ के नाम से उपन्यास लिखा था. अब तक होता यह रहा है कि जेके रॉलिंग के नए उपन्यास का आना अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में खबर होती थी. रॉलिंग का कहना है कि इससे उन पर एक खास तरह का दबाव होता था, जो छद्म नाम से लिखने पर नहीं था. रॉलिंग स्वीकार करती हैं कि जब उपन्यास को पाठकों के साथ–साथ आलोचकों ने स्वीकार किया, तो उन्हें एक विशेष प्रकार की अनुभूति हुई थी और वह इसका आनंद उठा रही थी.

जेके रॉलिंग का नाम खुलने के पीछे भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है. जेके रॉलिंग जिस लीगल फर्म की क्लाइंट हैं, उस फर्म के एक वकील ने यूं ही बातों ही बातों में अपनी पत्नी की दोस्त को बता दिया कि क्राइम थ्रिलर द कुक्कूज कॉलिंग के लेखक रॉबर्ट गॉलब्रेथ के नाम से जेके रॉलिंग ने ही यह उपन्यास लिखा है. उस मुलाकात के बाद वकील साहब की पत्नी की दोस्त ने ट्वीट कर दिया कि चर्चित उपन्यास द कुक्कूज कॉलिंग की असली लेखिका जेके रॉलिंग हैं. उस ट्वीट से क्लू लेते हुए अखबार ने यह ख़बर छाप दी. बाद में क़ानूनी फर्म ने यह स्वीकार किया कि उसके पार्टनर से यह ग़लती हुई है और उसके लिए उन्होंने जेके रॉलिंग से माफी भी मांग ली है, लेकिन रॉलिंग ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि एक ऐसी महिला ने उसके सबसे बड़े राज का फ़ाश कर दिया, जिसको वह जानती तक नहीं. खैर, अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में यह दिलचस्प प्रसंग चल रहा है. ऐसा नहीं है कि साहित्य की दुनिया में यह इकलौता वाकया हो. पहले भी हर भाषा में लेखक छद्म नाम से लेखन करते रहे हैं. छद्म नाम से लेखन के पीछे भी वही मानसिकता काम करती है, जो कि फिल्मों में हीरो के एक ही तरीक़े के रोल निभाने को विवश कर देती है और वो टाइप्ड हो जाते हैं. लेखन की दुनिया में भी ऐसा ही होता है. प्रकाशक क्राइम फिक्शन लिखने वाले लेखक से रोमांटिक लेखन या फिर फैंटेसी लेखक से क्राइम फिक्शन की अपेक्षा नहीं करते हैं. अगर कोई लेखक इस तरह का जोखिम मोल लेना चाहते हैं, तो प्रकाशक उसे हतोत्साहित करते हैं और यहीं से छद्म नाम से लिखने की शुरुआत होती है. अंग्रेजी में तो चार्ल्स डिकेंस से लेकर स्टेनली मार्टिन तक ने छद्म नाम से लेखन किया है. स्टेनली मार्टिन ने तो स्टेनली के नाम से लंबे समय तक कॉमिक्स लिखा और स्पाइडरमैन जैसे चरित्र की रचना की.

हिंदी साहित्य में भी छद्म नाम से लेखन की बेहद लंबी परंपरा रही है. अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, जबकि हिंदी में कहानी लेखिका स्नोबा बार्नो की पहचान को लेकर ख़ासा विवाद हुआ था. कई खोजी तो स्नोबा की तलाश में कुल्लू और मनाली की वादियों तक जा पहुंचे थे. स्नोबा बार्नो के नाम से जब पहली कहानी हंस में छपी, तो उसने पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. कहानी लोगों को पसंद आई, तो कहानीकार पर चर्चा शुरू हुई. कहानीकार के बारे में पता लगाने की कोशिशें शुरू हुईं, लेकिन हिंदी जगत में स्नोबा एक मिस्ट्री बनी रहीं. स्नोबा की कहानियों से ज़्यादा उसके होने या न होने पर चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों ने कहा कि सैन्नी अशेष स्नोबा के नाम से लिखते हैं, लेकिन वह भी सिर्फ कयासबाजी ही साबित हुई. अब भी स्नोबा की कहानियां छप रही हैं, लेकिन स्नोबा को किसी ने देखा नहीं है. लिहाजा, उसके बारे में तरह–तरह की कयासबाजी समय–समय पर होती रहती है. 1957 में जब विष्णुचंद्र शर्मा ने–कवि–पत्रिका निकाली थी, तो उसमें नामवर जी कवि मित्र के छद्म नाम से एक विशेष कालखंड में लिखी गई कविताओं पर टिप्पणी करते थे. उस स्तंभ की काफ़ी चर्चा होती थी. बहुत बाद में जाकर भेद खुला कि कवि मित्र असल में नामवर सिंह हैं. मुझे लगता है कि छद्म नाम से लेखन के पीछे एक मानसिकता यह भी होती है कि अपने समकालीनों पर तल्ख टिप्पणी की जा सके और उनके गुस्से से बचा भी जा सके. हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका कल्पना में अज्ञेय भी कुट्टीचातन के नाम से लेखन किया करते थे. आलोचना की पत्रिका कसौटी के अंकों में विवेक सिंह के नाम से उसके संपादक नंदकिशोर नवल आलोचनात्मक टिप्पणियां लिखा करते थे. बाद में उन्होंने ख़ुद ही स्वीकार किया था कि विवेक सिंह के नाम से वही लिखा करते थे. इसके अलावा, साहित्य की गतिविधियों पर भारत भारद्वाज भी ब्रह्मराक्षस के नाम से–दुनिया इन दिनों–नाम की पत्रिका में लोगों की ख़बर लिया करते थे. हिंदी के आलोचक और प्रतिष्ठित लेखक सुधीश पचौरी अब भी अजदक के छद्म नाम से मीडिया पर टिप्पणी करते हैं. हालांकि सालों पहले उनका नाम खुल चुका है, लेकिन स्तंभ अजदक के नाम से ही जारी है. इतनी लंबी सूची गिनाने का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ यह है कि साहित्य में कई बार अपनी छवि के विपरीत लेखन के लिए, तो कई बार साथी लेखकों के कोप से बचने के लिए, तो कई बार लेखन की वस्तुनिष्ठता को बचाए रखने के लिए छद्म नाम से लेखन का सहारा लिया जाता है. साहित्य की परंपरा को ही जेके रॉलिंग ने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और उनकी योजना रॉबर्ट गॉलब्रेथ के नाम से और कई उपन्यास लिखने की थी, जो अब शायद ही परवान चढ़ सके. हालांकि इस ख़ुलासे के बाद द कुक्कूज कॉलिंग की बिक्री और बढ़ गई है, क्योंकि उसके साथ जे के रॉलिंग का नाम जुड़ गया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि फैंटेसी लेखिका रॉलिंग को पाठक ज़्यादा पसंद करते हैं या क्राइम थ्रिलर लेखिका को पाठकों का प्यार मिलता है, क्योंकि क्राइम थ्रिलर में रॉलिंग का मुक़ाबला जेम्स पैटरसन जैसे मशहूर अमेरिकी लेखक से होगा. आलोचकों के सामने भी रॉलिंग को उसके नये अवतार में परखने की चुनौती होगी. जो भी हो, लेकिन विमर्शकारों के सामने आने वाले दिनों में रॉलिंग और चुनौतियां पेश कर सकती हैं. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

कविता

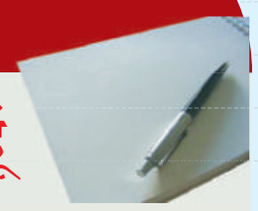

मैं ही वह नारी हूं

राजीव रंजन

कहीं जल रही हूं
कहीं बुझ रही हूं
कहीं ठोकरें खा रही हूं
कहीं प्यार के बदले
ग्लानि–पीड़ा पा रही हूं
सब दुःख सहना
चुप ही रहना
मैं ही वह नारी हूं
खिलौना कहते हो मुझको
बालक कहते हो खुद को
खेल कर जब हार गए
तो अबला कहते हो मुझको
प्रताइना हो मुझे कहीं
कभी नहीं तुम चुकते हो
क्या यही है तेरा स्तर
हैवानों से भी बदतर
मां तुम्हे धिक्कार गई
बहनें मुंह छुपा गईं
जिनसे पहचान बनाते हो
उन्हीं का अस्तित्व मिटाते हो
कलंक क्यों सर लगाते हो
दानव बनके फिरते हो
कहीं नही तेरी पहचान
हर जगह हो अंजान
इसीलिए तो कहती हूं
तू मुझमें है, तू मुझसे है
कई रूपों में देखे हो जिसको
मैं ही वह नारी हूं. ■

किताब मिली

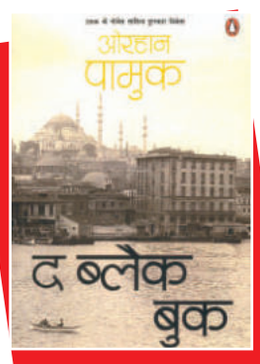

पुस्तक	लेखक
द ब्लैक बुक	ओरहान पामुक
प्रकाशक	मूल्य
पेंगुइन बुक्स	399

यह शानदार जासूसी उपन्यास है, जिसने जासूसी उपन्यास के अंदाज को बहुत ही निराले ढंग में प्रस्तुत किया है. इसे पढ़ने के दरम्यां पाठक के मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

समीक्षा

संथाल की सोंधी खुशबू

एस. बिजेन सिंह

मन को दो भीगने, पुस्तक एक गीत संकलन है, जिसे 84 पृष्ठों में बुना गया है. इसके लेखक हैं तारा चरण खवाड़े. इस संकलन में 75 वर्षीय हिंदी के स्थापित गीतकार प्रो. तारा चरण खवाड़े के 65 गीत संकलित हैं. बुजुर्ग गीतकार का यह पहला ही गीत संग्रह है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद लगता है कि यह कई वर्षों के अनुभव के बाद लिखी गई रचना है. गीत के बोल बहुत ही मिठास लिए हुए हैं. इसमें उनके जीवन के 5 दशकों के लंबे अंतराल के गीत संकलित हैं, जो पाठकों को सुखद अनुभूति का एहसास कराते हैं. प्रो. खवाड़े हिंदी के प्रसिद्ध अध्यापक रहे हैं. मंचों पर अपने गीतों की ख़ूबसूरत अदायगी के लिए भी वह चर्चित रहे हैं. देवघर संथाल परगना अंचल में आता है. इस संकलन के कुछ गीत संथाल संस्कृति की निश्छलता का हृदयग्राही चित्र खींचते हैं, जिससे संथाल परगना की मिट्टी की सोंधी खुशबू बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है. पुराने पारंपरिक गीत भी स्तरीय हैं. उनका छंद कसा हुआ है और भाषा बहुत ही प्रवाहमान है. ये गीत सहज ही हृदय में उतर आते हैं. प्रख्यात गीतकार डॉ शंकरमोहन झा ने ठीक ही लिखा है कि यह संकलन ठाकुर प्रसाद सिंह के *वंशी और मादल* के प्रयोगों का सुफल है. यह संकलन एक तरह से हिंदी की समूची गीतयात्रा का प्रमाणिक दस्तावेज बन कर आया है. इसमें गीतकार के लगभग दर्जन भर गीत नई शताब्दी के आसपास के हैं. इन गीतों में नवगीत की महक मिलती है. गीत की सारी विशेषताएं गीतप्रेमी प्रबुद्ध पाठक इस संकलन में पाएंगे. गीत की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं :

नव पल्लव–सा यह तन
क्वांरा, चंदन–सा मन
खोपे में 'दुधी फूल' धरती–सा लहंगा है
इनका जो 'पन' दे दो
पन के संग मन दे दो
अल्हड़ इस यौवन का प्यार बड़ा महंगा है
वायदों की नागफनी में अब उरझाओ ना
वंशी बजाओ ना, वंसी लगाओ ना ।।

समीक्ष्य कृति : मन को दो भीगने
लेखक : तारा चरण खवाड़े
प्रकाशक : भारती
क़ीमत : 100 रुपये

विशेषांक : पूर्वोतर छात्र मिलन समारोह

हिंदी विद्यापीठ पत्रिका

हिंदी विद्यापीठ पत्रिका झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी वैद्यनाथ देवघर से निकलने वाली एक स्तरीय त्रैमासिक शोध पत्रिका है. इस पत्रिका का यहां उल्लेख करना इसलिए उचित लगता है कि इस पत्रिका ने हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार में महती योगदान दिया है. यह पत्रिका हिंदी विद्यापीठ से प्रकाशित होती है, जो हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार के लिए प्रतिबद्ध एक राष्ट्रीय संस्था है. वहां के आवासीय महाविद्यालय में उत्तर–पूर्व के छात्र–छात्राओं के लिए हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन का सुंदर प्रबंध किया गया है, जो लगभग चार दशकों से चला आ रहा है. इस बार विद्यापीठ में 6 अप्रैल, 2013 को पूर्वोत्तर छात्रों के बीच पूर्ववर्ती छात्र–छात्राओं का मिलन समारोह आयोजित हुआ था. इस अवसर पर इस पत्रिका का विशेषांक प्रकाशित हुआ था. 1947 में इसी संस्था के छात्रों द्वारा निकाली जा रही हस्तलिखित पत्रिका की सामग्री के साथ–साथ पूर्ववर्ती छात्रों और वर्तमान छात्रों का आलेख उनके प्राध्यापकों के साथ शामिल है. पत्रिका पठनीय है और उत्तर–पूर्व के छात्रों के साथ–साथ हिंदी भाषा सीखने के उत्सुक अन्य हिंदी से अलग प्रदेश के लोगों के लिए भी उपयोगी है.

बहरहाल, हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1929 में हुई. 1975 से पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र–छात्राएं यहां हिंदी सीखने के लिए आते रहे हैं और आज भी यह परंपरा जारी है. नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम के छात्र–छात्राएं भारत सरकार की योजना के अंतर्गत यहां हिंदी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. यहां से शिक्षण प्राप्त कर ये अपने–अपने राज्यों में जाकर हिंदी के प्रसार–प्रसार के क्षेत्र में कार्य करते हैं. यह संस्थान हिंदी भाषियों के लिए एक मिल स्तंभ का कार्य करता आ रहा है, जो हिंदी के विशाल क्षेत्र का निर्माण करता है. आप इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 1975 ई के पूर्व भी बालशौरी रेड्डी, चलसानि सुब्बाराव, के गोपालन, प्रफुल्लचंद्र पट्टनायक जैसे छात्र यहां रहकर हिंदी की शिक्षा प्राप्त करते रहे और देश के शीर्षस्थ पदों पर काम कर उन्होंने यहां का लोहा मनवाया. आज हिंदी साहित्य में ये अक्षर पुरुष के रूप में गिने जाते हैं. पूर्वोत्तर छात्रों का यह सम्मेलन हिंदी विद्यापीठ के लिए गौरवपूर्ण क्षण था. इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर छात्रों के साथ दक्षिणी राज्यों के कुछ छात्र भी यहां शिक्षा प्राप्त करते रहे. इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र–छात्राएं तथा इस क्षेत्र में कार्यरत हिंदी के मनीषीगण यहां पधारे हुए थे. 1950–51 में श्री ठाकुर प्रसाद सिंह ने मुद्रित रूप में हिंदी विद्यापीठ पत्रिका की शुरुआत की, लेकिन उनके पूर्व भी यहां के छात्र 1947 के पूर्व से ही हस्तलिखित पत्रिका निकालते रहे. हस्तलिखित पत्रिका की परंपरा किसी भी संस्था के लिए गौरव का विषय है. 1947 की फरवरी में निकाली गई एक वैसी ही हस्तलिखित पत्रिका के चौथे अंक से पूर्व छात्रों और शिक्षकों की कुछ सामग्री लेकर इस अंक को पूर्णता देने का प्रयास किया गया है. डॉ लक्ष्मीनारायण सुधांशु द्वारा लिखित उक्त पत्रिका के संपादकीय संदेश को उन्हीं की हस्तलिपि में हू–ब–हू अंक में लिया गया है. इस अवसर पर डॉ. अशोक वाजपेयी, कुलाधिपति, हिंदी विद्यापीठ (देवघर), डॉ. पद्म नारायण, कुलपति (देवघर) भी उपस्थित थे. ■

sbijensngh@gmail.com

कुकटॉप में एलईडी संकेतक और 4 प्री–एडजस्टेड कुकिंग मोड्स हैं, जो कुकिंग के दौरान सुविधा प्रदान करते हैं और किसी भी अनिश्चितता को कम करते हैं. सुरक्षा के लिहाज से सोएर की ऑटो शट ऑफ विशिष्टता आपको किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाता है.

टाटा का जिंजर

नोएडा सेक्टर 63 में टाटा ने जिंजर समूह के अंतर्गत एक और होटल खोला. 83 कमरों वाले इस होटल को काफी शानदार बनाया गया है...

नोएडा सेक्टर 63 में टाटा ने जिंजर समूह के होटल का उद्घाटन किया. 83 कमरों वाले इस होटल को काफी शानदार बनाया गया है. इस मौके पर रूट्स कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके मोहन कुमार ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 63 में खुलने वाला जिंजर होटल एनसीआर में इस समूह का पांचवां होटल है. इससे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पूर्वी दिल्ली, मानेसर और फरीदाबाद में जिंजर होटल खुल चुका है. एनसीआर के ही ग्रेटर नोएडा भी एक जिंजर होटल बन रहा है, जिसे इसी वित्त वर्ष के अंत तक खोल दिया जाएगा. स्मार्ट बेसिक्स की संकल्पना पर आधारित इस होटल में स्मार्ट और बेहतरीन सेवाएं दी जाएंगी. नोएडा के बिजनेस ट्रेवलर्स के लिए यह होटल काफी उपयुक्त होगी, क्योंकि इस शहर में सूचना तकनीक, लाइफ साइंस, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोटिव जैसे इंडस्ट्रीयल हब है. कंपनी इसी वर्ष जयपुर, अमृतसर और चंडीगढ़ में भी जिंजर होटल खुल जाएंगे जो कि कंपनी की छवि के अनुरूप विकसित किए जा रहे हैं. गौरतलब है कि सात वर्ष पहले जिंजर होटल ने अपना पहला होटल खोला था. आज पूरे देश में इसके 28 होटल चल रहे हैं. ■

2जी के दाम में 3जी इंटरनेट सेवा

अब मात्र 123 रुपये में 1 जीबी, 246 रुपये में 2 जीबी और 492 रुपये में 4 जीबी डेटा रिलायंस 3जी में मिलेगा. रिलायंस का ये ऑफर नये और पुराने, पोस्टपेड और प्री-पेड दोनों तरह के ग्राहकों के लिए हैं.

रिलांयस कम्यूनिकेशन ने 3जी इंटरनेट के दामों में पचास प्रतिशत तक की कमी कर दी है. अब 2जी के दामों में 3जी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी. 3जी इंटरनेट की सेवाओं में एक बड़ा दांव खेलते हुए रिलायंस ने अपने उपभोक्ताओं को सस्ते दामों में 3जी सेवा देने का फैसला किया है.

अब मात्र 123 रुपये में 1 जीबी, 246 रुपये में 2 जीबी और 492 रुपये में 4 जीबी डेटा 3जी में मिलेगा. रिलायंस के ये ऑफर नये और पुराने, पोस्टपेड और प्री–पेड दोनों तरह के ग्राहकों के लिए है. अभी तक भारत में सिर्फ 5 प्रतिशत नेट उपभोक्ता 3जी का इस्तेमाल करते हैं. रिलायंस कंपनी के अधिकारियों का कहना था कि हमारा मकसद हर स्मार्टफोन और टैबलेट में तेज स्पीड नेट पहुंचाना है.

ज्यादा कीमत के कारण उपभोक्ता 3जी का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए ही रिलायंस ने यह कदम उठाया है. जो ग्राहक अभी तक ज्यादा कीमत के कारण रिलांयस के 3जी से दूरी बनाए हुए थे, उनके लिए यह सुनहरा मौका है. ■

बेहतरीन साउंड के साथ फिलिप्स

अगर आप बेहतरीन साउंड क्वालिटी के शौकीन हैं और बिना तारों के झंझट के अपने टीवी में बेहतर साउंड चाहते हैं, तो फिलिप्स का यह गैजेट आप ही के लिए बना है. फिलिप्स ने अपने इस ब्लूटुथ कनेक्टेड साउंड बार में डबल बेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है. इसकी विंग शेप डिजाइन इसको दीवार या टेबल पर रखने के लिए उपयुक्त बनाती है. इसका ड्यूल 60 वॉट का स्पीकर इसके साउंड को ज्यादा बेहतर बनाता है. इसका डॉल्बी डिजिटल 5.1 तकनीक टीवी की आवाज को सराउंड साउंड की तरह फील कराएगी. कंपनी ने इसकी कीमत 23 हजार रुपये रखी है. ■

स्टड निंजा 3 जी हेलमेट

स्टड कंपनी के इस हेलमेट में इतनी ज्यादा खूबियां हैं कि आप इसे झट से खरीद लेंगे. कंपनी अपने इस प्रोडक्ट पर एक साल की वारंटी दे रही है. इसका वजन 350 ग्राम है. इसकी पैडिंग पर ऐसे कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, जो एंटी एलर्जिक है. स्टड का यह हेलमेट भी स्क्रैच फ्री क्वालिटी के साथ है. यह हेलमेट कई रंगों में मौजूद है. कंपनी ने इस हेलमेट की कीमत 1500 रुपये रखी है. ■

कुकिंग हुई आसान

घरेलू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी सोएर एवं प्रमुख कारोबारी समूह एफएआइपीएल (फेंडा ऑडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने इंडक्शन कुकटॉप की नई श्रृंखला पेश की है. यह नई श्रृंखला फाइटर सीरीज आइएन 1500 आपकी कुकिंग को काफी आसान बना देगा. आइएन 1500, 1400 वाट की ऊर्जा पर कार्य करता है. यह पारंपरिक गैस स्टोव्स को पीछे छोड़कर रोजाना खाना बनाने के कार्य को एक मनोरंजक गतिविधि में तब्दील कर देगा. इसकी सतह ब्लैक क्रिस्टल का है, जो सुपर हीट प्रतिरोधी है. यह खाना भी जल्दी पकाएगा. आपकी जरूरतों के मुताबिक सोएर आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए सदैव तत्पर रहता है. कुकटॉप में एलईडी संकेतक और 4 प्री-एडजस्टेड कुकिंग मोड्स हैं, जो कुकिंग के दौरान सुविधा प्रदान करते हैं और किसी भी अनिश्चितता को कम करते हैं. सुरक्षा के लिहाज से सोएर की ऑटो शट ऑफ विशिष्टता आपको कुकिंग के दौरान होने वाली किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचाएगा. यह खाने को एकसमान गर्म करता है. कुकटॉप का नया संपूर्ण पैकेज-7 विभिन्न भारतीय कुकिंग मोड्स और विभिन्न तापमान को सुनिश्चित करते हैं. सोएर आइएन 1500-फाइटर सीरीज की कीमत 1990 रुपये है.यह आपकी रसोई के लिए प्रभावशाली, झंझट मुक्त, एक-स्रोत समाधान है. अपने बजट को सुधारने के लिए यह विकल्प अपनाइए. ■

गूगल का टैबलेट

गूगल के प्ले स्टोर पर अभी इसकी कीमत कम नहीं हुई है. पुराने नेक्सस 7 में 216 पिक्सल/इंच पिक्सल डेंसिटी और 1280-800 पिक्सल एचडी डिस्प्ले वाला 7 इंच का डिस्प्ले है. इसमें एनवीडिया टेग्रा 3 क्वाड-कोर प्रोसेसर और 1 जीबी रैम है.

गूगल ने पिछले हफ्ते नया टैबलेट लॉन्च किया है. हालांकि यह अभी भारत में नहीं आया है, लेकिन भारत में पुराना नेक्सस 7 कम कीमत पर मिलने लगा है. ऑनलाइन रीटेल वेबसाइट अमेजन इंडिया पर 15,999 रुपए वाले पुराने नेक्सस 7 टैबलेट (16 जीबी) की कीमत 11,999 रुपए तक आ गई है. वेबसाइट पर 18,999 रुपए वाले नेक्सस 7(32 जीबी) की कीमत 15,999 रुपए है. हालांकि गूगल के प्ले स्टोर पर अभी इसकी कीमत कम नहीं हुई है. पुराने नेक्सस 7 में 216 पिक्सल/इंच पिक्सल डेंसिटी और 1280–800 पिक्सल एचडी डिस्प्ले वाला 7 इंच का डिस्प्ले है. इसमें एनवीडिया टेग्रा 3 क्वाड–कोर प्रोसेसर और 1 जीबी रैम है. 4325 एमएच बैटरी है. नए नेक्सस 7 में 323 पीपीआई पिक्सल डेंसिटी के साथ 1920 –1200 पिक्सल का फुल एचडी रेजॉलूशन है. इसमें 1.5 गीगाहर्त्ज क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन एस4 क्वॉड–कोर प्रोसेसर और 2 जीबी रैम है. इसमें एड्रिनो 320 जीपीयू (ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट) है. नए नेक्सस में पहले के नेक्सस से 1.8 गुना तेज प्रोसेसर और 4 गुना तेज जीपीयू है. ■

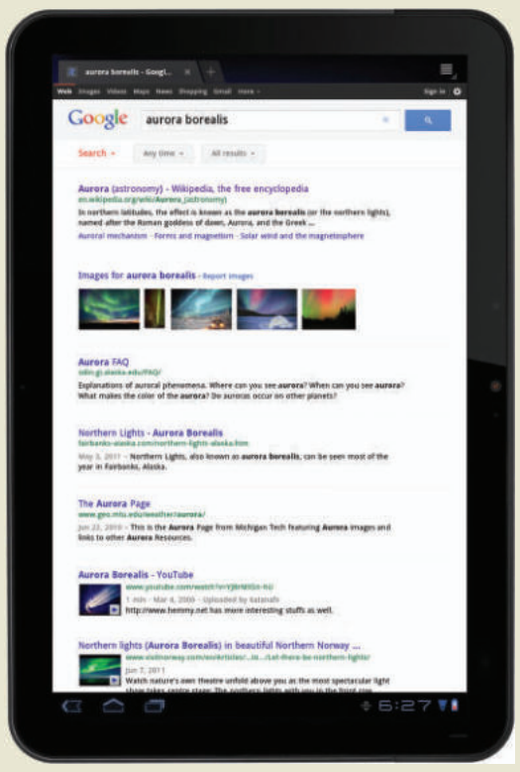

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

पॉल्यूशन फ्री बस

टाटा मोटर्स लिमिटेड और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) ने देश में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली बस बनाई है. कई साल के रिसर्च के बाद यह बस बनाई गई. इस बस का प्रदर्शन तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो के केंद्र लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर में किया गया.

अधिकारियों ने बताया कि यह सीएनजी से चलने वाली बस की तरह ही है. हाई प्रेशर में भी हाइड्रोजन की बोतल बस की छत पर होती है. इससे किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता. हाइड्रोजन सेल क्रायोजनिक टेक्नोलॉजी का एक सब–प्रॉडक्ट है, जिसे इसरो पिछले कई सालों से विकसित कर रही है. यह पूरी तरह से क्रायोजनिक टेक्नोलॉजी नहीं है. यह लिक्विड हाइड्रोजन हैंडलिंग है, जिसमें इसरो को महारत हासिल है. इसरो और टाटा मोटर्स ने हाइड्रोजन से चलने वाली बस के विकास के लिए 2006 में समझौता किया था. इसरो के मानद सलाहकार वीजी गांधी और टाटा मोटर्स के डेप्यूटी जनरल मैनेजर डॉक्टर एम राजा ने यह घोषणा की. भारत में पहली बार ऐसी ईंधन सेल बस बनी है जो हाइड्रोजन से चलती है. गांधी ने कहा कि फ्यूचर के ट्रांसपोर्ट के लिहाज से यह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा कदम है. इस गाड़ी से किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

> जांच आयोग ने आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स के मालिक और इंडिया सीमेंट लिमिटेड के चेयरमैन एवं बीसीसीआई के निर्वासित अध्यक्ष एन श्रीनिवासन, उनके दामाद और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सह-मालिक राज कुंद्रा के खिलाफ स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच की थी.

बीसीसीआई

बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोवर्सी इन इंडिया

बीसीसीआई को अगर बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोवर्सी इन इंडिया कहा जाए, तो ग़लत नहीं होगा, क्योंकि बीसीसीआई क्रिकेट को लेकर कम और फिक्सिंग जैसे अन्य विवादास्पद गतिविधियों को लेकर ज़्यादा सुर्ख़ियों में रहता है. बीसीसीआई की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाने की ही नहीं है, बल्कि खेल को साफ़-सुथरा रखने और लोगों के बीच खेल के प्रति विश्वास बनाए रखने की भी है. सवा अरब क्रिकेट प्रेमियों वाले बीसीसीआई को अब खेल प्रेमियों के प्रति जवाबदेह होना ही होगा...

नवीन चौहान

बीसीसीआई क्रिकेट के मैदान के बाहर की गतिविधियों को लेकर सुर्ख़ियों में है. जब से आईपीएल-6 में स्पॉट फिक्सिंग का ख़ुलासा हुआ है, तब से हर तरफ़ से बीसीसीआई की कार्यप्रणाली को लेकर उंगलियां उठ रही हैं. ताजा मामला बीसीसीआई द्वारा स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए गठित दो सदस्यीय आयोग को लेकर सामने आया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस आयोग को ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक ठहराया है. हाईकोर्ट के मुताबिक़, पूरा का पूरा जांच आयोग ही अवैध है और उसका गठन बीसीसीआई के संचालन नियमों की धारा 6 के नियम 2.2 और 3 के प्रावधानों का उल्लंघन है और उसके विपरीत है. बीसीसीआई संचालन के नियम 2.2 में कहा गया है कि आईपीएल आचार संहिता समिति का कम से कम एक सदस्य आयोग में होना चाहिए था, लेकिन आयोग का गठन करते वक्त इस बात को नज़रअंदाज़ कर दिया गया और चेन्नई हाईकोर्ट के दो सेवानिवृत्त जजों जयराम चौटा और आर बालासुब्रह्मण्यम के रूप में दो सदस्यीय आयोग का गठन किया था.

गौरतलब है कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे शक्तिशाली बोर्ड है, लेकिन आए दिन उसका नाम जिस तरह से विवादों में छाया रहता है, उससे तो यही लगता है कि भले ही इसका नाम बड़ा हो, लेकिन इसके काम ओछे हैं. स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए जो आयोग गठित किया गया, उसे लेकर पूरे विश्व की नज़रें बोर्ड पर टिकी हुई थीं. सभी को यह उम्मीद थी कि जांच निष्पक्ष होगी और गुनहगार पकड़े जाएंगे, लेकिन हुआ इसके उलट. आयोग ने सभी को क्लीन चीट दे दी. ऐसा कर के बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट की छवि को सिर्फ धुमिल ही नहीं किया है, बल्कि सवा अरब क्रिकेट प्रेमियों के साथ विश्वासघात भी किया है, क्योंकि क्रिकेट प्रेमियों के अंदर इस फिक्सिंग को लेकर जबरदस्त गुस्सा थी और वे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के पक्ष में थे.

गौरतलब है कि आयोग के गठन के ख़िलाफ़ बिहार क्रिकेट संघ और उसके सचिव आदित्य वर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी. अदालत ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि बीसीसीआई ने पांच सदस्यीय आईपीएल आचार संहिता समिति का गठन कर रखा है. बीसीसीआई के पास आयोग में अतिरिक्त व्यक्ति को शामिल करने का अधिकार है, लेकिन यह बीसीसीआई को आईपीएल आचार संहिता समिति के किसी भी सदस्य को शामिल किए बिना आयोग के गठन का अधिकार नहीं देता है. बीसीसीआई के फ़ैसले का बचाव करते हुए बीसीसीआई के वकील ने कहा कि बोर्ड को इस तरह के आयोग का गठन इसलिए करना पड़ा, क्योंकि आईपीएल आचार संहिता समिति के सदस्य अजय शिर्के और राजीव शुक्ला उपलब्ध नहीं थे. बीसीसीआई के सचिव संजय जगदाले ने आयोग का सदस्य बनने से साफ़ इंकार कर दिया था, लेकिन जजों ने उनके इस तर्क पर सवाल किया कि रवि शास्त्री और अरुण जेटली भी तो समिति के सदस्य हैं, तो उन्हें जांच पैनल में क्यों नहीं शामिल किया गया?

जांच आयोग ने आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स के मालिक और इंडिया सीमेंट लिमिटेड के चेयरमैन एवं बीसीसीआई के निर्वासित अध्यक्ष एन श्रीनिवासन, उनके दामाद और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सह-मालिक राज कुंद्रा के ख़िलाफ़ स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच की थी. 28 जुलाई को सौंपी अपनी रिपोर्ट में आयोग ने इन सभी को क्लीन चिट दे दी.

भारत में अब क्रिकेट खेल कम, व्यवसाय ज़्यादा बन गया है. आईपीएल में मैच फिक्स किए जा रहे हैं, मैच फिक्सिंग में अंडरवर्ल्ड और ख़ासकर दाउद इब्राहिम का नाम आने के बाद स्पॉट फिक्सिंग मामले की गंभीरता और भी बढ़ गई है. अब तो ऐसा लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से क्रिकेट को अंडरवर्ल्ड कंट्रोल कर रहा है और क्रिकेट की लोकप्रियता का वह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है. इस तरह के मामलों के लगातार सामने आने के बाद दर्शकों के बीच क्रिकेट की विश्वसनीयता में गिरावट आई है. ऐसे में जिस तरह जांच आयोग ने श्रीनिवासन, उनके दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सह-मालिक राजकुंद्रा को क्लीन चिट दी है, इससे बीसीसीआई की कार्यप्रणाली पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई पुलिस अभी भी इस मामले की सघन जांच में जुटी हुई है. पुलिस मामले की जड़ तक पहुंचना चाहती है. वह मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोपियों पर मकोका लगा रही है. ऐसे में आयोग द्वारा जल्दबाज़ी में रिपोर्ट देना और बड़े आरोपियों को क्लीन चिट देना शक के दायरे को पुख्ता करता है कि बीसीसीआई में सब कुछ सही नहीं चल रहा है. इसी वजह से वह जांच के दायरे में नहीं आना चाहता है. इसके साथ ही जांच के लिए आयोग में जिन जजों की नियुक्ति की गई, उनका संबंध भी तमिलनाडु से है. श्रीनिवासन भी तमिलनाडु के ही हैं. ऐसे में आयोग द्वारा निष्पक्ष जांच किए जाने पर भी क्रिकेट प्रशंसकों को संदेह है.

बीसीसीआई के अपारदर्शी कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. इस बार भी स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच पैनल को असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद एक बार फिर से बीसीसीआई को सूचना का अधिकार क़ानून के दायरे में लाने की आवाज़ तेज़ हो गई है. यह आवाज़ केवल आम जनता की तरफ़ से नहीं, बल्कि सरकार और बोर्ड के सदस्यों, दोनों की ओर से उठ रही है. झारखंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि बीसीसीआई आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहता है और वह संविधान और संसद को नहीं मान रहा है. यदि वह अपनी मांग पर अड़ा रहता है, तो सरकार कार्रवाई करने को लेकर मजबूर हो जाएगी. नैतिकता के आधार पर श्रीनिवासन को अपना पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन वह बीसीसीईआई को हाइजैक करने की कोशिश कर रहे हैं. बोर्ड के इस ग़ैरज़िम्मेदार रवैये की वजह से बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाना ज़रूरी हो गया है.

इस दिशा में एक आवश्यक क़दम उठाते हुए केंद्र सरकार ने भी नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल 2013 के जरिये बीसीसीआई समेत सभी खेल संघों को सूचना अधिकार क़ानून (आरटीआई) के दायरे में लाने की तैयारी कर ली है. बीसीसीआई भले ही सरकार से किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं लेता हो, लेकिन नया खेल क़ानून बनाने पर उसे न सिर्फ़ इसका पालन करना होगा, बल्कि आरटीआई को भी स्वीकार करना होगा. प्रस्तावित नियमों का पालन न करने पर बीसीसीआई को भारत के नाम का प्रयोग करने से रोका जा सकता है. पूर्व खेल मंत्री अजय माकन ने भी खेल संघों को आरटीआई के दायरे में लाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके कार्यकाल में स्पोर्ट्स बिल पास नहीं हो सका था.

नेशनल स्पोर्ट्स डेवलेपमेंट बिल 2013 का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज मुकुल मुदग्ल के अनुसार, क्रिकेट बोर्ड ही नहीं, बल्कि आईपीएल भी आरटीआई के दायरे में आएगा, लेकिन उन्होंने यह ज़रूर साफ़ कर दिया कि आरटीआई के तहत नेशनल एंटी डोपिंग ऐजेंसी, व्हेयरअबाउट, चयन संबंधी मामलों के अलावा गोपनीय कॉमर्शियल सूचनाएं, जांच और स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं जानने का अधिकार लोगों को नहीं होगा. नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट क़ानून के अंतर्गत देश के सभी खेल संघों को अपनी गतिविधियों के लिए खेल मंत्रालय से मान्यता लेनी होगी. इनमें बीसीसीआई भी शामिल है, जो खेल संघ खेल मंत्रालय से आर्थिक सहायता लेते हैं, उन्हें आधिकारिक प्रमाण पत्र लेना होगा. तभी वह देश में खेलों का संचालन कर पाएंगे.

दुनिया के सबसे पैसे वाले बोर्ड ने देश की सरकार के ऊपर नियंत्रण कर लिया है? क्या बीसीसीआई देश के संविधान और क़ानून से भी ऊपर है? बीसीसीआई को तत्काल सूचना का अधिकार क़ानून के दायरे में लाए जाने की ज़रूरत है. बोर्ड की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है. देश में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अन्ना हज़ारे और अन्य सामाजिक संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं. देश भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एकजुट है. बीसीसीआई हर बार ख़ुद को ट्रस्ट बताकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता. नि:संदेह क्रिकेट भारत में सबसे लोकप्रिय खेल है. बीसीसीआई की ज़िम्मेदारी केवल क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाने तक सीमित नहीं है. खेल को साफ़-सुथरा रखने की और लोगों के बीच खेल का विश्वास बनाए रखने की ज़िम्मेदारी भी बोर्ड की ही है. जिन सवा अरब खेल प्रेमियों ने बीसीसीआई को दुनिया का सबसे पैसे वाला और पैसे की वजह से सबसे ताक़तवर बोर्ड बनाने में योगदान दिया है, उनके प्रति बीसीसीआई को जवाबदेह होना ही पड़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया
जगमग दुनिया
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467
12 अगस्त–18 अगस्त 2013

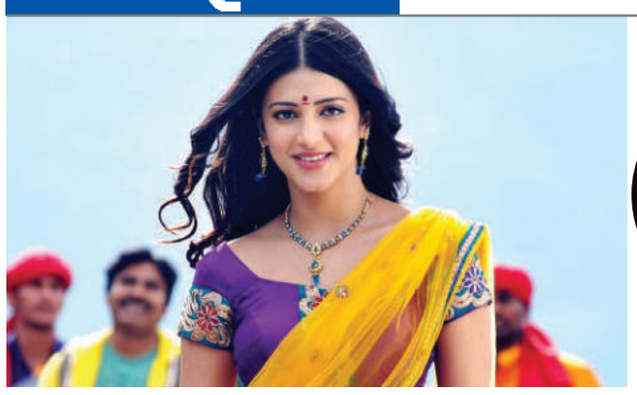

इन दिनों श्रुति काफी खुश हैं, क्योंकि उनकी हाल ही में दो फिल्में रिलीज हुईं और दोनों ही फिल्मों ने अच्छा व्यवसाय किया. प्रभुदेवा की फिल्म रमैया वस्तावइया में जहां वह सिधी–सादी लड़की की किरदार में दिखीं, वहीं फिल्म डी–डे में वह सेक्स वर्कर की भूमिका में दिखीं. श्रुति पिछले दो साल से साउथ की फिल्मों में काम कर रहीं थीं.

स्पोर्ट्स फिल्मों का दर्शकों पर चढ़ा खुमार

प्रियंका

भाग मिल्खा भाग की अपार कामयाबी ने बॉलीवुड को खेलों पर फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया है. इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए और भी खिलाड़ियों पर फिल्में बनाने की तैयारी बॉलीवुड में हो रही है. बॉलीवुड में किसी ख़ास पटकथा पर फिल्म हिट हो जाए, तो ट्रेंड चल निकलता है, फिर उस पटकथा पर कई फिल्में बनती हैं, लेकिन सभी की किस्मत भाग मिल्खा भाग जैसी हो, यह जरूरी नहीं. अब ज़रा नज़र डालते हैं, बॉलीवुड में खेल पर बनी अब तक की फिल्मों पर.

इसी वर्ष फरवरी में स्पोर्ट्स पर एक और फिल्म रिलीज हुई थी काई पो चे. चेतन भगत के उपन्यास थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर बनी इस फिल्म को भी काफ़ी सराहा गया. हालिया रिलीज फिल्म भाग मिल्खा भाग ने अब तक 90 करोड़ की कमाई कर चुकी है. हालांकि इससे पहले भी कुछ फिल्में खेलों पर बन चुकी हैं, लेकिन वो दर्शकों को कुछ ख़ास आकर्षित नहीं कर पाईं. इन फिल्मों से पहले कभी बॉलीवुड ने इस विषय पर फिल्म बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई. शायद इसकी एक वजह यही रही कि जब भी यहां इस विषय पर फिल्में बनाई गईं, उन्हें कुछ ख़ास सफलता नहीं मिली. लगान की सफलता के बाद क्रिकेट को बड़े पर्दे पर भुनाने के लिए तमाम फिल्में आईं, जिसमें स्टम्प्ड, इकबाल, सलाम इंडिया, हैट्रिक, विक्ट्री, जन्नत, पटियाला हाउस वगैरह ख़ास हैं, लेकिन सफल सिर्फ़ इकबाल और जन्नत रहीं.

शाहरुख स्टारर फिल्म चक दे को लेकर लोगों का रिस्पॉन्स देखने के बाद ही बॉलिवुड स्पोर्ट्स आधारित फिल्मों में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों पर भी फोकस किया जा सकता है. इसके बाद फुटबॉल पर दना दन गोल और कैरम पर स्ट्राइकर जैसी फिल्में आईं. इसी दौरान रानी मुखर्जी अभिनित फिल्म दिल बोले हडिप्पा भी आई, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं.

शाहरुख स्टारर फिल्म चक दे को लेकर लोगों का रेस्पॉन्स देखने के बाद ही बॉलीवुड में स्पोर्ट्स आधारित फिल्मों में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों पर भी फोकस किया जाने लगा. इसके बाद फुटबॉल पर दनादन गोल और कैरम पर स्ट्राइकर जैसी फिल्में आईं. इसी दौरान रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म दिल बोले हड़िप्पा भी आई, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं. हालांकि वूमेन क्रिकेट पर आधारित फिल्म दिल बोले हड़िप्पा को काफ़ी सराहा गया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ख़ास कमाल नहीं कर पाई.

वहीं एक ऐथलीट के डकैत बनने की सच्ची कहानी पर फिल्म पान सिंह तोमर भी काफ़ी पसंद किया गया. बॉलीवुड में स्पोर्ट्स पर आधारित कम फिल्में बनने के पीछे शायद यह भी वजह है कि स्पोर्ट्स फिल्में बनाने के लिए वक्त, रिसर्च और अनुभव, सब कुछ चाहिए. ऐसे में अगर एक फिल्म न चले, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है. यही वजह है कि बॉलीवुड में किसी नये विषय पर फिल्में बनाने का रिस्क फिल्मकार नहीं लेना चाहते. हालिया ट्रेंड देखें, तो अब खिलाड़ियों की ज़िंदगी पर फिल्में बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है. फिल्म मेकर्स का तर्क है कि इस तरह कि फिल्मों में फैमिली इमोशनल ड्रामा दिखाने का पूरा स्कोप रहता है. भाग मिल्खा भाग में फ्लाइंग सिख की कहानी दिखाने के बाद इन दिनों मेरीकॉम पर फिल्म बन रही है. इसके बाद पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अज़हरुद्दीन और हॉकी लीजेंड ध्यानचंद पर फिल्म बनने की भी चर्चा है. सच तो यह है कि रियल लाइफ पर फिल्म और उसमें लव इमोशन का तड़का दर्शकों को ख़ूब भा रहा है. ■

बॉलीवुड की स्पोर्ट्स फिल्में

- हिप हिप हुर्रे (1983) इस फिल्म से डायरेक्टर प्रकाश झा ने डेब्यू किया था. इस फिल्म में रांची के किसी स्कूल के फुटबॉल कोच की कहानी दिखाई गई थी. इस रोल को राजकिरण ने निभाया था.
- बॉक्सर (1984) मिथुन चक्रवर्ती की यह फिल्म सिल्वेस्टर स्टालॉन की रॉकी सीरीज़ से इंस्पायर्ड थी.
- लगान (2001) क्रिकेट पर आधारित इस फिल्म ने उस साल सबसे ज्यादा कमाई की थी. इसे ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था.
- इकबाल (2005) छोटे बजट की इस फिल्म में श्रेयस तलपड़े ने गूंगे-बहरे क्रिकेट प्लेयर का रोल किया था, जो नैशनल टीम में शामिल होने का अपना सपना पूरा करता है.
- चक दे (2007) किक्रेट से हटकर दूसरे खेलों को पर्दे पर दिखाने का क्रेडिट इसी फिल्म को जाता है. शाहरुख ने इसमें एक हॉकी कोच का रोल निभाया था, जो वूमेन टीम को गोल्ड मेडल तक लेकर जाता है.
- दना दन गोल (2007) विदेश में साउथ एशियन प्लेयर्स को लेकर यह फिल्म बनाई गई थी. जॉन अब्राहम स्टारर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई थी.
- दिल बोले हड़िप्पा (2009) रानी मुखर्जी और शाहिद कपूर अभिनीत इस फिल्म को काफी सराहा गया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स आफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई.
- पान सिंह तोमर (2012) इस फिल्म में एक ऐसे ऐथलीट की कहानी दिखाई गई थी, जिसे परिस्थितियां डकैत बना देती हैं. इस फिल्म के लिए अभिनेता इरफान खान को नैशनल अवॉर्ड भी मिला था.
- काई पो चे (2013) चेतन भगत के उपन्यास थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित इस फिल्म को दर्शकों ने काफी सराहा. तीन दोस्त, जो अहमदाबाद में रहते हैं. तीनों ही एक स्पोर्ट्स स्टोर, क्रिकेट कोचिंग एकेडमी सेंटर खोलना चाहते हैं. ■

टेलीविजन के शहंशाह सलमान

भले ही बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ हैं, लेकिन टीवी के शहंशाह तो सलमान खान ही हैं. सलमान टेलीविजन से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले स्टार हैं. कलर्स का चर्चित टीवी शो बिग बॉस फिर से शुरू होने वाला है और सलमान इसके लिए मोटी रक़म लेंगे. सलमान इस शो को होस्ट करेंगे और प्रति एपिसोड वह 5 करोड़ रुपये लेंगे. सलमान ने पिछले साल बिग बॉस के हर एपिसोड के लिए 2.5 करोड़ रुपये लिए थे. वहीं अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति की बात करें, तो वह हर एपिसोड के लिए 2.5 करोड़ रुपये लेते हैं. यह शो अगस्त में ही शुरू हो जाएगा. इस क़ीमत के साथ सलमान ने आमिर ख़ान को भी पछाड़ दिया. आमिर ख़ान सत्यमेव जयते के लिए प्रति एपिसोड 3 करोड़ रुपये लेते थे. टीवी शो ज़ोर का झटका के लिए शाहरुख ख़ान 2 करोड़ रुपये लेते थे, जबकि, रितिक रोशन ने जस्ट डांस के प्रति एपिसोड के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपये लिए. वहीं माधुरी दीक्षित झलक दिखला जा सीजन 5 के लिए 50 लाख रुपये प्रति एपिसोड लेती हैं. कहा जा रहा है कि बिग बॉस के इस सीजन के लिए सलमान और शो वालों के बीच 130 करोड़ रुपये का क़रार हुआ है. वह सप्ताह में 2 दिन एपिसोड के लिए शूटिंग करेंगे. इस बार के शो की थीम है- हेवन ऐंड हेल. यानी, इस बार के शो में सलमान ख़ान का फरिश्ता और राक्षस अवतार दिखाई देगा. बिग बॉस सितंबर के मध्य से ऑन-एयर होगा. अब सलमान ख़ान की इस साल भले ही कोई फिल्म अभी तक न रिलीज हुई हो, लेकिन कमाई के मामले में वह निश्चित तौर पर पीछे नहीं रहने वाले हैं. ■

दीया करेंगी शादी

बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा भी अब शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. जी हां, अगले वर्ष दिया अपने मित्र साहिल संघा से शादी करने वाली हैं. दीया लंबे समय से व्यवसायी साहिल संघा के साथ रिलेशनशिप में हैं. दीया कहती हैं कि साहिल के उनके जीवन में आने से उनका जीवन पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया है. 31 वर्षीया दीया अपने दोस्त साहिल और जायद खान के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाऊस भी चला रही हैं. तीनों की साझेदारी में बनी पहली फिल्म है इव ब्रेकअप्स जिंदगी. दिया कहती हैं कि साहिल के साथ मुझे एक पेशेवर साझेदार और जीवन संगिनी की भी भूमिका निभानी है. साहिल के आने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है. साथ ही दीया कहती हैं कि वह एक अतुलनीय और प्रतिभावान व्यक्ति हैं. ■

दिसंबर में रिलीज होगी

मुन्ना भाई सल्लू भाई किलर्स ऑर हीलर्स

मो अज्जम बेग की फिल्म मुन्ना भाई सल्लू भाई किलर्स ऑर हीलर्स की शूटिंग अजमेर में 29 जुलाई से शुरू हो गई. इसी दिन संजय दत्त का जन्मदिन भी था. इसलिए निर्देशक मोअज्जम बेग ने इसकी शूटिंग इसी दिन से ही शुरू किया. खास बात यह है कि यह फिल्म सलमान खान के जन्म दिन पर 27 दिसंबर को रिलीज होगी. गौरतलब है कि इस फिल्म के कलाकारों का चयन मुंबई, पुणे, दिल्ली और चंडीगढ़ में ऑडिशन के जरिये किया गया. अपनी फिल्म के कलाकारों को ढूंढने के लिए मोअज्जम बेग ने फेसबुक पेज, यूट्यूब और डिजिटल डायरी का सहारा लिया था. चुने गए पात्र हैं देव (एंग्री यंग मैन), किम सुदर्शन (फेसबुक सेलिब्रिटी), नताशा (रॉक स्टार) और समर (कैसानोवा). भोपाल के रहने वाले जुबैर कमाल खान को फिल्म में समर, दिल्ली के श्रेष्ठ कुमार को देव, अंजलि अरोड़ा को नताशा की भूमिका के लिए चुना गया है. हालांकि अभी किम सुदर्शन की तलाश पूरी नहीं हो पाई है. फिल्म निर्देशक मोअज्जम बेग कहते हैं कि यह एक ऐसी फिल्म है, जो पूरी तरह सलमान और संजय दत्त के प्रशंसकों के लिए है. अजमेर शरीफ से फिल्म की शूटिंग शुरू करने के बारे में फिल्म के राइटर और निर्देशक मोअज्जम बताते हैं कि 21 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उस समय मैं अजमेर शरीफ में था, इस फैसले से मैं थोड़ा आहत हुआ और वहीं से मेरे दिमाग में मुन्ना भाई सल्लू भाई कीलर्स और हीलर्स फिल्म बनाने का आइडिया मेरे जेहन में आया. जाहिर सी बात है, मैंने जब फिल्म बनाने की सोची, तो शुरुआत अजमेर शरीफ से ही करनी थी. इस पाक जगह पर लाखों लोग अपनी मुराद लेकर आते हैं. मैंने भी इस मुबारक जगह को शूटिंग के लिए चुना. ■

सेक्स वर्कर बनीं श्रुति

सारिका और कमल हसन की बेटी श्रुति हसन काफी समय से बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रही हैं. इन दिनों वह काफी खुश हैं, क्योंकि उनकी हाल ही में दो फिल्में रिलीज हुई हैं. जी हां, बॉक्स ऑफिस पर भी दोनों ही फिल्मों ने ठीक-ठाक बिजनेस भी किया. प्रभुदेवा की फिल्म रमैया वस्तावइया में जहां वह सिधी-सादी लड़की की किरदार में दिखीं, वहीं फिल्म डी-डे में वह सेक्स वर्कर की भूमिका में दिखीं. श्रुति पिछले दो साल से साउथ की फिल्मों में काम कर रहीं थी. इस बीच वह बॉलीवुड में भी कुछेक फिल्मों में दिखीं. इस बारे में वह कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको साल में दो-तीन फिल्में सिर्फ इसलिए करनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री और मीडिया में पहचान बनी रहे. लक और दिल तो बच्चा है जी, के बाद मुझे कई ऑफर मिले. आज भी मेरे पास फिल्मों के ऑफर्स आते हैं, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए. इस बिच मैंने साउथ की फिल्में कीं. पिछले दो साल में साउथ में मेरी पांच फिल्में रिलीज हुई और अभी भी दो साउथ की फिल्मों की शूटिंग कर रही हूं. मधुर भंडारकर की फिल्म दिल तो बच्चा है, में श्रुति काफी छोटी सी भूमिका में दिखीं. इस फिल्म में भले ही उनकी भूमिका छोटी सी थी, लेकिन उन्हें नोटिस किया गया. इस फिल्म में काम करने के बारे में श्रुति कहती हैं कि मैं क्या, कोई भी एक्ट्रेस मधुर के साथ काम करने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि की उन्हें महिला प्रधान फिल्में बनाने में महारत हासिल है. मधुर के साथ इंडस्ट्री की हर नामचीन ऐक्ट्रेस काम करना चाहती है. मुझे मधुर ने जब इस फिल्म के लिए अप्रोच किया, उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था. मैंने उनसे स्क्रिप्ट और अपने किरदार को लेकर भी बात नहीं किया. मुझे उन पर पूरा भरोसा था. मुझे बस इतना पता था कि मेरे को-स्टार कौन हैं. कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे यह फिल्म करके कभी अफसोस नहीं हुआ. बल्कि यह मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि मुझे अपने करियर के शुरुआत में ही मधुर जैसे बेहतरीन डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला. करियर के शुरुआती दौर में मधुर जैसे बेहतरीन डायरेक्टर की फिल्म का हिस्सा बनना, मैं आज भी एक बड़ी उपलब्धि मानती हूं. देर से ही सही, लेकिन मुझे दो अच्छी फिल्में मिलीं. मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी दोनों फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया. फिल्म डी-डे के किरदार में जीवंतता लाने के लिए मैं मुंबई के रेड लाइट एरिया में भी गई. बेशक, वहां जाकर मैंने जिस माहौल को जाना, वह इस किरदार को निभाते वक्त मेरे बहुत काम आया. इन दोनों फिल्मों ने काफी अच्छा बिजनेस किया. मैंने अपनी खुशी सबसे पहले पापा के साथ सेलिब्रेट किया, क्योंकि यहां तक पहुंचने में उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

12 अगस्त–18 अगस्त 2013

बिहार–झारखंड

सीमांचल

भाजपा-जदयू अलगाव
बिखरने लगे प्रत्याशी

भाजपा जदयू के बीच अलगाव के बाद राजधानी पटना में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों और स्थानीय नेताओं के बीच भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है. आए दिन यहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़े और दोशारोपण की खबरें आम हैं...

वरूण सिंह

दिलीप जायसवाल

ज्योति रानी

लेसी सिंह

सीमा देवी

संजय कुमार

उदय सिंह

नीरज सिंह

जदयू और भाजपा के अलगाव से सीमांचल की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है. सीमांचल की त्रिस्तरीय पंचायती राजनीति भी गठबंधन के टूटने से प्रभावित है. वर्तमान में यहां के पंचायती राज व्यवस्था में जदयू भाजपा के कार्यकर्ता विकास कार्यों को भूलकर एक-दूसरे को अपदस्थ करने की होड़ में जुटे दिखते हैं. इसी तकरार का नतीजा है कि पूर्णिया के रूपौली प्रखंड के प्रमुख परीक्षण ठाकुर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी. अब अमौर, जलालगढ़, डगरूआ बड़हरा कोठी, बनमनखी, श्रीनगर, भवानीपुर जैसे प्रखंडो में उठा-पटक का दौड़ जारी है. वहीं पूर्णिया के जिला परिषद अध्यक्ष पद से सीमा देवी को अपदस्थ कराकर भाजपा समझ रही है कि उसने जदयू को राजनीतिक पटकनी दे दी है. मालूम हो कि सीमा देवी जदयू के प्रदेश महासचिव आशीष कुमार बब्बू की पत्नी हैं और धमदाहा विधायक लेसी सिंह की करीबी मानी जाती हैं. दो वर्ष पूर्व जदयू के महासचिव आशीष कुमार बब्बू की पत्नी सीमा देवी, लेसी सिंह के सहयोग से ही मात्र दो मतों के अंतर से जिला परिषद अध्यक्ष बनी थीं. वहीं राजेश सिंह एक मत की बढ़त से उपाध्यक्ष बने थे.

- शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

किसमें कितना है दम

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सड़क से लेकर सदन तक भाजपा के आक्रामक तेवर से लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना धैर्य खोने लगे हैं. उन्होंने विधानसभा में कहा कि भाजपा को उसकी औकात बता देंगे. उनकी यह भाषा सुन कर उनके करीबी तक हैरान थे.

सरोज सिंह

नीतीश कुमार इन दिनों भाजपा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं. पिछले दिनों विधानसभा में जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया उसे सुनकर खुद उनके सहयोगी सुशील मोदी भी हैरान रह गए. मोदी ने नीतीश के कथन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि न जाने नीतीश को क्या हो गया है. भाजपा ने भी नीतीश पर पलटवार किया. सुशील मोदी ने कहा कि असली ताकत तो जनता के पास है, बड़े बड़े दावे करने वालों को जनता खुद उन्हें उनकी औकात बता देगी. नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव कहते हैं कि जब वे साथ थे तो हम इकतालीस थे. उस समय भाजपा ने उनका साथ दिया था. आज ऐसे लोग औकात बताने की बात करते हैं तो आश्चर्य होता है. दरअसल, जबसे भाजपा जदयू से अलग हुई है, तभी से राज्य में कोई न कोई घटना सरकार को परेशान कर रही है. बगहा गोलीकांड से शुरू हुआ सिलसिला मीड डे मिल से हुई बच्चों की मौत तक जा पहुंची है. इन सारे मुद्दों पर भाजपा काफी आक्रमक तरीके से जनता के बीच गई. धरना प्रदर्शन का दौर पूरे सूबे में चला. इसके बाद सदन में भी भाजपा ने इन मसलों को काफी कड़े तेवर के साथ उठाया. इसके अलावा, भाजपा जदयू की जीती हुई सीटों पर सम्मेलन कर रही है. इसमें में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं. नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में तो बड़ी संख्या में लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया. भाजपा की उन राजनीतिक क्रियाकलापों से जदयू में खासी बैचैनी है. जदयू को लगता है कि अगर भाजपा इसी गति से चलती रही तो लोकसभा चुनाव में उसे फायदा हो सकता है. सी वोटर के सर्वे में भी जदयू की सीटें घटने का अनुमान लगाया गया है. इसलिए जदयू ने जवाबी रणनीति के तहत भाजपा को कमजोर करने की कवायद शुरू कर दी है. भाजपा से खासकर सुशील मोदी के क्रियाकलापों से नाराज चल रहे विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है, और उनसे सार्वजनिक बयान दिलवाए जा रहे हैं. शुरुआत दरभंगा जिले के विधायक अमरनाथ गामी से की गई. धीरे-धीरे इसमें प्रेमरंजन पटेल, विजय कुमार मिश्रा और रामकिशोर सिंह भी शामिल हो गए. बिहारी बाबू शत्रुध्न सिन्हा तो नीतीश कुमार को पीएम मैटेरियल बता बैठे. भाजपा को उकसाने वाली उन कार्रवाईयों का भाजपा पर तो उतना असर नहीं हुआ, उलटे जदयू नेताओं की भाषा खराब होती गई. जदयू को लग रहा था कि उन नेताओं के नीतीश प्रेम से भाजपा की हवा खराब होगी, लेकिन यह आकलन गलत साबित हुआ. ऐसा इसलिए हुआ कि विरोध करने वाले नेताओं के बारे में सभी जानते हैं कि उन्हें अगली बार टिकट मिलने वाला नहीं है. बिहारी बाबू के बारे में तय है कि उन्हें इस बार लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा. वह अपनी पत्नी के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि उस सीट से इस बार सुशील कुमार मोदी या रविशंकर प्रसाद चुनाव लड़ेंगे. इसी तरह रामकिशोर सिंह ने जब देखा कि परिषद में उनका जाना मुश्किल है तो, उन्होंने अपना नीतीश प्रेम जगजाहिर कर दिया. विजय कुमार मिश्रा का भी यही हाल है.

- शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

» एक नज़र «

दर्ज होगी प्राथमिकी

पिछले बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की बैठक पटना में हुई. इसकी अध्यक्षता डॉ. अनिल सुलभ ने की. बैठक में उपस्थित लोगों ने बताया कि लंबे समय के बाद साहित्य सम्मेलन में साहित्य सेवियों और हिंदी प्रेमियों की भारी उपस्थिती देखी गई. उपस्थित सदस्यों ने सम्मेलन परिसर में हो रहे गुणात्मक परिवर्तन के लिए अध्यक्ष की प्रशंसा की. एक प्रस्ताव पारित कर सम्मेलन के निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति को विधि–सम्मत बताया गया और उनसे नए अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए चुनाव–प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया गया. समिति ने कार्यसमिति द्वारा प्रेषित निर्वाचक सूची को भी अनुमोदित कर दिया. बैठक में सम्मेलन के अध्यक्ष रामनरेश सिंह ने वित्तीय अनियमितता पर गरमागरम बहस भी की. उपस्थित सदस्यों ने सिंह को पदमुक्त करते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और सम्मेलन की सदस्यता समाप्त करने की मांग की. यह भी निर्णय लिया गया कि सिंह के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की प्राथमिकी दर्ज कराई जाए.

– शशि सागर

बच्चों ने जुटाए 51 हजार

सीतामढ़ी ज़िले के दिल्ली पब्लिक स्कूल लगमा के बच्चों ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों के लिए चंदा मांग कर 51 हजार रुपए जमा किए हैं. स्कूल के निदेशक ई. तारिक खान के नेतृत्व में बच्चों ने जिले के डीएम डॉ. प्रतिमा को चेक सौंपा. बच्चों की मानवीय संवेदना जिले में चर्चा का विषय है. वहीं दूसरी ओर प्राईवेट स्कूल एसोसिएशन का एक दल भी जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी मिर्जा आरिफ रजा को 51 हजार रुपये का चेक सौपा. दल में बिट्टू विश्वास, रमेश शुक्ला, परमहंस सिंह, महेश कुमार, शमशाद खां, प्रणत पाल, राजीव रंजन वर्मा, ब्रज भूषण राय, संजीव कुमार एवं अंबरीश कुमार निराला सहित कई लोग थे.

क्लब ने मनाया शहीद दिवस

कारगिल शहीद मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी की याद में लायंस क्लब प्रियदर्शिनी ने शहीद दिवस का आयोजन किया. सीतामढ़ी के नगरपालिका मध्य विद्यालय भवदेपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. प्रतियोगिता में सफल मनीषा को प्रथम, प्रियसी स्नेहा को द्वितीय व आकांक्षा कुमारी को तृतीय पुरस्कार दिया गया. इसके अलावा, करीब दो दर्जन बच्चों के बीच सांत्वना पुरस्कार का वितरण किया गया. डॉ. लता गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बतौर अतिथि डॉ. तारिणी प्रसाद, डॉ. मंजूबाला शरण और महावीर चौधरी मौजूद थे. साथ ही सचिव डॉ. शानू शिल्पी, कोषाध्यक्ष तारा खेमका, पॉली चौधरी, डॉ. रेणू चटर्जी, इंदु गुप्ता, कामिनी सिन्हा, सुषमा और मधु कुमारी आदि थे.

दांतों का परीक्षण

लायंस क्लब सीतामढ़ी सेंट्रल के तत्वावधान में पिछले दिनों एक शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में चिकित्सकों ने तकरीबन चार दर्जन से अधिक एसएसबी जवानों के दांतों का परीक्षण किया. कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष डॉ राजेश कुमार, सचिव सुधीर कुमार, लक्की सिंह, अमित कुमार, राज कुमार खेमका, डॉ राजेश खन्ना, डॉ हिमांशु, शशि कुमार चौधरी, कुमार अभिषेक के अलावा एसएसबी के डॉक्टर निशिकांत मिश्र समेत अन्य थे.

– ब्रजेश

किसानों को प्रशिक्षण

सीतामढ़ी जिले के पुपरी अनुमंडल क्षेत्र के बलहा मधुसूदन कृषि विज्ञान केंद्र में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जिले के तकरीबन 50 किसानों ने भाग लिया. केंद्र के पशु चिकित्सा वैज्ञानिक किंकर कुमार ने कार्यक्रम की शुरुआत की. मौके पर राम सूरत सिंह, रामबाबू राणा, रमेश राय, कृष्ण कुमार तिवारी, राम कुमार राय, मदन राय, गौरी शंकर राय, सुधीर ठाकुर, अशोक कुमार, सुशील ठाकुर, सरोज कुमार, मनोज कुमार और अमृत कुमार समेत कई अन्य लोग थे.

– गोविंद कुमार

गठबंधन टुटते ही बदला काराकाट का गणित

ममता चौहान

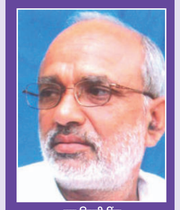

राज्य की एनडीए गठबंधन में हुई टुट के बाद वैसे तो लगभग सभी सीटों पर राजनीतिक समीकरण इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन रोहतास जिला का काराकाट लोकसभा क्षेत्र इस मुद्दे पर कुछ खास हलचल लिए बैठा है. भौगोलिक दृष्टि से राज्य के विषम लोकसभा क्षेत्रों में से एक काराकाट के बीचोबीच सोन नदी का पवार जल मानस के विचार ही नही भाषा में भी भिन्नता पैदा करता है. एक तरफ रोहतास के डेहरी, नोखा और काराकाट विधानसभा क्षेत्र दूसरी तरफ औरंगाबाद के नवीनगर, ओबरा और गोह विधानसभा क्षेत्र. सोन नदी के पूर्वी किनारे पर औरंगाबाद के तीनों विधानसभा क्षेत्र हैं, तो पश्चिमी किनारे पर रोहतास के तीन विधानसभा क्षेत्र हैं. बीच में दो किलोमीटर चौड़ी सोन नदी विभाजक रेखा का काम करती है, जिसके पश्चिम में भोजपुरी और पूरब में मगही भाषा का प्रभाव है. हम बात कर रहे हैं यहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर राजनीतिक दलों की हो रही उठापठक की, जिसमें सत्ताधारी दल जदयू के वर्तमान सांसद महाबली सिंह को भी दरकिनार कर उसी दल के कुछ दिग्गज चुनावी मैदान में टिकट पाने का दावा ठोकते हैं, लेकिन जिस तरह से महाबली सिंह ने पिछले दो वर्षो से काराकाट लोक सभा क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को अचानक तेज की है. उसे देख यह कहना गलत होगा कि पार्टी उनकी जगह किसी और के नाम पर विचार भी कर सकती है. हां, पहले के परिदृश्य कुछ और जरूर थे. तब महाबली सिंह की पार्टी के प्रति निष्ठा पर उस समय सवाल उठ खड़े हुए, जब गत विधानसभा चुनाव में अपने बेटे धर्मेंद्र कुशवाहा को श्री सिंह चयनपुर विधानसभा से राजद का टिकट दिलवाने में कामयाब रहे थे. उस समय अटकलों का बाजार कुछ तेज था, लेकिन अब गठबंधन से भाजपा को अलग होने और कुशवाहा मतों की अहम भूमिका को देखकर जदयू शायद ही किसी अन्य नाम पर विचार करे. वैसे यह तो समय ही बताएगा. पार्टी नेतृत्व चुनाव के ऐन वक्त पर क्या करता है. फिलहाल महाबली सिंह की दावेदारी मजबूत दिखती है. अब राजद के उम्मीदवारी पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि गत चुनाव में पुर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह ने महाबली सिंह को चुनाव में जोरदार टक्कर दी थी. फिलहाल कांति सिंह के क्षेत्र दौरे में तेजी को देखकर यह लगने लगा है कि पार्टी अलाकमान ने उन्हें चुनावी तैयारी में जुट जाने को शायद निर्देश दे दिया है. हालांकि उसकी अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जिसके कारण ओबरा के पुर्व विधायक सत्यनारायण यादव सहित कई लोग भी अपनी कसरत काराकाट क्षेत्र में कर रहे हैं. अब जदयू से अलग हुए भाजपा की तैयारी पर चर्चा किए बिना काराकाट लोकसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण अधूरा लग रहा है, जिसको लेकर भाजपा के तरफ से रामेश्वर चौरसिया सहित कई नाम सामने आ सकते हैं. फिलहाल चर्चा यह भी है कि अगर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से भाजपा के गठबंधन हुए, तो पार्टी काराकाट के लिए जरूर जोर लगाएगी, क्योंकि हाल ही में राजद से छोड़कर लोक समता में गए राम बिहारी सिंह इस समय काराकाट में कुछ ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं. फिलहाल यह मुद्दा तो गठबंधन होने व सीटों के बंटवारे में फंसा हुआ है. वैसे अगर भाजपा को लड़ना हुआ, तो और भी कई नाम सामने आ सकते हैं. कांग्रेस के तरफ से पूर्व प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह के अलावा कोई और नाम चर्चा में नही आया है. न हीं कहीं भी क्षेत्र में गतिविधियां देखने को मिलती है. कई कारणों से खास काराकाट लोकसभा क्षेत्र में राजपूत और यादव मतदाताओं के बीच संख्या के आधार पर जबरदस्त जोर–आजमाइस होता रहा है. पहले जब बिक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र था, तब भी यहां उन्हीं दो जातियों के बीच सीट हथियाने की होड़ रहती थी. बाद के परिपेक्ष्य में उन दोनों जातियों के बीच इस संघर्ष से रामप्रसाद कुशवाहा और फिर काराकाट बनने पर, पहले सांसद के रूप में महाबली सिंह की चुनौती सामने आई और वे सदन में पहुंचे. इससे पहले कांति सिंह ,वशिष्ठ नारायण सिंह, अजीत सिंह, तपेश्वर सिंह, रामअवधेश सिंह, रामसुभग सिंह सहित कई दिग्गज तत्कालिन बिक्रमगंज लोकसभा सीट पर कब्जा जमा चुके थे, जो या तो राजपूत विरादरी से थे या फिर यादव खानदान से. वर्तमान में रोहतास और औरंगाबाद का बराबर भागीदारी वाला यह लोकसभा सीट जब बना, तो वहां भी राजपूत और यादवों की संख्या बल को लेकर संघर्ष शुरू हुआ, जो आज तक जारी है. वैसे ब्राह्मण, कुशवाहा, रविदास, वैश्य और अल्पसंख्यक मतों की संख्या भी यहां कम नहीं है. ये हमेशा निर्णायक स्थिति में रहते हैं. ■

कांति सिंह

राम बिहारी सिंह

रामेश्वर चौरसिया

feedback@chauthiduniya.com

17 का शेष

किसमें कितना है दम

मतलब है कि विरोध भाजपा या सुशील मोदी का नहीं है, बल्कि टिकट कैसे मिले उसका जुगाड़ प्राथमिकता में है. यह बात शत्रुघ्न सिन्हा को भी पता है कि बिना भाजपा के टिकट के उनका या उनकी पत्नी का चुनाव जीतना नामुमकिन है. इसलिए भाजपा उन सारी विरोधी बयानों पर कोई तत्कालिक कठोर कदम नहीं उठा रही है. धीरे धीरे उस पर काम को आगे बढ़ाया जाएगा. अभी भाजपा की पहली प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाना और नीतीश कुमार को अलग अलग मुद्दों पर घेरना है. हुंकार रैली और नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक स्वागत के लिए भाजपाई कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. इसलिए अब हर सप्ताह इन तैयारियों की समीक्षा का फैसला किया गया है. उधर, जदयू भी जनता के बीच जाने की कोशिश तेज कर रही है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार, आयोगों का पुर्नगठन और मनोनयन कोटे की सीटों को भरना कुछ ऐसी चुनौतियां नीतीश कुमार के सामने हैं, जिनका सामना करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है. यह देखना दिलचस्प होगा कि उन राजनीतिक फैसलों के लिए नीतीश कुमार कौन सा दिन मुकर्रर करते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा–जदयू अलगाव बिखरने लगे प्रत्याशी

विधायक लेसी सिंह का सीमा देवी एवं उसके पति आशीष कुमार बब्बू से राजनीतिक, पारिवारिक, एवं समाजिक रूप से गहरा जुड़ाव रहा है. भाजपा के कई दिग्गजों को तब भी सीमा देवी का जिला परिषद अध्यक्ष बनना नागवार गुजरा था. यही वजह है कि गठबंधन टूटने के बाद विरोध उभरकर सामने आ गया. इलाके में यह बात सर्वविदित है कि पूर्णिया के भाजपा सांसद उदय सिंह एवं जदयू विधायक लेसी सिंह के बीच विगत कुछ वर्षो से संबंध अच्छे नहीं हैं. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन धर्म के चलते ही लेसी सिंह को उदय सिंह का सहयोग मिला था, लेकिन आशीष कुमार बब्बू की वजह से विधायक और सांसद में दूरी लगातार बढ़ती चली गई. चर्चा है कि अब लेसी सिंह खुद पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं. दूसरी तरफ धमदाहा के क्षेत्र संख्या 10 के जिला परिषद सदस्य सह भाजपा जिला उपाध्यक्ष ज्योति रानी ने गठबंधन धर्म के तहत सीमा देवी को अध्यक्ष बनाने में मदद की थी. अब ज्योति खुद ही धमदाहा क्षेत्र से भाजपा के टिकट की प्रबल दावेदार हैं, जो गठबंधन टूटने के बाद विरोध में चली आई हैं. जिला परिषद अध्यक्ष पद की प्रमुख दावेदार सुनीता देवी उर्फ प्रतिमा कुमारी लोजपा के पूर्व विधायक शंकर सिंह की पत्नी हैं. जहां तक लोजपा नेता शंकर सिंह से सांसद उदय सिंह से रिश्ते का सवाल है तो, वह जगजाहिर है. लोजपा के कई नेताओं का आंतरिक समर्थन सांसद को हमेशा रहा है. अध्यक्ष पद पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, लेकिन पिछले दिनों अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिला पार्षद सुनीता देवी के नेतृत्व में जिला पार्षद सरीता देवी, राहत प्रवीण, रिंकी कुमारी, हुमा फातमा, जय प्रकाश पासवान, राकेश सिंह एवं इकबाल के साथ 19 जिला पार्षदों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन जिला पदाधिकारी को दिया गया. 25 जुलाई, 2013 को जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया. इसमें कुल 32 जिला परिषद सदस्यों में से 24 ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया, एक ने विपक्ष में वहीं एक मत निरस्त हुआ. दूसरी तरफ उपाध्यक्ष के खिलाफ 23 मत पड़े, 2 विपक्ष में पड़े, जबकि 1 मत निरस्त हुआ. अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में अध्यक्ष सीमा देवी एवं उपाध्यक्ष राजेश सिंह नदारद रहे. इससे सुनीता देवी उर्फ प्रतिमा कुमारी के अध्यक्ष बनने एवं हुमा फातमा या राहत प्रवीण के उपाध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है. अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सीमा देवी ने कहा कि यह बाहुबल और धनबल की जीत है, जो अधिक दिनों तक चलने वाला है. स्थानीय निकायों की राजनीति को लेकर किशनगंज के भाजपा नेता सह प्रदेश क्रीड़ा मंच के उपाध्यक्ष वरुण सिंह, पूर्णिया भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य संजय कुमार मिर्धा एवं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य ज्योति रानी का मानना है कि निकायों में यह परिवर्तन लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है. आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जदयू का पत्ता साफ हो जाएगा और केंद्र में सत्ता की बागडोर भाजपा के हाथ में होगी. भाजपा के विधान पार्षद दिलीप जायसवाल का कहना है कि स्थानीय निकायों में उलट–फेर लोकल राजनीति से प्रभावित होती है, जहां तक आने वाले लोकसभा चुनाव का सवाल है तो भाजपा का भय सभी दलों में है. इसका विरोध सभी दल कर रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY शर्तें लागू।
Contact : 9386595926, 9334115955

निःसंतान दंपति घबराएं नहीं
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
डॉ. विजय राघवन
सूबे का पूर्णियां जिला चिकित्सक नगरी के रूप में विख्यात है. देश–दुनियां के कई जगहों पर यहां के चिकित्सक अपनी सेवायें दे रहे हैं. ऐसे ही एक चर्चित चिकित्सक हैं डा. विजय राघवन. डा. राघवन ने पूर्णियां जिले के नाका चौक के समीप माता अनुपमा देवी ट्यूब बेबी सेंटर की स्थापना की है. विश्व प्रसिद्ध टेस्ट ट्यूब बेबी चिकित्सक डा. बी. एन चकवर्ती का उन्हें इस कार्य में सहयोग मिल रहा है. बताते चलें कि डा. बी. एन. चक्रवर्ती को विश्व में दूसरा टेस्ट ट्यूब बच्चा देने की वजह से ख्याती मिली थी. डॉ. विजय राघवन वर्षो तक उनके सहयोगी रह चुके हैं. माता अनुपमा देवी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिहार का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है. इसका मुख्य उद्देश्य निःसंतान गरीब लोगों को लाभ पहुंचाना है. डा. राघवन कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पर नेपाल, झारखंड, सिक्किम, असम, बंगाल एवं पूरे बिहार से गरीब निःसंतान मरीज पहुंचते है. विगत एक वर्ष में 1,200 से ज्यादा निःसंतान गरीब दम्पत्ति को टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर लाभ मिल चुका है. यह संस्थान मोल्यूकूलर बॉयलोजी पर रिर्सच भी कर रही है. श्री राघवन ने कहा कि निःसंतान लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। माता अनुपमा देवी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उन्हें हर तरह से मदद देने को तैयार है। ■
ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
NOKSIRA A Division of AriskonPharma
प्रस्तुति: नीरज

पूर्णियां जिले के व्यवसायियों, भाजपा कार्यकर्ताओं मारवाड़ी वर्ग एवं समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं

संजय कुमार मिर्धा
भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य पूर्णियां (कसबा)

मारवाड़ी युवा मंच
गुलाब बाग पूर्णियां
नीरज खेमका
अध्यक्ष

ज्योति रानी
भाजपा जिला उपाध्यक्ष पूर्णियां सह जिला पार्षद धमदाहा, सं.-10

एट्रेक्ट
स्टॉकिस्ट
विश्वनाथ अग्रवाल
गुलाब बाग पूर्णियां

نیو شفا الٹرا ساؤنڈ سنٹر
न्यू शिफा अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर
NEW SHIFA ULTRASOUND CENTRE
काली मंदिर रोड, लाईन बाजार, पूर्णियां
(सदर अस्पताल के सामने, स्टेट बैंक वाली गली में)
Dr. M.N. Kazmi
Director
Dr. S.Vivekanand
M.D. (Radiologist) Assoc. Prof. (Katihar Medical College)

» एक नज़र «

आपदा प्रशिक्षण शिविर

सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित जौहरीमल उच्च विद्यालय में आपदा प्रबंधन व प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया. जूनियर रेडक्रॉस की स्थानीय शाखा द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक मोतिलाल प्रसाद और डीइओ कुमार सहजानंद ने संयुक्त रूप से किया. प्रशिक्षण में करीब 7 सौ छात्र–छात्राओं ने भाग लिया. मौके पर कोषाध्यक्ष अभय प्रसाद, प्रशिक्षक सुमित कुमार, संतोष कुमार, डॉ. जितेंद्र कुमार शाही, प्रधान शिक्षक मोहन सिंह, मो. वसीर अंसारी, प्रखंड भाजपा अध्यक्ष शत्रुध्न प्रसाद सिंह, पार्षद शंभू प्रसाद और अनिल सिंह समेत अन्य थे.

– ब्रजेश

ध्वस्त हुआ स्लुईस गेट

किसानों को बेहतर सिंचाई व्यवस्था मुहैया कराने के लिये सीतामढ़ी जिले के रीगा प्रखंड मुख्यालय के समीप स्लुईस गेट का निर्माण कराया गया था. यह गेट तकरीबन दो दशक से बेकार पड़ा हुआ है. सिंचाई की निर्वाध व्यवस्था के लिए वर्ष 1989–90 में उक्त गेट का निर्माण कराया गया था. लघु सिंचाई विभाग द्वारा कुसमारी व नजरपुर गांव के समीप निर्मित गेट का लाभ शहबाजपुर, पकड़ी, मठवा, रेवासी, अन्हारी व भगवानपुर के अलावा परसौनी प्रखंड के लाखों किसानों को मिला करता था. लेकिन योजना में लूट–खसोट की पोल महज एक साल बाद ही खुल गयी. तकरीबन 25 लाख की लागत से निर्मित उक्त गेट का लाभ फिलहाल किसानों को नहीं मिल रहा है. स्थानीय किसानों ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन से उक्त गेट का पुन: निर्माण कराने की मांग की है.

– नीरज कुमार

बैठक का अनुरोध

सीतामढी जिले के परसौनी प्रखंड में प्रमुख रजनीकांत यादव व उपप्रमुख चंद्र किशोर साहनी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुहिम शुरु हो गया है. बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी अनवार अहमद के पास 10 में से 7 पंचायत समिति सदस्यों ने शपथ पत्र के साथ अविश्वास जताया है. सदस्यों ने कार्यपालक पदाधिकारी से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध किया है. उधर प्रमुख श्री यादव ने अपना इस्तीफा एसडीओ को सौंप दिया है. जगदीश साह के नेतृत्व में आवेदन देने वालों में रेणु देवी, रामजनम पासवान, मंजू देवी, रेणु देवी, काजल कुमारी व उमेश महतो का नाम बताया गया है.

– राम नारायण

MOTHER PRIDE SCHOOL
H-45 Chanakyapuri Colony, GAYA
- Optimum teachers-students ratio
- Visual room for A-V activities
- Comp. awareness from KG-I
- Motivation in place of instruction
- Provide platform for IIT
- Powered by Smart class
Kindle the Desire of Learning
Rising sun in the field of school education
Vinit Kumar
Director
E mail- motherprideschool@rediffmail.com, Contact- 9801204410

सीतामढ़ी जिलेवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई
I Love India
HAPPY INDEPENDENCE DAY

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक
डॉ. अमरनाथ गुप्ता
पूर्व बसपा प्रत्याशी सह पार्षद नगर परिषद, सीतामढ़ी

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक
शिव कुमार अग्रवाल
पूर्व अध्यक्ष, नगर पंचायत डुमरा, सीतामढ़ी

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक
कैलाश कुमार
समाजसेवी, सीतामढ़ी

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक
ज्ञान प्रकाश 'ज्ञानू',
राज्य सहायक सचिव,
बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ, सीतामढ़ी

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त बिहारवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक
सबीह अहमद
प्रदेश लोजपा नेता,
सीतामढ़ी

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक
सुरेन्द्र महतो
भाजपा नेता, सीतामढ़ी

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक
विमल शुक्ला
अध्यक्ष,
जिला कांग्रेस कमिटी, सीतामढ़ी

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक
विजेंद्र कुमार यादव
अध्यक्ष
जिला कांग्रेस अनुशासन समिति सह पैक्स अध्यक्ष पोसुआ पटनिया, रीगा, सीतामढ़ी

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक
अलाउद्दीन बिस्मिल,
जिला पार्षद,सह जिलाध्यक्ष राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ट व सचिव मदरसा रहमानिया, मेहसौल,

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक
हरि नारायण राय
राजद नेता, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी

समस्त बिहारवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
:- पावन अवसर पर संकल्प :-
सरकार प्रायोजित योजनाओं का लाभ हकदारों को दिलाना एवं क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराना है।
गुड्डी देवी
जदयू विधायक, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी
राजेश चौधरी
जदयू नेता, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी

समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं
निवेदक
डॉ कुमकुम सिन्हा
पूर्व अध्यक्ष
लायंस क्लब एक्टीव पुपरी, सीतामढ़ी

बिहारवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
बसपा से जुड़कर गरीब, शोषित व पीड़ितों की समस्या के निदान का मार्ग प्रशस्त करें। बहन कुमारी मायावती के हाथ को मजबूत करें।
निवेदक
डॉ महेश कुमार
बसपा लोकसभा प्रत्याशी, सीतामढ़ी

समस्त मत्स्य पालकों व बिहारवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं
निवेदक
रामसखा चौधरी
आरएन फिश हेचरी,
जलालपुर बैंगरी, पुपरी, सीतामढ़ी

सीतामढ़ी - शिवहर समेत समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं.
भाजपा का अभियान, नरेंद्र मोदी संभाले देश का कमान'
नमो मिशन 2014 की सफलता में सहयोग का ले संकल्प ..
रामाशंकर प्रसाद
निवर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष सह प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, सीतामढ़ी

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त बिहारवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं.
क्षेत्र का सर्वांगीण विकास व सेवा का संकल्प
निवेदक
राज किशोर कुशवाहा,
विधान पार्षद, सीतामढ़ी

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

सीतामढ़ी के किसान सहतूत का पौधा लगाकर रेशम का उत्पादन करते थे. बाद में बाजार की अनुपलब्धता ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया. शुरुआती दौर में वे अपने उत्पाद को मुजफ्फरपुर में लाकर बेचा करते थे, जहां एक केंद्र की स्थापना की गई थी. बाद में किसानों को यह कह कर लौटाया जाने लगा कि राशि उपलब्ध नहीं है.

जमुई

जमुई में नमो का जाप

राजेश कुमार

जमुई जिले में भाजपा कैडरों की उपस्थिती अच्छी मानी जाती है. बावजूद इसके, अब तक गठबंधन धर्म और कई अन्य कारणों से भी भाजपा को जिले में मजबूत आधार बनाने का मौका नहीं मिला था. ऐसा माना जाता है कि जमुई जिले की राजनीति दो कद्दावर नेताओं नरेंद्र सिंह और जयप्रकाश नारायण यादव के इर्द-गिर्द ही घूमती है, लेकिन चकाई विधानसभा से चार बार विधायक रह चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता फाल्गुनी प्रसाद यादव पिछले तीस वर्षों से पहले नरेंद्र सिंह, फिर उनके दोनों पुत्र अभय सिंह और सुमित सिंह को कड़ी टक्कर देते आ रहे हैं. बहरहाल, जमुई लोकसभा क्षेत्र में शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई और तारापुर जैसे छह विधानसभा क्षेत्र हैं. इन सभी सीटों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जदयू का ही कब्जा है.

जिले में जदयू मजबूत है, इसका एहसास भाजपा को है. यही वजह है कि जिला भाजपा, गठबंधन से अलग होने के बाद से ही संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कैंपेन चला रही है. एक बूथ दस यूथ, जैसे श्लोगन के साथ भाजपा के नेता पंचायतों में पार्टी के विस्तार के लिए पहुंच रहे हैं. गठबंधन की वजह से 2000 से 2010 तक के आम चुनाव में भाजपा ने जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र सिकंदरा, जमुई और झांझा

मंगल पांडेय

में अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा था. अब दोनों दल गठबंधन से अलग हैं और लोकसभा चुनाव भी सिर पर है. ऐसे में हर कोई यह देखना चाहता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा की नीति क्या होगी और इसके प्रत्याशी कौन होंगे. भाजपा समर्थकों में जहां नरेंद्र मोदी के नाम पर उत्साह है, वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि प्रत्याशी चयन में खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा.

सूत्र बताते हैं कि अगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष संजय पासवान को या अनुसूचित जाति राज्य आयोग के उपाध्यक्ष जोगेंद्र पासवान को जमुई लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बना सकती है.

भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रकाश कुमार भगत कहते हैं कि गठबंधन के कारण पिछले काफी समय से जिन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा चुनाव नहीं लड़ती थी, उन क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा अपनी मजबूत दावेदारी का एहसास करा रही है. जिले के 10 प्रखंड और 2 नगर मंडल में भाजपा के 32 मंच और मोर्चा कार्यरत हैं. वहीं, भाजपा नेता विकास प्रसाद सिंह नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर यकीन करते हुए जनता के बीच हैं. विकास कहते हैं कि नमो को लेकर ग्रामीण और युवा गोलबंद हो रहे हैं. युवाओं का गोलबंद होना बाकी पार्टियों को चिंतित कर रहा है. फिलहाल, जिले में भाजपा अपनी ताकत को बढ़ाने में लगी है, इसके लिए जिला भाजपा नरेंद्र मोदी का भी सहारा ले रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि जमुई की जनता नमो पर कितना भरोसा जताती है.■

विकास सिंह

फाल्गुनी यादव

feedback@chauthiduniya.com

किला फतह करने की कवायद

प्रमंडल के एकमात्र भाजपा विधायक आलोक रंजन भी नरेंद्र मोदी को करिश्माई बताते हुए कहते हैं कि कांग्रेस ने देश में महंगाई, लूट, भ्रष्टाचार और गरीबी की परिपाटी विकसित कर दी है. देश को कांग्रेस से बचाने का माद्दा अगर किसी में है, तो वह नमो हैं. केंद्र में अगली सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी.

मनोज ठाकुर

सत्तर वर्षों तक साथ रहे जदयू-भाजपा अब एक-दूसरे के विरोधी हैं. इस अलगाव का असर राष्ट्रीय होने के साथ-साथ क्षेत्रीय भी रहा. अलगाव के बाद से कोसी अंचल में भाजपा ज्यादा सक्रिय हो गई है. यह जान लें कि कोसी प्रमंडल के सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिले के कुल 14 विधान सभा और 2 लोकसभा क्षेत्र में से भाजपा के खाते में सिर्फ सहरसा विधानसभा क्षेत्र ही है. एक पर राजद का और बाकी सभी सीटों पर जदयू का कब्जा है. यही वजह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता और नेता ज्यादा सक्रिय हो गए हैं. कार्यकर्ता और नेता नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग और गुजरात में हो रहे विकास की चर्चा क्षेत्र में करते नजर आ रहे हैं. प्रमंडल के एकमात्र भाजपा विधायक आलोक रंजन भी नरेंद्र मोदी को करिश्माई बताते हुए कहते हैं कि कांग्रेस ने देश में महंगाई, लूट, भ्रष्टाचार और गरीबी की परिपाटी विकसित कर दी है. देश को कांग्रेस से बचाने का माद्दा अगर किसी में है, तो वह नमो हैं, केंद्र में अगली सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी.

नरेंद्र मोदी को नायक बना कर भाजपा कोसी अंचल के गांवों में भी सघन प्रचार अभियान चला रही है. उसी का नतीजा है कि अंचल के सुदूर गांव के लोग भी नरेंद्र मोदी को जानने लगे हैं. असर्फी कोसी नदी के पूर्वी-पश्चिमी तटबंध के बीच बसे एक टापूनुमा गांव के रहने वाले हैं. उनके गांव के कई लोग गुजरात में मजदूरी करते हैं. असर्फी कहते हैं की नरेंद्र मोदी गुजरात में बहुत विकास कैलकै, ओते तै सड़कों पर गंदा नै फेंक सकै छियैह, चौवीसों घंटे बिजली रहै छ, कोई भुखल नै सुतैह छै, ओ प्रधानमंत्री बनतै तै

आलोक रंजन

मिहिर झा

देश के खूब विकास होतैय.(नरेंद्र मोदी गुजरात में बहुत विकास किए हैं, वहां सड़क पर कचरा नहीं फेंका जाता है, 24 घंटे बिजली रहती है, कोई भूखा नहीं सोता है, अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो देश का पूरा विकास होगा) सहरसा से भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष मिहिर झा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक कुशल प्रशासक हैं. लगातार तीसरी बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनना इस बात का सबूत है. इतना ही नहीं, गुजरात मॉडल का अनुशरण देश और दुनिया में किया जा रहा है, जो उनके कुशल नेतृत्व का परिचायक है. आगामी लोकसभा में नमो की लोकप्रियता की वजह से हम इस प्रमंडल के दोनों लोकसभा सीटों पर कब्जा करेंगे. नरेंद्र मोदी की कुशल प्रशासक वाली छवि परोस कर अपने पक्ष में गोलबंद करने में कोसी अंचल के नेता लगे हुए हैं. आने वाला वक्त बताएगा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ये कितने सफल हो पाते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी

नकारा बना प्रशिक्षण केंद्र

वाल्मीकि कुमार

बाढ़, सुखा, बेरोजगारी और नक्सलवाद के चौराहे पर खड़े सीतामढ़ी जिले में सरकारी व्यवस्था का लाभ हकदारों को मिलना मुश्किल हो गया है. हुक्मरानों की अनदेखी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का आलम यह है कि यहां कुटीर उद्योग ख़त्म होने के क़गार पर है. कुटीर उद्योग के रूप में विस्तार कर हज़ारों की आर्थिक तंगी में मददगार साबित होने वाली संस्था भी दशकों से बदहाली के दल-दल में फंसी है. इस तथ्य का जीवंत उदाहरण सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में मौजूद है. सरकारी ज़मीन पर सरकार द्वारा पदस्थापित कर्मचारी वेतन तो पा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है. शिवहर-सीतामढ़ी राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-104 के किनारे स्थित मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केंद्र की

स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी. रेशम एवं हस्तकरघा निदेशालय, पटना द्वारा संचालित उक्त केंद्र उद्योग विभाग से संबद्ध बताया जाता है. तक़रीबन 10 एकड़ सरकारी जमीन पर मौजूद केंद्र रेशम उत्पादन के प्रसार में स्थापना काल में बेहतर साबित हुआ. बाद में समय गुजरने के साथ ही इसका भविष्य रसातल में चला गया. बताया जाता है कि स्थापना के बाद तकरीबन 6-7 साल तक केंद्र का लाभ स्थानीय किसानों को मिलता रहा. किसान सहतूत का पौधा लगाकर रेशम का उत्पादन भी करते रहे. बाद में बाजार की अनुपलब्धता ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया. शुरुआती दौर में सीतामढ़ी के किसान अपने उत्पाद को मुजफ्फरपुर में लाकर बेचा करते थे, जहां एक केंद्र की स्थापना की गई थी. बाद में किसानों को यह कह कर लौटाया जाने लगा कि राशि उपलब्ध नहीं है. नतीजतन रेशम उत्पादन से किसानों का मोहभंग होता गया. ऐसा नहीं है कि बाजार में रेशम के खरीदार नहीं हैं, लेकिन बंगाल के मालदह समेत अन्य बड़े शहरों के व्यापारी अब छोटे शहरों में न के बराबर आ रहे हैं. केंद्र पर प्रतिवर्ष रेशम उत्पादन के लिए 10 किसानों को सितंबर से लेकर फरवरी तक विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रशिक्षण में शामिल किसानों को 3 सौ रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों से प्रशिक्षण की राशि भी केंद्र को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. प्रायोजित मनरेगा के तहत केंद्र की जमीन पर शहतूत और अर्जुन का पौधा तो लगाया गया है, लेकिन समुचित कोष के अभाव में केंद्र का विधिवत संचालन नहीं हो पा रहा है. केंद्र के सफल संचालन और किसानों को वाजिब प्रशिक्षण के लिए विभागीय स्तर पर परियोजना पदाधिकारी समेत आधा दर्जन से अधिक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है. बताया जाता है कि इसमें परियोजना पदाधिकारी नागेंद्र प्रसाद वर्मा करीब 7 साल से पदस्थापित हैं, लेकिन वह लगातार पूर्णिया के प्रभार में हैं, जबकि स्टोर कीपर राकेश कुमार, शशिभूषण, कीटपालक सुरेश यादव, राम प्रवेश साह एवं सत्येंद्र कुमार के अलावा आदेश पाल एवं रात्रि प्रहरी छोटे ठाकुर व बुधो देवी केंद्र पर समय गुजार रहे हैं. कर्मियों की मानें, तो किसानों को अगर सही बाजार उपलब्ध कराया जाए, तो रेशम उत्पादन कुटीर उद्योग के रूप में बहुत हद तक लोगों के लिए आर्थिक मददगार साबित हो सकता है. प्रतिवर्ष किसान कम से कम 25 हजार रुपये तक की आमदनी कर सकते हैं. केंद्र पर अब भी रेशम उत्पादन को लेकर कीड़ा तैयार किया जाता है. आवश्यकतानुसार मुजफ्फरपुर, सिवान, बेतिया व सहरसा केंद्र से कीड़ा का आदान-प्रदान भी किया जाता है.

विभागीय लापरवाही और सरकारी उदासीनता का आलम यह है कि 6 ब्लॉकों में केंद्र पर निर्मित खपरैल मकान अब जर्जर स्थिति में है, लेकिन मरम्मत तक नहीं कराया जा रहा है. केंद्र के अधिकांश भवनों में स्थानीय गरीब तबके के लोगों ने अपना डेरा जमाना भी शुरू कर दिया है. कर्मियों की बातों पर भरोसा करें, तो सीडीपी योजना के तहत केंद्र के लिए उपलब्ध कराई गई तकरीबन 9 लाख रुपये वर्ष 2009-10 में पूर्णिया केंद्र को हस्तांतरित कर दिया गया, लेकिन सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी केंद्र के विकास के लिए किसी भी प्रकार की पहल तक नहीं की जा सकी. केंद्र के बदहाली का आलम यह है कि जिला स्तर पर भी कोई पदाधिकारी पलट कर भी जाना मुनासिब नहीं समझते. स्थानीय किसानों का कहना है कि पदस्थापित पदाधिकारियों के नहीं रहने के कारण केंद्र औचित्यहीन बन कर रह गया है. सरकारी एवं प्रशासनिक स्तर पर अगर समय रहते केंद्र के विकास को लेकर समुचित प्रयास नहीं किया गया, तो जिले का एकमात्र रेशम उत्पादन प्रशिक्षण इकाई महज चंद वर्षों में ही अतीत की कहानी बन कर रह जाएगी. केंद्र के प्रति उदासीन रहने वाले जनप्रतिनिधियों को भी आने वाले चुनाव में किसानों के सवालों का जवाब देने में पसीना छूट सकता है, क्योंकि लोगों को जनप्रतिनिधियों की भाषणबाजी अब पच नहीं रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

12 अगस्त–18 अगस्त 2013

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

ईमानदारों को सजा बेईमानों का मजा

ग्रेटर नोएडा में तैनात आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के निलंबन के कारण उत्तर प्रदेश सरकार सवालों के घेरे में है. अब, अपनी सफाई में मुख्यमंत्री चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यह है कि सपा सरकार में गुंडा राज आज भी हावी है और ईमानदारों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं. सत्ता के कई बिन्दु अलग-अलग काम कर रहे हैं. इसी के चलते समाजवादी सरकार को कई मोर्चों पर नाकामी और बदनामी झेलनी पड़ रही है. पार्टी के बड़े नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं. सपा नेताओं और मंत्रियों की कथनी-करनी में जमीन-आसमान का फर्क है. सुशासन देने का वादा करने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौकापरस्त और जातिवादी राजनीति के शिकार हो गए हैं. न तो उन्हें जनता से हमदर्दी है, न ही अदालत के आदेश की चिंता. तुष्टिकरण की राजनीति को सपा ने अपना चेहरा-मोहरा बना लिया है. वह अक्सर सरकारी मशीनरी, खासकर आईएएस/पीसीएस अधिकारियों के नाकारेपन का रोना रोते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह और उनके करीबी मंत्री/नेता ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की जगह मौकापरस्त और छल-प्रपंच के सहारे नाम रोशन करने वाले अधिकारियों को शरण और बढ़ावा देते हैं. जब पार्टी के बाहुबली और बहरुपिये नेता अखिलेश सरकार के पालनहार बन जाएं, तो स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है. सपा भले ही पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन डेढ़ वर्षों में ही उसकी कलई खुल गई. कई मौके ऐसे आए, जब सरकार को अपना चेहरा छिपाना पड़ गया. नया मामला ग्रेटर नोएडा में तैनात आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के निलंबन का है, जिसे लेकर अदालत से जनता तक सरकार की फजीहत हो रही है. सपा के नेताओं को मुंह छिपा कर भागना पड़ रहा है. पार्टी और सरकार दो फाड़ों में बंटी दिखाई दे रही है. दुर्गा को सपा के करीबी खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाना महंगा पड़ गया. यह और बात है कि दुर्गा के समर्थन में सपा के ही कद्दावर नेता राम गोपाल यादव और आजम खां खड़े दिखाई दे रहे हैं. बसपा, भाजपा, कांग्रेस, रालोद सहित सभी दल सपा सरकार को अपने निशाने पर लिए हुए हैं.

कहा जा रहा है कि सपा नेता तथा मंत्री नरेन्द्र भाटी के दबाव में यह कार्रवाई की गई थी, जिनके बेटे और रिश्तेदार इस क्षेत्र में अवैध खनन के काम में लगे थे और दुर्गा उनके काम में न केवल रोड़ा अटका रही थी, बल्कि सख्त कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार कर उनके कई वाहन जब्त भी कर लिए गए थे. क्षेत्र के राजनीतिज्ञ, विशेषकर सत्तारूढ़ दल के नेता इस बात से भड़के हुए थे कि यमुना और हिंडन नदियों से खनन रोकने के लिए इस महिला अधिकारी ने विशेष उड़नदस्ते बना दिए. इतना ही नहीं, कई अवैध खनन के कई मामलों में अप्रैल माह से पुलिस ने 17 मुकदमे दर्ज किए थे. जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 22 मामलों में खनन माफियाओं की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. जून माह में भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग ने ग्रेटर नोएडा के 55 लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पिछले तीन माह में अवैध खनन के मामले में 297 वाहन एवं मशीनें जब्त की गईं और इस काम में लगे लोगों से 82.34 लाख रुपया अर्थदंड वसूला गया था. अफसरों के अनुसार, ऐसे मामलों में पिछले वर्ष दो करोड़ रुपये से अधिक अर्थदंड के रूप में वसूला गया, जबकि राजस्व विभाग का मानना है कि अवैध खनन से बहुत बड़ी क्षति हुई है.

अखिलेश सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा में अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली बहादुर आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को पुरस्कृत करने की जगह उन्हें सस्पेंड किए जाने के बाद तो सपा के विरोधियों को जैसे राज्य सरकार के खिलाफ मजबूत हथियार ही मिल गया. एक धार्मिक स्थल की अवैध दीवार को गिराने से सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ने की आड़ लेकर अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने वाली आईएएस दुर्गा को निलंबित करना सपा सरकार के लिए मुसीबत बन गई है. दुर्गा का निलंबन किए जाने की बात बुद्धिजीवी पचा नहीं पा रहे हैं. वह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सपा के डेढ़ वर्षों के शासन काल में कई बड़े दंगे हुए, इसके गुनहगार अफसरों पर तो किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, फिर दुर्गा के मामले में यह दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है. सपा नेताओं को मीडिया के सवालों का जबाब देते नहीं बन रहा है. आईएएस एसोसियेशन ने भी इस मुद्दे पर अपनी मुट्ठी कस ली है.

बहरहाल, आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के निलंबन की पृष्ठभूमि में भले ही खनन माफिया से टकराव भी एक वजह बताई जा रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारी के निलंबन का यह पहला मामला नहीं हैं. आईएएस अधिकारी और मौजूदा वित्त सचिव हिमांशु कुमार ने इलाहाबाद का कमिश्नर रहते हुए वहां के बालू माफिया पर नकेल कसनी शुरू की, तो उन माफियाओं ने हिमांशु का तबादला करवा दिया. उनके निलंबन पर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी. ऐसा ही मामला पूर्व आईएएस प्रोमिला शंकर का था. प्रोमिला शंकर ने एनसीआर कमिश्नर रहते हुए यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के मास्टर प्लान पर एतराज जताते हुए इसे मंजूरी देने से इंकार कर दिया था. यह मास्टर प्लान, रीजनल प्लान-2021 का उल्लंघन जैसा लग रहा था. प्रोमिला के इस रुख के बाद तत्कालीन बसपा सरकार की नजरें उन पर टेढ़ी हो गई. प्रोमिला के श्रीलंका जाने को बहाना बनाकर निलंबित कर दिया गया. माया का यह खौफ ही था, जो उस समय प्रोमिला शंकर के मामले में आईएएस एसोसिएशन असहाय दिखी थी. प्रदेश सरकार ने जब उनका निलंबन तीन माह बाद बढ़ा दिया, तो केंद्र सरकार ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उनका निलंबन खत्म किया था. रिटायरमेंट से तीन दिन पहले उन्हें बहाल किया गया था.

बस्ती के पुलिस अधीक्षक रह चुके पीपी श्रीवास्तव को चीनी मिल पर फायरिंग का आदेश देना मंहगा पड़ गया. उन्हें सजा के तौर पर निलंबित कर दिया गया. मजिस्ट्रेट जांच हुई. नौ महीने बाद उन्हें आरोप पत्र दिया गया. जांच में निर्दोष पाए गए. बाद में डीआईजी होकर रिटायर्ड हुए. मैनपुरी के एसपी श्रीधर पाठक पर आरोप लगा कि उन्होंने अपराधियों को लाइसेंस दिला दिए. जांच भी नहीं हुई और उन्हें निलंबन की सजा सुना दी गई. दो साल तक श्रीधर को निलंबित रखा गया. जांच हुई और निर्दोष पाए गए. वाराणसी के मौजूदा एसपी अजय मिश्र इटावा में एसएसपी थे. बसपा सरकार को खटक गए. सवा साल तक निलंबित रखे गए. जांच बैठाई गई. उन पर आरोप था कि उन्होंने साथी डीएम का फोन नहीं उठाया था. जांच हुई और निर्दोष पाए गए. सपा के पिछले

शासनकाल में वाराणसी के डिप्टी एसपी शैलेन्द्र सिंह को माफिया मुख्तार अंसारी से अदावत मंहगी पड़ गई थी. यह मामला अपने समय में काफी चर्चित हुआ था. बात फरवरी 2004 की है. प्रदेश में सपा की सरकार थी और मुलायम सिंह सीएम थे. शैलेन्द्र सिंह ने माफिया मुख्तार अंसारी के यहां छापा मारकर एक लाइट मशीनगन, जो सेना से चुराई गई थी, बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी. इस मामले में कुछ लोग पकड़े भी गए थे. मुख्तार को भगोड़ा घोषित कर उन पर शैलेन्द्र सिंह की रिपोर्ट के आधार पर पोटा लगाया गया था. तब मुख्यमंत्री सचिवालय से मुख्तार पर लगा पोटा वापस लेने के लिए प्रशासन पर काफी दबाव डाला गया था, लेकिन दबाव में न आकर शैलेन्द्र ने झुकने की बजाए इस्तीफा ही दे दिया. अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा था कि यह सरकार ईमानदार अफसरों को काम नहीं करने देना चाहती है. सरकार माफिया और दबंगों के दबाव में है. इसलिए मैं पद से इस्तीफा देता हूं. नागपाल के मामले में शैलेन्द्र का कहना है कि वर्तमान सरकार में कोई भी ईमानदार अधिकारी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहा है. नागपाल ने तो काफी पहले ही यह कह दिया था कि खनन माफिया उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मैं अपना फर्ज ईमानदारी से निभाती रहूंगी. ईमानदारी से काम करना ही उनके निलंबन का कारण बना. भाजपा शासनकाल में कुछ ऐसे ही हालात उन्नाव के एसपी रहे राजीव सब्बरवाल को लेकर पैदा हुए थे. प्रदेश सरकार ने उन्नाव के एक भाजपा नेता से कहासुनी के बाद उनके खिलाफ निलंबन आदेश जारी कर दिए. आईपीएस एसोसिएशन भड़क उठी और तत्कालीन डीजी एमसी द्विवेदी के नेतृत्व में वर्ष 1999 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता से मुलाकात की. नतीजतन तुरंत उनके निलंबन खत्म किया गया. बसपा सरकार में तो निलंबन का इतिहास ही रच दिया गया. पुलिस भर्ती घोटाले में एक साथ एडीजी समेत 23 आईपीएस निलंबित किए गए थे. बाद में उन्हें भी जांच के बाद निर्दोष पाया गया. सारे घटनाक्रम का निचोड़ निकाला जाए, तो साफ हो जाता है कि अधिकारियों के निलंबन के पीछे राजनीतिक-प्रशासनिक मतभेद, मनमाने आरोप ज्यादा काम करते हैं. जांच के बाद निष्कर्ष बेमानी साबित होते हैं. किसी ने चुनाव में मनमाफिक काम नहीं किया, तो किसी ने हुक्मउदूली कर उलटे उन्हीं के आदमी को कानून का रास्ता दिखा दिया. नतीजा यह हुआ कि कई-कई महीनों तक अधिकारियों को निलंबन का सामना पड़ा. आरोप पत्र दिए गए, लेकिन जांच के बाद नतीजा सिफर रहा. पिछले करीब दो-ढाई दशकों की बात की जाए, तो

शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

नियम यह है

अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील नियमावली) 1968 के मुताबिक, प्रदेश सरकार को केवल तीन महीने तक निलंबन का अधिकार है. इसके लिए उसे निलंबन से पहले प्रारंभिक जांच करानी चाहिए. जांच में दोषी पाए जाने पर ही तीन महीने के भीतर केंद्र सरकार का अनुमोदन लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है.

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

ईमानदारों को सजा बेईमानों का मजा

.....पृष्ठ 17 का शेष.....

उत्तर प्रदेश की मौजूदा और तमाम पिछली सरकारों की छवि एक क्रूर खलनायक के तौर पर बनती रही है.

बात दुर्गा नागपाल कि की जाए, तो मीडिया, विपक्ष और नौकरशाह, सभी नागपाल के पक्ष में उतर आए हैं. मामला अदालत में पहुंच गया है. दुर्गा के समर्थन में आंदोलन चलाए जा रहे हैं. एक सुर से निलंबन को सारे लोग तानाशाही कार्रवाई करार दे रहे हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश भले ही कुछ भी बोलें, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें सब कुछ पता होगा. नागपाल के मामले में सरकार ने जो फैसला लिया है, वह सुशासन की दिशा में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक ईमानदार अधिकारी को हतोत्साहित करने की कोशिश है, जो अवैध खनन और अतिक्रमण के विरोध में मुस्तैदी से डटी हुई थी. इस फैसले से सरकार का मुखौटा उतर गया है. सरकार का जो असली चेहरा सामने आया है, वह दागदार है. इस फैसले से स्पष्ट होता है कि सरकार खनन माफियाओं और अराजक तत्वों के दबाव में काम कर रही है. भ्रष्टाचार की फसल भी खूब लहलहा रही है. सरकार उन्हें रोकने वाले अधिकारी को दंडित कर यह संकेत दे रही है कि भ्रष्टाचार के खेल में अधिकारी साधक की भूमिका निभाएं, बाधक की नहीं. लोगों को पता है कि दुर्गाशक्ति नागपाल अपने क्षेत्र में जो काम कर रही थीं, वह जनहित और सुशासन के पक्ष में था. इसलिए ज्यों ही निलंबन का आदेश आया, सोशल मीडिया पर सरकार की थू–थू होने लगी. विपक्षी दल चिल्लाने लगे और मीडिया सरकार के विरोध में उतर आया. यहां तक कि आईएएस एसोसिएशन के 12 अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्य सचिव से मिलकर आपत्ति दर्ज की और निलंबन को वापस लिए जाने की गुहार लगाई. गौतमबुद्ध नगर की उपजिलाधिकारी के रूप में नागपाल की पोस्टिंग के मुश्किल से अभी छह माह ही हुए हैं. इस बीच सरकार को बहाना मिल गया कि नागपाल ने सरकारी जमीन को अतिक्रमित कर खड़ी की जा रही मस्जिद के मामले में समस्या खड़ी करने वाला फरमान जारी किया था. सरकार का कहना था कि इससे पवित्र रमजान के महीने में सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ सकता था. दरअसल, सरकार इस मामले की आड़ ले रही है. असल बात यह है कि सरकार ईमानदार और लगनशील अफसरों को बर्दाश्त कर पाने में सक्षम नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बदहाल है शिक्षा व्यवस्था

राज्य सरकार की उदासीनता के कारण बलिया में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है. विद्यालय बंद पड़े हैं. एक तरफ यहां शिक्षक लापरवाह हैं, तो दूसरी तरफ यहां के स्कूल हजारों की संख्या में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं.

शिवनाथ चतुर्वेदी

जिले में शिक्षकों की कमी के कारण दर्जनों विद्यालय बंद पड़े हैं, जबकि 300 से ज़्यादा विद्यालय एकल रूप से चल रहे हैं. उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी के गृह जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग की स्थिति कुछ ज्यादा ही दयनीय है. जिले में 2055 प्राथमिक और 615 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं. उनमें लगभग 6000 शिक्षक/शिक्षिकाएं तैनात हैं, जबकि अभी भी लगभग 3000 से अधिक शिक्षकों की कमी है.

यहां शिक्षकों के अभाव में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है. इसका एक बड़ा कारण शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में लगाने का है. पूरे साल शिक्षक विद्यालय में शिक्षक कार्य छोड़कर आर्थिक गणना, जनगणना, पशु गणना, राशन कार्ड आदि कार्यों में लगे रहते हैं. मिड–डे मील, ड्रेस वितरण आदि की जिम्मेदारी भी शिक्षकों पर ही होती है. पढ़ाई का पूरा समय शिक्षक खाना पकाने व खिलाने में निकाल देते हैं. कई विद्यालय तो ऐसे हैं, जो शिक्षामित्रों के सहारे चल रहे हैं. ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरे. पढ़ाई न होने के कारण उन विद्यालय में बच्चों की संख्या का ग्राफ भी लगातार गिरता जा रहा है. जहां शिक्षकों की कमी के कारण जिले में शिक्षा की हवा निकली हुई है. वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शासनादेश को ठेंगा दिखा दिया है. जिले के खंड शिक्षा अधिकारी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. आदेशों का पालन करने के बदले शिक्षकों को निलंबित करने तक की धमकी दे रहे हैं. ऐसे में शिक्षक खुद ही बीआरसी कार्यालय से स्कूल तक किताबें ढोने को मजबूर हैं, जबकि

शासन ने विभाग को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किताबें पहुंचाने का निर्देश दिया है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी के भी आदेश को ठेंगे पर रख देते हैं. शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को हर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुफ्त पुस्तकें पहुंचाने के निर्देश दिए थे. कुछ विद्यालयों को छोड़कर अधिकतर विद्यालयों में खंड शिक्षाधिकारी शिक्षकों पर स्वयं किताबें ले जाने का दबाव बना रहे हैं. बीआरसी कार्यालय से स्कूल तक किताबें पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की होती है. दुलाई के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को अलग से बजट दिया गया है. इसके बावजूद सभी खंड शिक्षा अधिकारी उस कार्य को अंजाम नहीं दे रहे हैं. शिक्षकों के मुताबिक, उन्हें स्वयं किताबें ले जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और जब शिक्षक शासनादेश का हवाला देते हैं, तो उन्हें निलंबित करने की धमकी दी जाती है.

प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग शासनादेश का पालन नहीं कर रहा है. शिक्षकों को खुद किताबें लानी पड़ रही हैं. उसका खर्च भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है. उन मामलों पर जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

उपेक्षित है बलिया

पूर्वी उत्तर प्रदेश का बलिया जनपद कई मामलो में उपेक्षा का दंश झेल रहा है. जिले की जनता बिजली और पानी के लिए तरस रही है. हालत यह है कि इस जिले के परीक्षार्थियों से लेकर गृहिणियों तक में जन प्रतिनिधियों को लेकर गुस्सा भरा है. जनपद के अंबिका चौधरी, रामगोविन्द चौधरी, नारद कैबिनेट मंत्री है. लोकसभा सांसद नीरज शेखर सहित जनपद में सात में से 6 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं. इसके बावजूद जनपद मुख्यालय पर 15 से लेकर 18 घंटे तक बिजली गुम रहती है. लोकसभा 2009 के चुनाव में सांसद नीरज शेखर ने जनपदवासियों से कहा था कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको नियमित बिजली और पानी देंगे. उन्ही वादों पर नीरज शेखर चुनाव तो जीत गए, लेकिन बिजली की दशा में वे कुछ सुधार नही करवा पाए.

पिछले कई महीनों से शहरवासियों की नारकीय स्थिति हो गई है. बिजली की दुर्दशा पर मुख्यालय निवासी युवा समाज सेवी श्री अजय कुमार कहते हैं कि इससे बेहतर गांव हैं कि वहां कम से कम रात और दिन की बिजली आपूर्ति का समय तय है. सामाजिक कार्यकर्ता डॉ हरेराम वर्मा कहते हैं कि यहां के नेता वोट तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में पलट कर जनता का हाल तक नही पूछते, बस मंच से कोरे आश्वासन देना उन्हें आता है. जनता भी ठहरी भोली–भाली वह नेताओं के कोरे आश्वासनों की ठगी का शिकार हो जाती है.

जब–जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, यह जिला विशिष्ट का दर्जा प्राप्त करता है. उसके बावजूद बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है.

सपा को है युवा शक्ति पर भरोसा

अजय कुमार

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और लोक निर्माण, सिंचाई और सहकारिता मंत्री शिवपाल यादव की गिनती सुर्खियों से दूर रहकर अपना काम करने वाले नेताओं में की जाती है. अपने काम से मतलब रखने वाले शिवपाल सपा के अन्य नेताओं की तरह विवादों से दूर रहते हैं. कार्यकर्ताओं और विधायकों में उनकी अच्छी पकड़ है. उनके दरबार में न्याय मांगने वालों का जमावड़ा लगा रहता है. वह सबको संतुष्ट करने की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं. जमीन से जुड़ा रहना उनके लिए सोने पर सुहागा साबित हो रहा है. कहा यह भी जाता है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसीलिए अब उन्हें सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है. हाल में ही उनको कई और महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपा जाना इस बात के संकेत हैं. चर्चा यह भी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर सपा के नंबर बढ़ते हैं, तो शिवपल यादव के कद में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा. नि:संकोच कहा जा सकता है कि काफी हद तक इस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी अधिक शिवपाल के कामों की चर्चा हो रही है. वह सरकार और संगठन दोनों ही मोर्चों पर दृढ़ता के साथ डटे हुए हैं. राजनीतिक व्यस्तता के बीच वह जनता से भी रूबरू होने का मौका तलाश लेते हैं, ताकि आम लोगों की नब्ज को टटोला और पकड़ा जा सके. इसीलिए सार्वजनिक, निजी और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं आदि में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में वह अक्सर दिख जाते हैं. बच्चों के बीच भी वह खासे लोकप्रिय हैं.

शिवपाल को जब भी मौका मिलता है, वह बच्चों को करीबी बना लेते हैं. समय निकाल कर वह बच्चों से बात करते हैं. उनके रंग में रंग जाना उन्हें खूब भाता है. हाल में ही उनका लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर के प्रतिष्ठित स्कालर्स होम इंटर कालेज में आगमन हुआ. मौका था छात्र–छात्राओं के सम्मान समारोह का. बच्चों को देख कर उनका चेहरा खिल उठा. उन्होंने वहां अधिक समय बिताया. उन्होंने बच्चों को सफलता के मंत्र बताए. उनका कहना था कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रम, अनुशासित जीवन जरूरी है. यह बात स्कॉलर्स होम के छात्र–छात्राओं की सफलता ने साबित भी कर दिया है. समाजवादी सरकार के शिक्षा के प्रति नजरिये को उजागर करते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि युवा शक्ति के सहयोग से ही प्रदेश में समाजवादी सरकार का गठन हुआ है. सपा को युवा शक्ति पर काफी भरोसा है. युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव छात्र शक्ति का सम्मान करते हैं और उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं.

श्री यादव ने कहा कि स्कॉलर्स होम स्कूल छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो दे ही रहा है, यहां उनकी प्रतिभा को निखारने में भी कोई कोर–कसर बाकी नहीं रखी जा रही है. मंत्री जी का कहना था कि विश्व में वही देश विकसित है, जहां पर सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह की अच्छी शिक्षण संस्थाएं सम्पूर्ण विकास की दिशा में प्रयास करती हैं. कॉलेज के छात्र मयंक रजनी, तरुण प्रकाश, पुष्पेन्द्र मिश्रा, आशुतोष त्रिवेदी, पंकज इसके प्रमाण हैं. सत्येश शंकर अवस्थी, आशुतोष विक्रम सिंह, दीर्घा जोशी, समर्थ शुक्ला और नीता कुशवाहा की सफलता यह बात साबित करती हैं. इस मौके पर प्रदेश के मनोरंजन कर राज्यमंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडेय ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि बच्चे कल के भविष्य हैं, उन पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है. समाजवादी सरकार की कोशिश है कि शिक्षा के क्षेत्र में यूपी नए आयाम तय करे. इंटर पास छात्र–छात्राओं को लैपटॉप और दसवीं पास छात्र–छात्राओं को टेबलेट दिए जाने को सही ठहराते हुए पांडेय ने कहा कि विरोधी दलों के नेता लैपटॉप वितरण को सरकारी खजाने का अपव्यय बताते हैं, जबकि हम जानते हैं कि लैपटॉप और टेबलेट से बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होगा.

समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष नावेद सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एसआरएस यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ अशोक बाजपेयी, पूर्व महापौर डॉ दाऊ जी गुप्त, भारती एयरटेल के हेड(लीगल एंड रेगुलेटरी), उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के अमिया पांड्या, यूपी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेन्द्र जायसवाल, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष धनंजय गुप्ता, स्कालर्स होम कॉलेज के फाउंडर चेयरमैन और वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार, विद्यालय के वाइस प्रेसीडेंट सुनील जौली, प्रधानाचार्य श्रीमती सरिता जायसवाल एवं बड़ी संख्या में अभिभावक व छात्र–छात्राएं उपस्थित थे. इस मौके पर मुख्य अतिथि शिवपाल सिंह यादव ने इस मौके पर आइसीएसई और आईएससी बोर्ड परीक्षाओं के प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं और अन्य कक्षाओं के शैक्षिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया. प्रधानाचार्य सरिता जायसवाल ने कॉलेज का रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्कॉलर्स होम के 67 छात्र–छात्राओं ने बारहवीं और दसवीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल को गौरवान्वित किया है. उनमें सत्येश शंकर अवस्थी (97.25), मयंक रजनी (96.5), समर्थ शुक्ला (94.25), आशुतोष विक्रम सिंह (94) और दीर्घा जोशी ने 90 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया. ■

feedback@chauthiduniya.com

पूर्वांचल में फिर शुरू हुआ गैंगवार

सैयद शावेज़ फ़िरोज़

पूर्वांचल में एक बार फिर गैंगवार शुरू हो गया है. माफ़िया डॉन ब्रजेश सिंह के खेमे पर दो माह के अंदर यह दूसरा हमला है. पहले हमले में घायल अजय बच गए थे, लेकिन इसके बाद हाल ही में हुए दूसरे हमले में हमलावरों ने डॉन के चचेरे भाई व सकलडीहा (जनपद–चंदौली) विधायक सुशील सिंह के चाचा सतीश सिंह की हत्या कर दी. हत्या के समय सतीश सिंह वाराणसी के चौबेपुर थानांतर्गत धौरहरा गांव स्थित अपने आवास से पैदल ही टहलने के लिए निकले थे. घर के समीप ही बाइक सवार बदमाशों ने पहले उन्हें रोका और फिर धड़ाधड़ सात गोलियां उनके जिस्म में दाग दीं और असलहा लहराते हुए फरार हो गए. पुलिस को मौके पर नौ एमएम के चार और 7.62 बोर के दो खोखे मिले थे.

सतीश सिंह के पिता रामअवतार सिंह ने चौबेपुर थाने में बीकेडी उर्फ इंद्रदेव सिंह, विनोद भारद्वाज, सतीश सिंह पुत्र मकनू सिंह एवं अज्ञात पर हत्या के साथ ही बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, सुधीर सिंह और अतुल राय पर बेटे की हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसके पूर्व 4 मई को ब्रजेश सिंह के करीबी अजय सिंह उर्फ़ खलनायक पर टकटकपुर में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. 35 राउंड हुई इस फायरिंग के दौरान खलनायक की पत्नी भी इनके साथ थी. इस हमले में खलनायक को चार गोलियां लगी थी, जबकि उनकी पत्नी मीरा सिंह के पैर में एक गोली लगी थी. हालांकि हमले में बुरी तरह से घायल अयज सिंह बच गए थे. इसके बाद से ही मौके की तलाश में लगे हमलावरों ने आख़िरकार सतीश सिंह को निशाना बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया. बताते चलें कि सन् 2001 में उसरी चट्टी गोलीकांड के बाद से ब्रजेश सिंह एंड कम्पनी पर कभी हमला नहीं हुआ था. अचानक शुरू हुए गैंगवार से पूर्वांचल में दहशत का माहौल है. वर्चस्व और बदले की यह जंग अब एक बार फिर शुरू हो गई है. सकलडीहा के विधायक सुशील सिंह ने अपने चाचा की हत्या के बाद यह कहकर पुलिस महकमे को सकते में डाल दिया है कि उनकी जान भी खतरे में है. बक़ौल विधायक उन्होंने कुछ दिन पहले ही राजधानी में प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक पत्र उनके सचिव को सौंपा है, जिसमें उन्होंने यह ज़िक्र किया है कि उनकी जान को खतरा है. उस पत्र में यह भी लिखा गया है कि विधायक को किन लोगों से जान का खतरा है.

सतीश सिंह

ब्रजेश सिंह

डॉन के क़रीबी की हत्या के बाद मीडिया की सुर्ख़ियों में उसे गैंगवार की शुरुआत बताए जाने और पुलिस महकमे की किरकिरी से नाराज़ वाराणसी ज़ोन के डीआईजी जीएल मीणा उसे गैंगवार मानने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि दोनों तरफ़ से गोलियां चलती हैं तो उसे गैंगवार माना जाता है. जिले में एक गैंग द्वारा घटनाएं की गई हैं. इस कारण उसे गैंगवार कहना उचित नहीं है. आईजी के बयान से तो यही लगता है कि पुलिस को दूसरी तरफ़ से भी गोलियां चलने का इंतज़ार है, जिसके बाद ही पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी. ■

सुशील सिंह

जीएल मीणा

feedback@chauthiduniya.com

अखिलेश सरकार में नौकरशाही बेलगाम

दर्शन शर्मा

उत्तर प्रदेश सरकार के डेढ़ साल पूरे हो चुके हैं. अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाना चाहती है. मुख्यमंत्री का दावा है कि वह इस बार प्रदेश में 10 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर के रहेंगे. उनका यह कहना कि लोकसभा चुनाव में उनका मुद्दा विकास ही रहेगा. प्रदेश में निवेश के लिए उद्यमी आने लगे हैं. सरकार उन्हें उनके मुताबिक माहौल बना रही है. वे प्रदेश को विकास के पहले पायदान पर खड़ा करेंगे. उसके लिए सपा सरकार कड़े कदम भी उठा रही है. उन्होंने यूपी के बुनियादी विकास में अवसर व चुनौतियां विषय पर पीएचडी चेंबर के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में तमाम उपलब्धियां गिनाईं कि सपा के डेढ़ साल के शासनकाल में प्रदेश में सकारात्मक औद्योगिक माहौल बना है. वहीं कुछ खामियां भी रहीं, जिसके कारण अफसर हैं. जो फाइलों के निवटारे में रुकावट बनते हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में मदद नहीं करते. वह अधिकारी रहने लायक नहीं है. पैसा है, लेकिन उसे कैसे व किस प्रकार खर्च करना है, उस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है. उनका कहना है कि प्रदेश के विकास के लिए कार्य तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ दुश्मन अधिकारियों की लॉबी है, तो दूसरी ओर कुछ लोग पीआईएल लेकर घूमते रहते हैं और कानूनी तौर पर खिलवाड़ करते रहते है. उन्होंने आगरा के फिल्की, सीआईआई व पीएचडी चेंबर आदि औद्योगिक संगठनों का जिक्र किया कि प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि हर क्षेत्र के उद्यमी प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित हों. कई देशों के राजदूतों का हवाला दिया. बिजली उत्पादन में प्रगति हुई है. 130 मेगावाट वाले सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की योजना है. हमारा गेहूं महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बड़े राज्यों तक पहुंच रहा है. आलू काफी पैदा हुआ. पोल्ट्री जैसी लघु इकाइयां गांवों में विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं. 16 शहरों को जोड़ने के लिए एक साथ काम किया जा रहा है.

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव सिर पर आ चुका है. अटकलें यह लगाई जा रही है कि चुनाव नंवबर–दिसंबर में भी हो सकते हैं. माहौल चुनाव का बन चुका है. संभवत: अब तक सपा प्रमुख मुलायम सिंह सत्तर से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित भी कर चुके हैं. वे लगातार बैठकों के जरिये अपने चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों और उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स लगातार देते रहे हैं. वह कह रहे हैं कि क्षेत्र में जाएं और उनके काम करें. उनसे मिलें. वहीं अखिलेश सरकार में मंत्रियों को भी आगाह कर रहे हैं कि वह प्रदेश के विकास में अफसरों से काम लेने में कोताही न बरतें. उन पर सख्ती बरतें. उनकी चाहत है कि लोकसभा चुनाव में वे 60 सीटें जीतकर अपना परचम संसद में लहराएं. वहीं अखिलेश यादव की मंशा है कि विधानसभा की तरह युवा मतदाता उनकी झोली में फिर से वोट डाल दे. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश का रथ बहुत पहले ही प्रचार के लिए निकल चुका था, जिसके पीछे मुलायम की ही रणनीति थी. रथ के पीछे आपार भीड़ लगती थी. चुनाव में पिता–पुत्र की जोड़ी हिट हुई थी. लोग उन्हें सुनने के लिए बेताब रहते थे, लेकिन इस बार उनके रथ की आहट अभी तक सुनाई नहीं दे रही है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि सपा सरकार मुट्ठी भर युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के जरिये खुश तो कर सकती है, लेकिन भत्ता बांटने मात्र से उनके पेट भरने वाला नहीं है और न ही उनकी रोजी–रोटी की कोई गारंटी है. युवाओं के खाली हाथों को सिर्फ काम चाहिए. लैपटॉप का लॉलीपॉप नहीं. अफसरों पर तोहमत लगाकर सरकार उपहास का पात्र बन रही है. उन डेढ़ वर्ष में सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं लाई है, जिससे युवाओं को भरोसा होता कि सरकार उनके लिए कुछ कर भी रही है. सरकार सिर्फ कागजों पर काम कर रही है.

फिलहाल युवाओं के बल पर चुनाव जीतने वाले अखिलेश सरकार के सामने 70 लाख युवा बेरोजगारों की फौज खड़ी है. सरकारी विभागों में भर्तियां न होने से आधे पद खाली पड़े हुए हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. प्रदेश में अध्यापकों की इतनी कमी है कि किसी–किसी स्कूल में एक भी अध्यापक नहीं है. दूसरी ओर प्रदेश में कानून व्यवस्था लड़खड़ा रहा है. अफसरों के 21 हजार पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें भरा नहीं जा सका है. उनमें सबसे अधिक 8192 पद चिकित्सा विभाग में हैं.

दूसरे नम्बर पर ग्राम विकास विभाग आता है. यहां पर 6932 पद तथा तीसरे नंबर पर सिंचाई विभाग आता है, जहां पर अफसरों के रिक्त पदों की संख्या तकरीबन 2532 है. कर्मचारियों की कमी के कारण अफसरों पर बोझ बढ़ा है, लेकिन सरकार उसकी अनदेखी कर काम के लिए अफसरों पर डंडा बरसाती रहती है. प्रदेश के विभिन्न महकमों के अफसरों को कई बार इधर से उधर किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री अभी भी असंतुष्ट हैं कि वे उनकी सुनते नहीं. बुद्धिजीवियों का कहना है कि अफसरों की समस्या हर मुख्यमंत्री के सामने रही है. सबने उनको काबू में किया. उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं होती थी. पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यकाल में अफसर उनके कहने में थे. कल्याण सिंह का यह कहना कि ब्यूरोक्रेट्स तो एक घोड़े की तरह होता है, उसे काबू करने के लिए सवार की जांघों में ताकत होनी चाहिए. अगर सवार कमजोर हुआ, तो घोड़ा तो अपनी मर्जी से दौड़ेगा ही. मुलायम सिंह और मायावती के सामने अफसरों ने कभी ना–नुकर नहीं दिखाई. वे भी ब्यूरोक्रेट्स रूपी घोड़े की लगाम को तराशना जानते थे. अफसर हुक्मउदूली करना जानते ही नहीं थे. बसपा की चार सरकारों की बात करें, तो जब–जब बहनजी सत्ता में आईं, ब्यूरोक्रेट्स ने उफ तक नहीं किया. उनके फरमानों के आगे अफसर नाचते थे. इतना भय कि कई नेता अकड़ूं बैठते थे और अफसर जूती पहनाने के लिए दौड़ लगाते थे. बसपा सुप्रीमो मायावती हाल ही में ऐसा कह भी चुकी हैं कि जनता को उनकी याद जरूर आएगी, क्योंकि सपा सरकार में मंत्री और अफसर निरंकुश हैं. उन्हें संभाल पाना सपा सरकार के बूते की बात नहीं रह गई है. सरकार जनता की गाढ़ी कमाई लैपटॉप और बेरोजगारी भत्ता बांटने से ज्यादा उनके प्रचार और वितरण कार्यक्रमों पर खर्च कर रही है. सपा सरकार स्थायी रोजगार न देकर युवाओं को बेरोजगार बनाए रखना चाहती है. सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी का कहना है कि सपा सरकार के युवा मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब भी कोई समस्या आती है, तो वे उसका तत्काल समाधान करते है, लेकिन मुख्यमंत्री का यह वक्तव्य हैरानी भरा जरूर है कि अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं. वे याचिका दायर कराने पर ज्यादा ध्यान देते हैं. इससे जाहिर होता है कि अफसरशाही बेलगाम है. सरकार और अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी का एहसास हो रहा है. आखिर ऐसे कौन से हालात हैं, जिसके कारण अफसर सरकार के कामकाज में अड़ंगा लगाते हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि वे पहली बार मुख्यमंत्री बने अखिलेश की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं. यह तो वही बात है कि ब्यूरोक्रेट्स निजाम के मिजाज की नब्ज पहचान लेते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

नवाबों की रियासत रोटी को भी मोहताज

एक दशक पहले द्वारिका शुगर मील की स्थापना इस आशा के साथ की गई थी कि क्षेत्र के किसान और आम जनता का विकास होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है. आए दिन किसानों को अपनी मांगों के लिए धरना–प्रदर्शन करना पड़ता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

कई मशहूर रियासतों, नवाबों एवं राजाओं की शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है अफजलगढ़ विकास खंड क्षेत्र. इस विशाल एवं हरे–भरे भू–भाग में जन प्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा तथा अधिकारियों व कर्मचारियों की लालफीताशाही के चलते आजादी के 60 साल बाद भी नाम मात्र का विकास हुआ है. विकास की आश लगाए

यहां न तो कोई उद्योग है और न उचित शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, पेयजल, बिजली एवं सिंचाई के साधन, आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण यहां की जनता को भारी असुविधाओं से दो-चार होना पड़ रहा है.

यह क्षेत्र आज भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक पिछड़ेपन का शिकार है. यहां न लोगों के पास करने के लिए कोई कामकाज है और न ही रोजी–रोटी का कोई स्थायी जरिया ही उपलब्ध है. इतना ही नहीं, उस विशाल क्षेत्र में आज तक कोई उद्योग जनता के विकास के लिए नहीं लगा है. एक दशक पहले द्वारिका शुगर मील की स्थापना की गई थी, इस आशा के साथ कि क्षेत्र के किसान और आम जनता को विकास की राह मिलेगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है. उदाहरण के तौर पर मील कर्मचारी ज्यादातर क्षेत्र से बाहर के हैं. आए दिन किसान अपनी मांगों को लेकर धरना–प्रदर्शन करते रहते हैं. किसानों का भुगतान समय से नहीं किया जाता और बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं.

इसके अलावा कोई उद्योग या कारखाना अथवा फैक्ट्री भी नहीं लग पाई है. उचित शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, पेयजल, बिजली एवं सिंचाई के साधनों का भी अभाव है, जिसके चलते यहां की जनता को भारी असुविधाओं से दो चार होना पड़ता है. कहने के लिए तो यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास अपनी खेती की जमीन है, जिसके कारण अधिकांश व्यक्ति मजदूरी पर निर्भर है. तीखी धूप व कड़ाके की सर्दी में कठोर परिश्रम कर के जैसे–तैसे अपने परिवारों की ये गुजर–बसर कर पाते हैं. ये क्षेत्र जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है. उत्तराखंड की सीमा मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है. अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है. बिजली व सिंचाई और विकास के लिए भरपूर साधन है, जो कि विडंबना है. हमारा क्षेत्र दूर–दूर तक जंगलों से घिरा हुआ है. यहां विकास की अपार संभावना है. ■

feedback@chauthiduniya.com

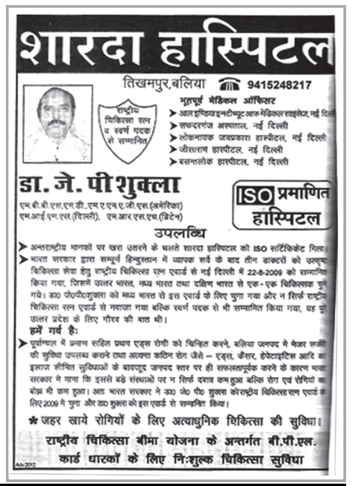

लालू यादव पिछले दिनों मीर्ज़ापुर में थे. विंध्य धाम में उन्होंने बाबा विभूति नारायण उर्फ़ पगला बाबा की घंटों पूजा-अर्चना की. उनकी भक्ति से खुश होकर बाबा उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बनने का वरदान तक दे दिया.

फैजाबाद

आज भी अंग्रेजों का क़ानून : अन्ना

राकेश कुमार यादव

आजादी के 64 साल बाद भी अंग्रेजों का कानून देश में लागू है. इसे बदलने का आह्वान करते हुए समासेवी अन्ना हजारे ने अपनी जनतंत्र यात्रा को लेकर धर्म नगरी अयोध्या और अवध के नवाबों की पहली राजधानी फैजाबाद में पहुंचे और जनतंत्र मोर्चा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित किया. जनसभा से पूर्व अन्ना हजारे ने अयोध्या के बिड़ला धर्मशाला में पहुंचकर श्रीराम जानकी का दर्शन किया और पत्रकारों से मुखातिब हुए. पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अन्ना ने कहा कि देश के राननीतिज्ञ गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं. 5 रुपये और 12 रुपये मे भोजन की बात करना गरीबों का मजाक ही है. यदि देश में महंगाई नहीं है तो फिर सांसद 50 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन क्यों ले रहे हैं? वे 100 रुपये में अपना गुजारा क्यों नहीं कर रहे हैं? इस समाज का पैसा जो टैक्स के रूप मे सरकार की जेब में जा रहा है, उसे जनता का प्रतिनिधि कहे जाने वाले राजनीतिज्ञ मनमाने ढ़ंग से उड़ा रहे हैं. सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता बनाने वाले देश के नेताओं को सबक सिखाकर अच्छे और चरित्रवान लोगों को संसद में भेजना होगा, तभी वास्तविक लोकतंत्र आएगा और जन उपयोगी कानून बनेगा. अंग्रेज चले गए, लेकिन देश को लूटने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून आज भी लागू है, इसे बदलना होगा. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देशवासियों के साथ धोखा कर रहे हैं. लोकतांत्रिक गणराज्य के संविधान में पार्टियों की बात कहां कही गई है? आपराधिक छवि वाले राजनीतिज्ञों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है. जनप्रतिनिधियों पर चल रहे मुकदमों का निस्तारण फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिये जल्द से जल्द होना चाहिए. लैपटॉप वितरण और अन्य माध्यमों से वोट बटोरने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है. प्रलोभन में आकर वोट देना देशद्रोह है. खाद्य सुरक्षा बिल पर लाया गया अध्यादेश चुनावी स्टंट है. इसे संसद के माध्यम से पारित कराया जाना चाहिए. धर्म नगरी अयोध्या में पत्रकारों से वार्ता करने के बाद अन्ना फैजाबाद में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उनका लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया. जनसभा को संबोधित करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि समाज और देश सेवा करके मृत्यु भी आ जाए तो यह मेरा सौभाग्य होगा. जीवन के अंतिम समय तक वह जन लोकपाल और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते रहेंगे. आगामी आंदोलन दिल्ली में सितंबर माह के पहले सप्ताह से आरंभ की जाएगी, जिसमें पूरे देश की जनता को एकत्र किया जएगा. अगर जन लोकपाल विधेयक आ गया तो देश से 60 प्रतिशत भ्रष्टाचार खत्म होगा और गरीबों को न्याय मिलेगा. वर्तमान समय में देश के हालात बहुत खराब हो गए हैं. आम आदमी और देश का किसान खून पसीने से अन्न उत्पादित करता है, लेकिन उसकी कीमत का निर्धारण नेता कर रहे हैं. अन्ना ने कहा कि हर इंसान को जीवन सेवा के लिए मिला है. 77 साल की उम्र हो गई है, लेकिन मेरे अंदर देश सेवा का जज्बा अभी भी है. देश और समाज की सेवा करते हुए 40 साल हो गए. घर नहीं गया, मंदिर में रहता हूं, वहीं खाना खाता हूं. महाराष्ट्र के जिस गांव में रहता हूं, वहां कोई नशा नहीं करता है. ऐसा ही समाज पूरे देश में बनाना है.

अन्ना ने कहा कि 10 साल के संघर्ष के बाद सूचना का अधिकार लागू करा पाया. 12 दिन अनशन किया और महाराष्ट्र सरकार ने 2002 में आरटीआई लागू किया. केंद्र सरकार ने यह कानून 2005 से पूरे देश मे लागू कर दिया, जिससे गरीबों का भला हो रहा है और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लग रही है. जनलोकपाल विधेयक के लिए संघर्ष करते दो साल हो गए, लेकिन सरकार बार-बार धोखाधड़ी कर रही है. संसद में बिल पारित हो गया और कानून अभी तक नहीं आया. इसलिए सोचा कि जनता को पूरे देश में जाकर जगाएंगे और अब जनता को जगाने के लिए निकल पड़े हैं. 26 जनवरी, 1950 में प्रजातंत्र आ गया और सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने इसे सही ढंग से लागू नहीं किया. 1952 मे पहला आम चुनाव हुआ, वह संविधान के खिलाफ था. यह परंपरा आज भी कायम है. अन्ना ने कहा कहा कि छोटे परिवार में दु:ख है, बड़े परिवार में आनंद है. हमारा बड़ा परिवार है, पूरा देश ही हमारा परिवार है. इसलिए आनंद ही आनंद है. निश्काम भाव से देश और समाज में काम करो, उसी से देश और समाज बनेगा.

जनतंत्र यात्रा में अन्ना हजारे के साथ आए चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारतीय ने अपने संबोधन से जनसभा की शुरुआत की. उन्होंने अन्ना की इस यात्रा के ध्येय और उदेश्य की चर्चा की और कहा कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं महंगाई खत्म करना हमारे वश में नहीं है. देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हो रही है. देश का पानी, जंगल, खनिज आदि विदेशियों को बेचा जा रहा है. अगर अब भी हम न चेते तो हमारी दशा अफ्रीकी देशों की तरह हो जाएगी. अन्ना को सिपाहियों की जरूरत है, जो दूसरी आजादी के सेनानी बन सकें और भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर सकें. अन्ना के सेना में अब तक 44 हजार लोग शामिल हो चुके हैं और अभी लोगों के शामिल होने का सिलसिला जारी है.

अन्ना के कारवां में शामिल होने की ललक

पंजाब के जालियांवाला बाग से शुरू हुई जनतंत्र यात्रा के अयोध्या और फैजाबाद में पहुंचने पर समाजसेवी अन्ना हजारे का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, वहीं उनके कारवां में शामिल होने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया. हालांकि अन्ना रामनगरी में रामलला के दर्शन करने नहीं गये, लेकिन अयोध्या के ही बिड़ला धर्मशाला में स्थापित रामजानकी मंदिर में जाकर मत्था टेका और जन लोकपाल विधेयक और जनतंत्र लागू होने की प्रार्थना की. मौके पर पहुंचे पत्रकारों को अन्ना ने अपने आंदोलन और देश के वर्तमान सियासी माहौल की जानकारी दी साथ ही आगामी सितंबर माह में राजधानी दिल्ली में होने वाले जन संसद में किसानों, युवाओं और ग्रामीणों के शामिल होने का आह्वान भी किया. अन्ना की इस यात्रा से लोगों में एक नई चेतना जागृत होती देखी गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

पगला बाबा की शरण में लालू

सैयद शावेज़ फ़िरोज़

चारा घोटाले में फंसे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव अदालत के चक्कर काट-काट कर परेशान हो गए हैं. इसलिए उन्होंने अपनी परेशानियों को हल करने का आसान फ़ार्मूला निकाला है. वह अब तंत्र-मंत्र की साधना करेंगे. जी हां, उन्हें उम्मीद ही नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से उनके बुरे दिन दूर हो जाएंगे और अच्छे दिन जल्द ही उनका स्वागत करेंगे. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जनपद मीर्ज़ापुर में थे. विंध्य धाम में उन्होंने बाबा विभूति नारायण उर्फ़ पगला बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और तक़रीबन तीन घंटे तक पूजा-अर्चना किया.

लालू ने अपने कष्टों के निवारण के लिए पगला बाबा से गुहार लगाई. उन्होंने बाबा के आश्रम में परिक्रमा भी की और वहीं उनके चरणों में घंटों बैठे रहे. बाबा ने भी शिष्य की परेशानी को समझा और उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बनने का वरदान दे डाला. आशीर्वाद मिलते ही लालू गदगद हो उठे. उनके चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी. यही नहीं औघड़ बाबा से पत्नी राबड़ी देवी को भी उन्होंने फोन पर आशीर्वाद दिलाया. पगला बाबा को चमत्कारी बाबा बताते हुए लालू ने कहा कि उन्हें दुश्मन की हर चाल का पता चल जाता है, बाबा ने उनके लिए खास उपाय किए हैं और अब कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. हद तो तब हो गई जब लालू ने बाबा को साक्षात शिव का वरदान ही ठहरा दिया. बाबा भी भक्त की भक्ति पर झूम उठे. लालू को उन्होंने 7 साल की उम्र में दीक्षा दी थी, जिसके बाद से ही वह उनकी शरण में हैं. उन्होंने कहा कि लालू की परेशानी दूर करने के लिए अनुष्ठान किए जाएंगे. पूर्व रेल मंत्री ने पगला बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद मीडिया से मुलाकात की. अष्ठभुजा डाक बंगले में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए लालू ने जहां कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जमकर तारीफ़ की. वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही भाजपा के शीर्ष नेताओं की भी जमकर खिंचाई करते हुए कहा कि राहुल प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, जबकि मोदी में देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है. वह सिर्फ़ दंगा करा सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते. भाजपा का नाम लिए बगैर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि फिरकापरस्त ताकतें यदि सत्ता में आईं तो देश कमज़ोर होगा. कांग्रेस की शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि सभी दलों को मिलकर कांग्रेस का सहयोग करना होगा, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष दलों को साथ लेकर चलती है. बिहार में हुए मिड-डे-मील हादसे पर बोलते हुए लालू ने कहा कि यह हादसा नीतीश सरकार की खामियों को उजागर करता है. उसका ख़ामियाज़ा उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में अवश्य भुगतना पड़ेगा. बटला कांड पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बोले कि व्यक्ति को अधिकार है कि वह न्याय पाने के लिए लोअर कोर्ट के फैसले को अपर कोर्ट में दाखिल कर सकता है.

कभी बिहार पर एकछत्र राज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अब पगला बाबा की शरण में हैं. इसके पूर्व भी वह यहां सपरिवार पूजा-अर्चना के लिए आ चुके हैं. लालू का दावा है कि इस बार बाबा के तंत्र-मंत्र उन्हें परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे. बहरहाल यह तो वक्त ही बताएगा कि प्रधानमंत्री बनने का सपना पालने वाले लालू प्रयाद यादव की आंख आखिर कब खुलती है? ■

feedback@chauthiduniya.com

पगला बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद लालू मीडिया से मुखातिब हुए. प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों की खुब तारीफ़ की. वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही भाजपा के शीर्ष नेताओं की भी जमकर खिंचाई की. उन्होंने कहा कि राहुल प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, जबकि मोदी में देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है. वह सिर्फ़ दंगा करा सकते हैं, कभी देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते.

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120-6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627366